24.3.2015/1100/jt/av/1

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

24.3.2015/1100/jt/av/2

प्रश्न संख्या :1703

अध्यक्ष : श्री अनिरुद्ध सिंह, अपना प्रश्न करेंगे।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1704

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का स्पैसिफिक उत्तर मांगा था मगर माननीय मंत्री महोदया ने इसको जनरेलाइज सा कर दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 7 टाउन लिए हैं ,वे किस क्राटीरिया के तहत लिए गए? दूसरा, फेज़-i में बनी डी.पी.आर. का स्टेटस क्या है? तीसरा, जैसे उत्तर में नालागढ़ के बारे में दिया हुआ है कि 'it will also be taken up in due course of time'. तो इसको क्लेरिफाई किया जाए कि यह फेज़ -vii होगा या क्या होगा?

Irrigation and Public Health Minister : Speaker, Sir, Dharamsala, Mandi, Kullu, Manali, Kangra, Nagrota-Bagwan and Rampur have been got approved under Urban Infrastructure Development Scheme for small and medium towns from the Ministry of Urban Development, Govt. of India. The provisions to supply water 24X7 basis have been made in the estimates of these schemes. I would also like to explain that there are seven days and our systems are not designed to provide water supply. As you all know, how is the situation in the whole State. We have unplanned development in the towns. So, it is very difficult to say that this is going to be done this way. This is what I would like to explain to you and I hope you understand that.

24.3.2015/1100/jt/av/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बता तो दिया कि इस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि क्राइटीरिया क्या है। यह तो माननीय मंत्री जी ने जनरल सा पढ़कर बता दिया कि कौन-कौन से टाउन लिए हैं। कौन से टाउन लिए हैं, यह तो मुझे भी पता है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न तो यह है कि वे टाउन किस क्राइटीरिया के तहत लिए गए हैं? साथ में, डी.पी.आर. का प्रेजेंट स्टेटस भी बताया जाए और नालागढ़ को कब तक लिया जायेगा? उसके बारे में तो बिल्कुल उत्तर नहीं दिया गया है।

Irrigation and Public Health Minister: Speaker, Sir, all the urban water supply schemes ae proposed to be remodelled to supply water on 24X7 basis in phases. However, in seven towns in different parts of the State were taken up for 24X7 water supply in PPP mode on pilot basis in order to rope in investment from the private sector to augment water supply schemes in urban areas of the Pradesh. Himachal Pradesh Infrastructure Development Board invited proposal for providing 24X7 water supply in the selected towns of Baddi, Parwanoo, Nahan, Paonta Sahib, Palampur, Kangra and Nurpur on the PPP mode on pilot basis during December, 2014, but no response was received.

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1105/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1704__ जारी..

अध्यक्षः इन्होंने पूरा रिप्लाई दे दिया है । ...(व्यवधान)..आपको इन्होंने सारी इंफोर्मेशन दी है। What do you want to ask now?

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो टाऊन्ज़ लिए हैं इसका क्राईटेरिया क्या था और किस बेस पर लिए हैं? कौन-कौन से साथ टाऊन लिए हैं, that I know already. इसका क्राईटेरिया क्या था और जो डी.पी.आर. बनानी है उसका प्रेजेन्ट स्टेटस क्या है? नालागढ़ टाऊन कब तक लिया जाएगा, डयु कोर्स ऑफ टाईम क्लैरिफाई किया जाए।

Speaker: Hon'ble Minister, if you have got some specific information please give him.

Irrigation-cum-public Health Minister: Speaker Sir, it is a very simple thing. आपको सारे शहरों का पता है। आप ही के शहरों का नहीं बल्कि सभी शहरों का आपको मालूम है। तभी हमने आपसे कहा कि जो टाऊन्ज़ हैं, they are selected in different parts. कोई ऐसा एक जगह नही है। पहले आप शांति से बात तो सुन लीजिए। हम यही कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में सिलेक्ट किए गए हैं। जो हमारा कंसीडरिंग द पोटेंशियल है वह बहुत मुश्किल है और पी.पी.पी. मोड से इनवैस्टमैन्ट को अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है। मैं इसकी कागज़ात आपको दे दूंगी और आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको तसल्ली हो जाएगा।

Speaker: Hon. Member, you can discuss the matter with the Hon. I&PH Minister.

24.03.2015/1105/negi/jt/2

प्रश्न संख्या- 1705 -सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं पूछा गया।

अध्यक्षः अगला प्रश्न -1706- डॉ0 राजीव सैजल- अनुपस्थित ।

24.03.2015/1105/negi/jt/3

प्रश्न संख्याः 1707.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इसके अनुसार मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के माध्यम से पिछले 2 सालों में जो दो डिवीजन्ज़ हैं- नम्होल और स्वारघाट, उनमें क्रमशः 1,89,24778/- और 1,14,77,761/- रूपये खर्च हुए हैं। इसमें काफी हेड्ज का पैसा पंचायतों के माध्यम से खर्च हुआ है और काफी ठेकेदारों के माध्यम से खर्च हुआ है । एक तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या क्राईटेरिया है, कौन से काम पंचायतों के माध्यम से होने हैं

और कौन से काम ठेकेदारों के माध्यम से होने हैं, यह कौन डिसाइड करता है? क्योंकि यह वर्ल्डबैंक का फंडिड प्रोजेक्ट है, क्या वहीं की गाइड लाईन्ज़ हैं या प्रदेश सरकार ने खुद कोई गाइड लाईन्ज़ बनाई है कि कौन से काम पंचायतों के माध्यम से होने हैं और कौन से काम ठेकेदारों के माध्यम से होने हैं? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो पंचायतों के माध्यम से काम हुए हैं उसमें अगर आप अनैक्स्चर देखेंगे तो बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ पंचायतों में तो लाखों रूपये खर्च हुए और कुछ पंचायतों में एक भी पैसा खर्च नही हुआ है। लगभग 50 प्रतिशत पंचायतें ऐसी हैं जिनके नीचे-जीरो-जीरो लिखा है। और विकास कार्य भी ऐसे हैं कोई यह नहीं कह सकता कि उन पंचायतों में हो नही सकते । अगर कोई पुखर या सिंचाई टैंक बनना है तो वह हर पंचायत में बन सकता है । परन्तु एक पंचायत में लाखों रूपये के बन गए और साथ लगती पंचायत में एक भी पैसा खर्च नही हुआ। अगर मंत्री महोदय कहेंगे तो मैं सभी पंचायतों के नाम भी पढ़ सकता हूं। परन्तु अध्यक्ष महोदय दुःख इस बात का है कि यह बिल्कुल राजनीतिक आधार पर हो रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं उन पंचायतों में खर्च नहीं हुआ है।

अध्यक्षः ऐसा है, रणधीर जी, You don't have to make any references. आप क्वैश्चन कीजिए। How can you say this is politically motivated? You can't say this thing.

24.03.2015/1105/negi/jt/4

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय जब है ऐसा तो ...(व्यवधान).. यह आप देखिए, राजपुरा पंचायत...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

24/1110/03.2015.यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या --- 1707-जारी---

श्री रणधीर शर्मा---जारी---

आप देखिए राजपुरा पंचायत किसी भी हैड में, अध्यक्ष महोदय पोखर पंचायत टैक है, वर्ड्डा छत जल संग्रहण टैंक है, उठाऊ व लधु सिंचाई योजना है, सिंचाई कूल मकोबल संरचना ,पैदल चलने वाला पुल, मिट्टी का बांध, खुरली निर्माण, सामुदायिक भवन, यह सब पंचायतों के माध्यम से है । तो इतने विकास कार्यों में क्या कारण है, चाहे राजपुरा पंचायत है,सोलधा पंचायत है, नम्होल, सिकरोहा पंचायत है, नौणी है, सुई-सुराहड़ है, कोठीपुरा है झणडुता है, बैरी मिया है, गेहड़वी हैं, ऐसी अनेक पंचायतें जिनमें भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित प्रधान हैं । उनमें जीरो, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि इन पंचायतों में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ ।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ,जैसा माननीय सदस्य महोदय ने फरमाया कि कुछ पंचायतों में बिल्कुल पैसा खर्च नहीं हुआ और कुछ पंचायतों में पैसा खर्च हुआ है । पंचायत प्लान बनता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि किस कार्य को पंचायत स्वयं करेगी व किस कार्य को ठेकेदारों के माध्यम से किया जायेगा । ठेकेदार भी रजिस्टर्ड तथा छोटे ठेकेदार होंगे। बड़े ठेकेदार इसमें नहीं आते । जहां तक रणधीर भाई ने बात की है कि ये पंचायतें बी0जे0पी0 से सम्बन्धित हैं इसलिए उनको काम नहीं दिया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है । अगर वे काम करना चाहें तो वे भी कर सकते

24/1110/03.2015.यूके/जेटी/2

हैं, इसमें किसी को मनाही नहीं है । वर्ल्ड-बैंक की डायरैक्शन के मुताबिक इन पंचायतों में काम होते हैं । पंचायतों में कार्य लोगों द्वारा बनाई गई पंचायतें जलागम विकास योजना के अनुसार किए जाते हैं । पंचायत द्वारा हर कार्य में भागीदारी ली जाती है, कुछ ग्राम पंचायतों में प्रश्न की अवधि के दौरान सिविल कार्य नहीं हुए हैं, परन्तु उनमें नॉन सिविल कार्य हुआ है। अगर सिविल में काम नहीं हुए हैं तो बाकी प्लान के तहत वहां कार्य हुए हैं। जो मैने आपको इन्फार्मेशन दी है उसमें से आपने पढ़ कर सारी पंचायतों के बारे में सुनाया है, नम्होल और स्वारघाट की उसमें इसके अतिरिक्त 5.94 करोड़ रुपए कृषि, बागवानी, पशु-पालन आदि गतिविधियों में खर्च हुए हैं, बिलासपुर जिले में।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, मैने जो जानकारी चाही थी, एक तो वह मिली नहीं कि पंचायतों ने कौन से काम करने हैं और ठेकेदारों से किसने काम कराना है ? यह क्या पंचायतें निर्धारित करती हैं? मंत्री महोदय के उत्तर से लगा कि इसको पंचायतें निर्धारित करती हैं । जब कि सच्चाई यह नहीं है । दूसरी बात ,जहां इन्होंने कहा कि पंचायत अपना प्रस्ताव बना कर भेजती है । जिन पंचायतों के मैं नाम ले रहा हूं, उन सभी पंचायतों ने बकायदा जनरल हाऊस करके अपना प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक जितने हैड पंचायतों के माध्यम से सिविल काम होते हैं उन सबकी प्रोपोज़ल डाली है । मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के ऑफिस में भेजी है।

24/1110/03.2015.यूके/जेटी/3

बार-बार प्रधान चक्कर भी लगाते हैं । परन्तु उसके बावजूद भी इन पंचायतों में एक भी पैसा, अध्यक्ष महोदय, 19-21 का फर्क हो तो हम भी नहीं बोलते, सरकार है उनकी, हो सकता है । परन्तु जीरो-हर्डैंड, कहीं आप करोड़ों में पैसा खर्च कर रहे हैं और कहीं एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं । 50 % पंचायतें ऐसी हैं । इसलिए जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं । क्योंकि पंचायत प्रधान ने अपना पूरा प्रोपोज़ल बना कर भेजा है । उसका मेरे पास भी रिकॉर्ड है । दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो इन्होनें कहा कि छोटे ठेकेदारों से करवाते हैं, हम इन ठेकदारों की लिस्ट पढ़ें तो इन ठेकेदारों में ए-क्लास के ठेकेदार हैं, इनके ही उत्तर में । एक-क्लास के ठेकेदारों को भी इन्होंने काम दिया है । इसके अलावा मैने पूछा था कि जो ठेकेदारों को काम दिए हैं, उनके टैंडर कॉल किए? निविदाएं दीं हैं? तो सूचना दी थी । इसमें 74 ठेके दिए गए हैं, जो ठेकेदारों के माध्यम से 74 काम नम्होल सब-डिवीजन में कराए गए हैं इनमें से 73 कामों में 3-3 ही टैंडर आए हैं क्योंकि कम से कम 3 टैंडर चाहिएं होते हैं । तो क्या बात है कि हर काम में 3 ही टैंडर आते हैं?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

24.03.2015/1115/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1707... जारी

श्री रणधीर शर्मा...जारी

क्या यह फिक्सिंग नहीं है कि जिसको काम दिया जाता है वही अन-ऑफिशियली दो और से कोटेशन्ज लेकर तीन के नाम दे देता है? अन्यथा 74 में से 73 कार्यों के केवल 3-3 ही टैंडर क्यों आए हैं? यह बहुत हैरानी की बात है। मंत्री महोदय बताएं कि क्या इन टैंडर्ज़ को अख़बारों के माध्यम से एडवर्टाईज किया था या ऑफिस में ही चुपचाप, जिस ठेकेदार को काम देना था उसको बुलाकर उससे 3 कोटेशन्ज लेकर उसको काम दे दिया गया? अभी जो बातें मैंने पहले कही उनके जवाब भी नहीं आए, वह जवाब भी मंत्री महोदय दें और कैसे 'ए' क्लास के ठेकेदारों को काम दिया गया , उसकी भी जानकारी दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसका स्पैस्फिक जवाब दें।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी ने बताया कि इन कार्यों के 3-3 टैंडर हुए, इसमें टैंडर नहीं होते हैं। वर्ल्ड बैंक की डायरैक्शन है कि 30 लाख रुपये से नीचे के जो काम हैं वह कोटेशन से होंगे। इनकी 3-3 कोटेशन्ज आती हैं, उसके मुताबिक उनको एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख और दस लाख तक के काम दिए जाते हैं। दूसरे ,पंचायत स्वयं निर्णय लेती है कि कार्य किस माध्यम से करवाना है। जहां तक आपने कहा कि हमारी पंचायतें रैज्योल्यूशन देती हैं और वह आते-जाते थक जाते हैं, यह सूचना आपने दी है। अगर आपकी कोई ऐसी पंचायतें छूटी होगी तो वह देखेंगे। उनमें दूसरे काम तो हुए हैं। सिविल काम के अलावा जो दूसरे काम वहां हुए हैं जो कोटेशन पर नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि आपके 5.94 करोड़ रुपये के काम अदर ऐक्टिविटीज में हुए हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे सूचना देंगे तो मैं इसमें जांच करवाऊंगा और जिनको काम नहीं मिला होगा ,उनको काम दिलाएंगे।

24.03.2015/1115/sls-ag-2

Speaker: Next Question. यह तो खत्म ही नहीं होगा। आप एक मिनट बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज भी कुछ सदस्यों ने मेरे पास कंपलेंट की है कि चौथे-पांचवें नंबर पर लगे हमारे प्रश्नों का नंबर ही नहीं आता है क्योंकि सप्लीमैंटरीज इतनी ज्यादा हो रही हैं। इधर भी मैं माननीय मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा

कि आप स्पैस्फिक जवाब दें और जो बात पूछी है उसी का जवाब दें। ताकि प्रश्न का निपटारा शीघ्र हो। लगातार सप्लीमैंटरीज पूछते रहेंगे और एक ही प्रश्न में लगे रहेंगे तो जो औरों के प्रश्न हैं ,वह रह जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि be short and be brief ताकि आपका जवाब सही मिल सके। इधर से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप स्पैस्फिक रहिए and don't beat about the bushes.

श्री रणधीर शर्मा : आपने जो कहा, हम उसका ध्यान रखेंगे। मंत्री भी ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि वह पंचायतें बता दें। पंचायतें तो इन्हीं के उत्तर में हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनके आगे जीरो, जीरो ,जीरो, जीरो लिखा है वही हैं। मैं पार्टीबाजी में भी नहीं जाता। आप इसको बैलैंस करें। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आने वाले समय में जिन पंचायतों में इन दो सालों में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ ,उन पंचायतों में ये विकास के कार्यों के लिए पैसा देंगे ताकि सभी पंचायतों में लगभग बराबर का पैसा खर्च हो? दूसरे इन्होंने कहा कि 'अन्य'। अन्य कोई नहीं है बल्कि वह इनडिविजुअल बैनेफिट्स के काम हैं। कोई बीज बांटते हैं, कोई खाद बांटते हैं। मैंने तो उसकी बात ही नहीं की है। उसमें 5.94 करोड़ रुपये लगा होगा, लेकिन उसमें भी भेदभाव हुआ है। अगर मंत्री जी को विश्वास नहीं है तो मैं उसका भी अलग से प्रश्न लगा लूंगा। परंतु मैंने तो विकास कार्यों की बात की है। इसमें जो पंचायतों में इम्बैलैंस हुआ है ,क्या मंत्री महोदय उस इम्बैलैंस को दूर करने का आश्वासन देंगे? साथ ही, जो ठेकेदारों के माध्यम से ये काम हुए हैं, उसमें यह घोटाला लगता है। कुल 74में से 73 कार्यों में 3-3 ही कोटेशने आना, ये 100% मिलीभगत का काम लगता है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे?

24.03.2015/1115/sls-ag-3

Speaker: Hon'ble Minister, be specific and brief.

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि 3-3 कोटेशन्ज आई हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक की डायरैक्शन के मुताबिक 3-3 कोटेशन्ज लेते हैं। इससे न ज्यादा ले सकते हैं न कम ले सकते हैं। उसके मुताबिक ही ये कार्य होते हैं। ...(व्यवधान)... अगर ज्यादा ली हैं तो उसका पता कर लेंगे।...(व्यवधान)...जहां तक आपने

पंचायतों की बात की है, उसमें कोई अनियमितता हुई होगी तो उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न ..गर्ग जी

24/03/2015/1120/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1707-----क्रमागत

श्री रणधीर शर्मा----क्रमागत

नहीं-नहीं ज्यादा तो ले सकते हैं और कहीं-कहीं सात भी हैं।

वन मंत्री : यदि ज्यादा ली हैं, तो पता कर लेंगे। आप बैठ जाइए। जहां तक इन्होंने पंचायतों की बात की है अगर उसमें कोई अनियमित्ताएं हुई होंगी, तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रश्न समाप्त

2/-

24/03/2015/1120/RG/JT/2

प्रश्न सं. 1708

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न सं. 1708 का उत्तर चाहिए, प्रश्न संख्या 1706 का नहीं। एक तो मैंने माननीय मंत्री महोदया से पूछा था कि विभिन्न मण्डलों द्वारा बाजार से खरीदी गई सामग्री, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। विभागीय उत्तर के अनुबन्ध 'क' के पृष्ठ-4 में 'Pending payments against work done by contractor 'के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 159 11.लाख रुपये, वर्ष 2012-13 में 246.13 लाख रुपये ,वर्ष 2013-14 में 588.97 लाख रुपये और टोटल 994.21 लाख रुपये दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय उत्तर के 'ख' भाग में लिखा गया है कि 'बकाया राशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।' अब वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 वाला बजट भी खत्म हो गया है। तो यह कौन सी पेमेन्ट है? जो बिना बजट के काम हुए हैं यह उनकी पेमेन्ट है? मैं यही माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के विभागीय उत्तर के 'क' भाग में दर्शाया गया है कि 'गत तीन वर्षों 2011-12, 2012-13 व 14-2013में

बाजार से खरीदी गई सामग्री के बकाया भुगतान की राशि का मण्डलवार विवरण अनुबन्ध 'क' पर दर्शाया गया है तथा ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान की बकाया राशि का मण्डलवार विवरण अनुबन्ध 'ख' पर दर्शाया गया है।' इसी प्रकार विभागीय उत्तर के 'ख' भाग के अनुसार 'बकाया राशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।'

अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य और भी डिटेल्ड रिप्लाई चाहेंगे, तो मैं इनको दे दूंगी। उससे ये सन्तुष्ट हो जाएंगे। यदि ये चाहते हैं, तो बताएं।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं मुझे उसका उत्तर चाहिए कि ये पेमेन्ट्स क्यों नहीं हुईं? वर्ष 2011-12 की पेमेन्ट में विभागीय उत्तर में कहा गया है कि जब बजट आएगा तब होगी। तो अब वर्ष 2 ,12-011वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के लिए कौन सा बजट आएगा? मेरा यही प्रश्न है कि जो पेमेन्ट अभी पैन्डिंग है, उत्तर में माननीय मंत्री महोदया कौन से बजट की बात कर रही हैं?

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, during the last three years 2011-12, 2012-13 and 2013-14, total pending payments against purchase of material from the markets are Rs.4701 lakh. The division-wise/year-wise details have been provided in the reply. The pending

24/03/2015/1120/RG/JT/3

payments against purchase of material from the market are likely to be cleared during the current financial year in all divisions except Palampur Division.

The division-wise details of pending payment of works done by the contractors during the last three years i.e. 2011-12, 2012-13 and 2013-14 are given in the reply. The total payments due against work done for the last three years is Rs. 994.21 lakh only. The pending payments are likely to be cleared during the current financial year in Rohru, Jubbal, Rampur, Shahpur, Dehra, Indora and Sidhata, SIMP in Jawali Division. However,

the pending payments for the work done by the contractors in the following divisions will not be cleared as per reasons recorded below. The Divisions are Padhar, Palampur, (Let the hon. Member listen to the whole story) Jawali is being sorted out, Barsar: we are looking into this, Keylong and Reckong Peo as well as Pooh and Kaza. So, you can well imagine. It is a very long information. If you want I can give you the whole information and you can read it and be satisfied. If you are not satisfied, then let me k now.

Contd….ms/jt

24/03/2015/1125/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः1708 क्रमागत-----सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी--------

आपको एक बात बता दूं। आपका एरिया है जिसका आपको पता है। For development in tribal areas, we are providing additional funds to clear the liabilities in tribal areas. -----(व्यवधान) मैं आपके एरिया की बात नहीं कर रही हूं लेकिन आपका एरिया भी ट्राइबल है। आपका मटीरियल कहां से कहां आता है, आप बताइए? (व्यवधान) विधायक महोदय, आप मेरी बात सुनिए। आप एक बात समझिए। आप अपनी ही बात कर रहे हैं और हम सबकी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो सभी का इकट्ठा करना है। एक-एक आदमी का अलग नहीं कर सकते। यह प्रदेशहित की बात है।(व्यवधान) हमने कोई एक आदमी की बात नहीं सुननी है। मैं आपको तसल्ली देती हूं कि आपका काम ठीक हो जाएगा। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है? हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति का काम ठीक हो। आप विधायक हैं, हम इसका मान-सम्मान करते हैं। मैंने बता दिया है कि जो आपको जरूरत है, वह काम हो जाएगा। (व्यवधान) आप तसल्ली रखिए।

Speaker: Next question, Shri Mahender Singh.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ पूछना है।

अध्यक्षः डिटेल में बता तो दिया है। You can discuss the matter with Hon. Minister. आप मंत्री जी के साथ बात कर लीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, प्लीज मुझे भी कुछ पूछना है।

अध्यक्षः रवि जी, कृपया बैठ जाइए। काफी हो गया है। You can discuss the matter with the Hon. Minister. अलग से चर्चा कर लीजिए।

मुख्य मंत्रीः यह प्रश्न जो आई0पी0एच0 ने वैरियस लोगों से और एजैंसीज से सामान खरीदा है उसकी पेमैंट के बारे में है। If this money is due to somebody and is legally due to somebody, certainly, it will be cleared as soon as possible within the next financial year.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक इसमें जो जवाब दिया है,

मुख्य मंत्रीः हो गया है।

24/03/2015/1125/MS/JT/2

श्री रविन्द्र सिंहः नहीं, मुख्य मंत्री महोदय मेरा अनुपूरक प्रश्न कुछ और सा है। इसमें यह बताया है कि पालमपुर डिवीजन में वर्ष 2011-12 की 19,45000-/रूपये-2012 , 13की 1 करोड़ 57 लाख 1 हजार और 14-2013की 1 करोड़ 69 लाख 15 हजार रूपये की पेमैंट है। कुल मिलाकर 3 करोड़ 45 लाख 61 हजार की पेमैंट ड्यु है। माननीय मंत्री जी ने यह बताया भी है कि पालमपुर को छोड़कर अन्य सभी में इसका(व्यवधान) ,यह क्या कारण है कि वहा इतनी(व्यवधान)?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां तक पालमपुर की बात है। कुछ उसमें एलीगेशन्ज हैं कि उसमें खर्चा बेतहाशा हुआ है। Matter is under investigation and after that, if it is found that money is payable, it shall be paid.

प्रश्न समाप्त/

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा------

4.03.2015/1130/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः1709

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें मानसून सत्र 2013 की जो सूचना इन्होंने दी है कि हमने भारत सरकार को 1972.08करोड़ रूपये के नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार को केस भेजा। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन के बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना एक लिखित वक्तव्य वर्ष 2013 के मानसून सत्र के बीच में इस माननीय सदन में दिया है। जो लिखित वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि हमने भारत सरकार को 2892.08 करोड़ रूपये का मैमोरेंडम भेजा है ।पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 1972.08 करोड़ रूपये की फीगर ठीक है या 2892.08 करोड़ रूपये की फीगर ठीक है जिसको आपने हाऊस में ले किया है? माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्त्व्य की कापी मेरे पास है।

दूसरे, माननीय मंत्री जी वर्ष 2013-14 और 2014-15 में बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की जो यहां पर सूचना दी गई है और आपने काफी बड़ी सूचना देने की कोशिश की है। उस सूचना के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2014 में जो हमारा रिलीफ मैनुअल है उसमें भी कुछ संशोधन किया है। जो वर्ष 2014 में आपने संशोधन किया , संशोधन करती बार क्या आपने इस बात को ध्यान में रखा कि हमारे जैसा ही पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर है। वहां पर जो रिलीफ मैनुअल दिया जा रहा है वह कितना है? मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के रीलीफ मैनुअल और हिमाचल के रिलीफ मैनुअल के बीच में कितना अन्तर है? हमारे यहां पर कोई आदमी किसी त्रासदी से मर जाए तो डेढ़ लाख रूपया देते हैं, जबकि उत्तराखंड में 5 लाख रूपये देते हैं। यदि 80 परसेंट हैंडिकेप्ड हो जाए तो हम 62 हजार रूपया देते हैं और उत्तराखंड में 2 लाख रूपया देते हैं। यदि 40 से 6 0परसेंट हेंडिकेप हो जाए तो हम 43,500/-रूपये देते हैं और उत्तराखंड में 1 लाख 50 हजार

4.03.2015/1130/जेके/एजी/2

रूपये देते हैं। अगर कोई मकान क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके लिए हमारे यहां पर 70 हजार रूपये का प्रावधान है जबकि उत्तराखड में 2 लाख रूपये का प्रावधान है। हमारे यहां पर यदि गाय-भैंस आदि मर जाए तो 16,400/-रूपये का प्रावधान है जबकि उत्तराखंड में 20 हजार रूपये का प्रावधान है। यदि खच्चर मर जाए तो हमारे यहां पर 10 हजार रूपये का प्रावधान है जबकि उत्तराखंड में 25हजार रूपये का है। जमीन की जब क्षति होती है उसके लिए हमारे यहां पर 3 हजार रूपये प्रति बीघा है और उत्तराखंड में 10 हजार रूपये प्रति बीघा है। मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2013, जून को जो भारी बारिश हुई वह बारिश उत्तराखंड में भी हुई, किन्नौर में भी हुई और मण्डी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई। आपने वर्ष 2013-14 में जो राशि दर्शाई है कि हमने इतने करोड़ रूपये पूरे प्रदेश के अन्दर बांटी है। मैं उस राशि के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 की राशि 247.22 और 168.95 करोड़ रूपये दर्शाई है । क्या माननीय मंत्री जी इन दानों वित्तीय वर्षों की राशियों का ब्रेक-अप देंगे?

तीसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो राहत मैनुअल है उसमें यह बतलाया गया है कि अगर किसी का मकान चला जाता है उसके पास मकान बनाने के लिए, गऊशाला बनाने के लिए जगह नहीं रहती है तो उसको 2 से 3 बिस्वा जमीन अलॉट की जाएगी। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वर्ष 2013 में वर्ष 2014 में जिनके मकान और गऊशालाएं चली गई उनमें से कितने पात्र व्यक्ति है जिन्होंने विभिन्न जिलाधीशों के पास अपनी-अपनी एप्लीकेशन्ज़ दी हुई हैं लेकिन उनमें से कितनों को 2-3 बिस्वा जमीन मिली है और कितनों को नहीं मिली है?

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

24.03.2015/1135/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1709 क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

चौथा मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो भारी वर्षा के कारण डैबरीज आई है उस डैबरीज को निकालने का प्रावधान आपके रिलीफ

मैनुअल में है। क्या उस डैबरीज को उठाने का प्रावधान उस रिलीफ मैनुअल के मुताबिक करेंगे? जो धर्मपुर में नुकसान हुआ है, जो प्रदेश के दूसरे भागों में नुकसान हुआ है, उसमें से कितनी डैबरीज उठा दी गई है और कितनी डैबरीज उठाने के लिए बाकी है? जो उठाने के लिए डैबरीज शेष है कब तक उसको उठा दिया जायेगा? तीन-चार महीनों के उपरांत मानसून आने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि मानसून आ जाए और वह डैबरीज न उठे। उससे हमारे बहुत परिवारों व गांवों का नुकसान होगा। मैं माननीय मंत्री जी से इसके संदर्भ में जानना चाहूंगा।

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Member has put many supplementaries at a time. He has tried to mention that in the memorandum the total damage of Rs. 2892 crores was indicated in the State. This figure is also correct and the memorandum which we have given to the Government of India that is also correct i.e. Rs. 1900/- crore and something in accordance with the National Disaster Relief Fund. So, both the figures are correct. There is no difference between the two.

So far as he has tried to mention that Uttrakhand is giving more and Himachal is giving less, I would like to say that we have our own manual; Uttrakand has its own manual; and Punjab has its own revenue manual. The Government of India has fixed some criteria/norms, but State Government has given more than that, not less than Government of India. In some cases we are giving more as announced by the Government of India and in some constituencies we are in parallel.

24.03.2015/1135/SS-AG/2

Sir, he has also tried to say that some houses and cowsheds have washed away. The scheme for providing three biswas of land to a landless is different. It is not covered under this scheme. Those persons

who have no land at all for construction of the houses, three biswas of land is given to them in rural area and two biswas of land is given in

urban area. That is a separate scheme. He also tried to explain the memorandum which the Chief Minister has laid on the Table of the House that we have given Rs. 2892 crore. We have asked for Rs. 1972 crore to the Government of India i.e. according to the norms fixed by the Government of India. As per National Disaster Relief Fund, that comes to Rs. 1972/- crore.

Sir, he said that debris is to be removed. So, money makes the mare go. If we have money, we will definitely take steps to remove the debris in exceptional cases, but in every case we cannot. We have requested Government of India. Government of India gives relief keeping in view the area and population of the State. Whereas we have presented to the Government of India two separate memoranda, one in 2013 and the second in 2014, but Government of India has not given us anything this year. In 2012-2013, we received Rs. 45.94 crores from Government of India and from the State Government we have released Rs. 144.17 crores and a total amount of Rs. 190.15 crores was released for the disaster management. In 2013-2014, we received Rs. 95.84 crores from Government of India and State Government has released Rs. 150.38 crores, a total amount of Rs. 247.42 crores. In 2014-2015 Government of India has not given us a single penny till today in spite of the fact that we have given Rs. 832 crores as Disaster Relief Fund from the State. I personally wrote a letter to the Hon'ble Union Home Minister. I received his acknowledgement. Please for God sake, provide us relief at the

24.03.2015/1135/SS-AG/3

earliest, but till today we have not received anything. The State Government is trying to give relief from the State Disaster Relief Fund.

जारी श्रीमती के0एस0

/1140/24.03.2015केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः1709

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि दो बिसवा जमीन शहरी क्षेत्र में ओर तीन बिसवा जमीन ग्रामीण क्षेत्र में दी जाने की आपने अधिसूचना जारी की है। जो आपने अधिसूचना जारी की है जो कि 27 जनवरी, 2014 की है, इस अधिसूचना में आपने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मकान चला जाए और उसके पास मकान बनाने योग्य जमीन न रहे, उसको भी जमीन मिलने का अधिकार है। आपने हाऊस में कहा कि जिसके पास जमीन ही न हो, तो जिसके पास जमीन ही नहीं होगी उसके पास मकान भी नहीं होगा क्योंकि बिना जमीन के मकान कौन व्यक्ति बना सकता है फिर तो वह एन्क्रोचर होगा। इसलिए पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपकी जो अधिसूचना है, आप उसके मुताबिक अपने आप को करैक्ट करें।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि एन.डी.आर.एफ. और एच.डी.आर.एफ. कि हमने जो आपको भेजा, क्या इस हाऊस की इतनी गरिमा गिर गई है कि इस हाऊस में जो आप पढ़ते हैं, जो इस हाऊस में ले करते हैं, उसके अलावा आप भारत सरकार को कुछ और भेजते हैं। आप उसी ज्ञापन को जो भारत सरकार को भेजना था, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 23, 24 और 25 जुलाई, 2013 को केन्द्रीय टीम आई और वैसी ही टीम 27, 2014-11-28को केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में यहां पर जो विभिन्न क्षेत्रों में फल्ड आया है, उसके लिए

/1140/24.03.2015केएस/जेटी/2

भेजी। लेकिन आपने एक तो जैसे मैंने कहा कि आपने इस माननीय सदन में कुछ कहा और वहां कुछ और कहा इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को करैक्ट करें।

तीसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लगभग 520 मकान और गौशालाओं का धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर 13,14,15 अगस्त, 2014 को भारी वर्षा के

कारण, बादल फटने के कारण वहां पर नुकसान हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं, राजस्व मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि इतना नुकसान हुआ है परन्तु उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई। आपने कुछ सड़कों के लिए पैसा दिया, कुछ पैसा आई.पी.एच. को दे दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां खुद गए थे । इन्होंने वहां की दयनीय स्थिति खुद देखी है। उस दयनीय स्थिति को देखते हुए जो वहां पर रैस्टोरेशन वर्क है जो कि जमीनों को रीस्टोर करने का काम है, जो बाकी मकान बचे हुए हैं, उनको रीस्टोर करने का काम है उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया ।

Speaker: Hon. Member, are you making a question or a speech? Make a brief question. You are wasting the time. It is very sad.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में इन्होंने कहा कि हमने 158 करोड़ रुपया रीलीज़ किया मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में

/1140/24.03.2015केएस/जेटी/3

जो नुकसान हुआ है, उस 158 करोड़ रु0 में क्या माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने जो भारी वर्षा के कारण नुक्सान हुआ है और भारी बर्फबारी की वजह से नुक्सान हुआ है, उस सारे का एस्टिमेट बना कर आपने 158 करोड़ रु0 किया हुआ है? अगर 158 करोड़ किया हुआ है तो उसमें से जिला मण्डी के लिए कितना और बाकी जिलों के लिए कितना पैसा दिया गया? जिला मण्डी के लिए जो दिया गया उसमें से कितना पैसा धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लिए गया? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा । इसके अलावा भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में जो नुकसान हुआ उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.3.2015/1145/jt/av/1

प्रश्न संख्या : ----1709जारी

श्री महेन्द्र सिंह जारी---------
नुकसान हुआ, वहां के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां के लिए पैसा दिया जाए वह पैसा वहीं पर लगना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो विधान सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, it should be relevant, to the point and very precise. Hon. Member is giving a speech. So, let me make it very clear to him. हमने भारत सरकार को जो मैमोरैंडम दिया है उसमें भी हमने 2,892 करोड़ रुपये की फिगर बताई है जो कि हमारे नॉर्म्ज के मुताबिक बनती है। जो स्टेट डिजास्टर मैनुअल के मुताबिक बनती है हमने वह फिगर दी है। जो हमने भारत सरकार को कहा कि हम 1972 करोड़ रुपये लेने के हकदार है वह भारत सरकार के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड के नॉर्म्ज के मुताबिक घटकर 1972 करोड़ रुपये हो गई है। So, there is no question of misguiding the House. मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा हम इनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम सदन की गरिमा, precedents, traditions, norms and rules made by this House, we know better and we observe those rules. बाकी आपने जो नोटिफिकेशन के बारे में कहा। वह नोटिफिकेशन राजस्व विभाग ने जारी की है मगर जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने कितने लोगों को तीन-तीन बिस्वा जमीन दे दी। यह इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है। Not relevant at all. लेकिन हमने कहा है और जिलाधीश को लिखा है। जिनके सिर्फ मकान और काउ शैड; दोनों बह गये हैं, he becomes eligible to get 3 biswa of land under this scheme. तो इसमें तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरे, यह स्कीम तो सिर्फ लैण्डलैस के लिए हैं जिसका डिजास्टर से मकान ही खत्म हो जाता है। उसके पास घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। इंदिरा आवास योजना के तहत मकान सैंक्शन होते हैं, राजीव आवास योजना के तहत मकान

24.3.2015/1145/jt/av/2

सैंक्शन होते हैं। गांधी कुटीर योजना के अंतर्गत मकान सैंक्शन होते हैं। In case he has no land at all for construction of the house, in that particular case Deputy Commissioner has been authorized to sanction 3 biswa of land in his favour. पर वह रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। हमने उसका परफोर्मा प्रिसक्राइब किया है और वह देना पड़ता है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं यह केवल धर्मपुर का ही मामला नहीं है बल्कि यह पूरी स्टेट का मामला है। मैं मुख्य मंत्री महोदय के साथ धर्मपुर गया था। वहां लोगों ने कहा कि हमारे विधायक तो आए ही नहीं है। मैंने कहा कि हम जो आ गए हैं। आपके विधायक नहीं आए, हम आ गए हैं। मैं एक बात और बता दूं। उस दौरान आपके क्षेत्र में 23-24 जे.सी.बी. लगाकर सड़कों को बहाल कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार युद्ध स्तर का काम प्रदेश में कहीं और नहीं हुआ होगा। धर्मपुर में सड़कें बहाल कर दी गई है। केवल यह बताना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं उसके लिए माननीय धूमल जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं जैसे इन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मामला उठायेंगे। केंद्र सरकार से भी मामला उठायें। उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार सिर्फ पोपुलेशन और एरिया न देखें अपितु प्राकृतिक आपदा में जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है; यहां भारी बारिश और बर्फबारी से बहुत ज्यादा तबाही होती है। भारी बर्फ के कारण यहां नुकसान बहुत अधिक होता है। लोगों के घर बह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं दिया। जैसे हमीरपुर का एक पार्ट और आपका धर्मपुर का कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ; उसमें अलॉटमैंट ओवर एण्ड एबव दी जाती है। जिलाधीश को अलग पैसा दिया गया। लोक निर्माण विभाग को उसमें अलग पैसा दिया गया। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता क्योंकि पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक है और हम पूरे हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखते हैं। हमने सबसे ज्यादा पैसा 90 करोड़ लोक निर्माण विभाग को दिया है। मेरे पास काफी डिटेल्ड इनफोर्मेशन है, यह इतनी बड़ी फाइल है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने लोगों को दिया गया। हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों को रिलीफ दिया गया उसके बारे में इस फाइल में सारी सूचना है। चाहे मकान का दिया या पशु

24.3.2015/1145/jt/av/3

का नुकसान हुआ। बारिश या बर्फ इत्यादि से हुए पूरे नुकसान के अंतर्गत दिए गए रिलीफ की इसमें सूचना दी गई है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कितना पैसा दिया गया। इन्होंने 1 जनवरी, 2013 से 20 मार्च, 2015 तक प्रश्न पूछा है। इस पीरियड के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फ की वजह से 147 लोगों की मृत्यु हुई और 25331 पशुओं की जान गईं। निजी सम्पत्ति---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1150/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः .1709 जारी..

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ..जारी..
और 25331 पशुओं की जानें बारिश और बर्फ की वजह से गई । नीजि सम्पति को 302 करोड़ 30 लाख रूपये का नुकसान हुआ । सरकारी सम्पति को 3635 करोड़ 43 लाख रूपये का नुकसान हुआ। और 1 अप्रैल, 2013 से 21 मार्च, 2015 तक प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु संबंधित जिलाधीशों व अन्य विभागों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने,राजस्व विभाग ने 452.147 करोड़ रूपये की धनराशि भी जारी कर दी है। कुछ राशि डी.सीज .को दी है ताकि वे मौके पर जा करके आकलन करके मौके पर राहत प्रदान कर सकें। कुछ धनराशि जहां-जहां नुकसान हुआ है पी.डब्ल्यू.डी. को और आई.पी.एच. को दी है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का नुकसान हुआ है, हेल्थ डिपार्टमैन्ट का नुकसान हुआ है और बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है उसके लिए राशि दी है। केन्द्र सरकार से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मिला और केन्द्र की टीम यहां आई थी और अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग करनी है उनके साथ 3-4 मंत्री और होते हैं, हमारा जो मैमोरेंडम गया है उसपर वह विचार करेंगे। उन्होंने मेरी चिट्ठी एक्नॉलेज़ड की है और उन्होंने कहा है कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसपर विचार करेंगे । तो हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मदद करे। इस वक्त एक नया पैसा भी केन्द्र से हिमाचल सरकार को नहीं मिला है, यह मैं इस मान्य सदन को बता देना चाहता हूं।

Speaker: Next Question, Shri Manohar Dhiman. (Interruption) We are not going to deal one Question for one hour. We have to take up all the Questions. (Interruption) Not allowed. Next Question, Shri Maohar Dhiman.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी...(व्यवधान)..

24.03.2015/1150/negi/ag/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन हॉवर है। इस क्वैश्चन हॉवर में आज की सूची में बहुत से क्वैश्चन्ज़ हैं। अगर आपने इसमें इतनी बहस करनी थी तो अलग से चर्चा के लिए नोटिस देते जिसमें चर्चा होती । Question Hour is not meant for discussion. प्रश्न काल तो सूचना प्राप्त करने के लिए और सूचना देने के लिए होता है । ...(व्यवधान)..

श्री रविन्द्र सिंह : मंत्री जी का जवाब ठीक नहीं है और यह गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। _____(व्यवधान)___

(विपक्ष के सभी सदस्य पूर्वाह्न 11.52बजे सदन से वाक-आऊट कर गए)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :एक नया पैसा केन्द्र सरकार ने हमें नहीं दिया है और आप उसमें मदद नही कर रहे हैं।

समाप्त.

24.03.2015/1150/negi/ag/3

प्रश्न संख्याः 1710.

श्री मनोहर धीमानः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसमें ही यह दर्शाया गया है कि अब तक केवल 4 किलोमीटर के लगभग कार्य पूर्ण हुआ है । पिछले 2 वर्षों से इस गति से यह कार्य चला है। इसकी लम्बाई लगभग 34

किलोमीटर है। इसको पूरा करने का लक्ष्य 2017 तक था और इस गति से तो यह 202 7तक भी कम्प्लीट नही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस कार्य के लिए गति प्रदान की जाए। मुझे जहां तक जानकारी है, पैसे की कमी के कारण यह कार्य धीमी गति से चल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि किलोमीटर 22 से ले करके किलोमीटर 34तक, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस दिन इसका नींव पत्थर रखा था उस दिन हमें आश्वासन दिया था। क्योंकि ये मैक्सिमम इफैक्टिड एरिया है ,लोगों के घरों में पानी घुसता है और उपजाऊ ज़मीन बह जाती है तो मैं चाहता हूं कि यहां से इसका कार्य शुरू किया जाए। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे?

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

24/1155/03.2015.यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या - --**1710जारी**---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, इन्होंने तो वह सब जगह देखी है। आपने अपने स्टार्ड क्वैश्चन में जो सप्लीमेंटरी की है, यह channelization of Chhounch Khad in Tehsil Indora, District Kangra was accorded on 05.11.2013 for Rs. 179.59 crore. There is provision of C/o 34 KM embankments and 1740.30 hectares land to protect land from flood. आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और हम बहुत जल्दी से इसको तैयार कर रहे हैं और इसके काम में बड़ी गति ला रहे हैं। लेकिन हमने इसमें बजट को भी देखना है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप चिन्ता बिल्कुल मत कीजिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट the work of C/o embankment on both sides has been completed 3.60 kilometer and 260 hectares land has been protected from the flood. There is provision of reclamation 1740.300 hectares of land out of which 260.00 hectares of land has already been reclaimed. So, you can well imagine everything is being done very well. Thank you.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस लौट आए।)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महादेय, माननीय सदस्य का कहना था कि जो छौंछ खड्ड का चैनेलाईजेशन है ,इसमें पहले रिहायशी एरिया को कवर किया

24/1155/03.2015.यूके/एजी/2

जाए ताकि जो रिहायशी एरिया है उसको डैमेज न हो, आपके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री मनोहर धीमानः सर, धन्यवाद ।

24/1155/03.2015.यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या-1711

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का रिप्लाई देने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहता हूं । जो प्रश्न संख्या 1709 इन्होंने (श्री महेन्द्र सिंह जी)किया था, वह प्रश्न इतना लैन्थी था, उसमें इतने हजारों रूपया इस से सम्बन्धित सूचना की कलैक्शन में लगा, मैमोरेंडम बनाने में लगा, एक-एक आदमी का इतना समय लगा । मैं विधान सभा सेक्रेटेरिएट से भी निवदेन करूंगा कि इतने लम्बे प्रश्न, जिनके लिए हमें बड़ा भारी पैसा खर्च करना पड़ता है । ऐसे प्रश्न न लगाए जाएं । यह मेरी रिकवैस्ट है । दूसरा अध्यक्ष महोदय ,मैने इतना विस्तृत तौर से जवाब दिया है (व्यवधान) एक मिनट, आप (विपक्ष को)बैठों मैं बोल रहा हूं । मैंने विस्तृत तौर पर जवाब दिया है और मैने यह ब्लेम डाला है कि केन्द्र सरकार ने कोई पैसा इस साल हमको नहीं दिया है । पिछली UPA की सरकार को हमको पैसा देती रही है, इनकी केन्द्र की सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया तो हम अपनी FDR से पैसा दे रहे हैं । इसमें 9 प्रश्न तो अकेले श्री महेन्द्र सिंह जी ने पूछ लिए । इसमें कितने प्रश्न होने थे?

24/1155/03.2015.यूके/एजी/4

प्रश्न संख्या-1711

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसके मुताबिक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 15 पटवार सर्कलों में पटवारी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में कुल कितने पटवार सर्कल हैं ? दूसरा प्रश्न मैने इसमें यह किया था कि इनको कब तक फिल-अप किया जायेगा ? उसके बारे में सूचना स्पष्ट नहीं है। जनाब ने लिखा है कि सितम्बर महीने के बाद पद भर दिए जाएंगे। तो सितम्बर तक का तो बड़ा लम्बा-चौड़ा पीरियड है। इसमें स्पेसिफिक डेट कोई नहीं है। तो काईंडली इसके बारे में बताएं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है कि कुल कितने पटवार सर्कल हैं ? तो इनके प्रश्न में, 44 सैंक्शन पटवार सर्कल इनके पास है। जिसमें 29 पोस्टें भरी हुई हैं, 15 पोस्टें खाली हैं। इन 15 पोस्टों में भी मेरे ख्याल में कुछ लोगों की 2015 में रिटायरमैंट हुई है और ट्रांसफर भी हुई हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। पटवारी ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे ही ट्रेनिंग अगस्त में 2015 में कुछ ट्रेनिंग होगी, कुछ सितम्बर में खत्म होगी। जैसे ही ट्रेनिंग के बाद वे ऐग्ज़ाम देंगे, ऐग्ज़ाम के बाद जो क्वालीफाई करेंगें उनको लगा दिया जायेगा। मैं निश्चित तौर पर इस बात को जानता हूं कि पटवारियों का पद जरूरी है, कई सर्टिफिकेट्स उनको देने पड़ते हैं। इसलिए सरकार इस बारे में गंभीर है।

24/1155/03.2015.यूके/एजी/5

अगले दो साल तक जो पटवारियों के पद खाली हैं उनकी ट्रेनिंग भी हम एडवांस में करा रहे हैं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

24.03.2015/1200/sls-jt-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

जय राम ठाकुर जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जो बहुत लंबे प्रश्न होते हैं, जिनमें 400-400, 500-500 कॉपीज बनती हैं ,उनको हमने करटेल किया है और उसमें हमने परमीशन दी है कि 100 या 200 कॉपीज के बजाये केवल 5-6 कॉपीज दी जाएं। वह हमने करटेल किया है। लेकिन आपसे भी मेरा एक निवदेन है कि आप जब प्रश्न करें तो यह देख लें कि आपके ही सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न किए होते हैं। इसलिए अगर आप एक प्रश्न में ही आधा या पौना घण्टा लगा देंगे ,तो बाकी प्रश्न कब पूछे जाएंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप सप्लीमैंटरीज भी ब्रीफ में करें ताकि उनका उत्तर भी प्रीसाइजली मिल जाए। अगर आप स्पीच देना शुरू कर देंगे ,लैक्चर देना शुरू कर देंगे तो वह प्रश्न केवल डिस्क्रिप्शन में ही निकल जाता है। वह मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसका बुरा न मानें क्योंकि यह बड़ी अज़ीब बात है कि आपके ही कुछ मैंबर ऐसे होते हैं जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और वह प्रश्न यहां पर आ ही नहीं पाते। हमेशा 3-4 ही प्रश्न लगते हैं। अगर आप ब्रीफ में अपनी बात रखेंगे तो वह आपके ही हित में है। अगर आपने एक घण्टे में केवल एक ही प्रश्न करना है तो आप रिजौल्व कर लीजिए। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम कागज़ की भी किफ़ायत कर रहे हैं और साथ में आपको भी समय दे रहे हैं। हमने किसी को भी समय देने से मना नहीं किया है। लेकिन मेरी मज़बूरी है कि हर आदमी को ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। अगर 6 लोगों के प्रश्न है और 6 सदस्य अगर 4-4 मिनट बोलें तो वह प्रश्न आधे घण्टे का हो जाता है। मेरा निवेदन है कि उसमें भी आप थोड़ा-सा नियंत्रण रखें और कौपरेट करें जिससे आपके ज्यादा प्रश्न लग सकें। इसमें सरकार की ओर से आपको ज्यादा उत्तर मिल सकते हैं।

जय राम ठाकुर जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

24.03.2015/1200/sls-jt-2

श्री जय राम ठाकुर : सर, इसमें मेरा एक निवेदन है। यह प्रश्न हमारे 5 सदस्यों का था। विधान सभा सचिवालय को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। इसके बावजूद अगर इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से क्लब कर देंगे ,और क्लब किए हुए प्रश्न को पूछने के अधिकार से हमें वंचित करेंगे ,मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा। आज से पहले भी यहां इस माननीय सदन में बीसों बार यह हुआ कि जब प्रश्न क्लब किया जाता है तो एक-एक अवसर उन सभी सदस्यों को दिया जाता है जिनका नाम उस प्रश्न में होता है क्योंकि सभी सदस्यों की मंशा अलग-अलग होती है। जैसे मेरा प्रश्न था जिसे क्लब कर दिया गया। मैंने पर्टिकुलरली इस प्रश्न में पूछा था कि भारी बर्फ़बारी के कारण जो बगीचों को नुकसान हुआ ,बागवानों को नुकसान हुआ, पॉली हाऊसिज को नुकसान हुआ; यह प्रश्न उसकी भरपाई से संबंधित था। वह भी इसमें डाल दिया। आगजनी और बाढ़ का भी इसमें डाल दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर बहुत लंबा हो गया। लंबा होने की वजह से, जब हम इसकी कॉपियां मांगने लगे; ठीक है, पेपरलैस हाऊस है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां हम कंप्यूटर में जितना देख सकते थे ,देखा। लेकिन हमें इसकी कॉपी भी उपलब्ध नहीं हुई क्योंकि उसका बंडल बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा जानकारी है। इसका ख़र्चा भी कम होगा अगर यह प्रश्न केवल दो-तीन हिस्सों में ही होता। इससे यह प्रश्न भी ठीक हो जाता और सभी सदस्यों को इसमें अपनी बात कहने का अवसर भी मिल जाता और मंत्री जी के माध्यम सें इसका उत्तर भी ठीक प्रकार से आता।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बार-बार यह कहने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह आप कह रहे हैं? 14-2013में तो वहां आपकी सरकार थी। 14-2013 में जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त कितना पैसा आया? यह जानकारी भी हम लेना चाहते थे। इसलिए ...(व्यवधान)...

24.03.2015/1200/sls-jt-3

Speaker: This question cannot be revived now because Question Hour is over. This cannot be opened.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं बल्कि मैं व्यवस्था से संबंधित अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमारे जो प्रश्न हैं ,अगर लगता है कि उनका उत्तर लंबा है तो कम-से-कम उनको क्लब न किया जाए ताकि सभी सदस्यों को अपना प्रश्न पूछने का अवसर मिले।

अध्यक्ष : मैं आपकी सूचना के लिए और इस माननीय सदन की सूचना के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही है कि किसी को प्रश्न पूछने से या बोलने से रोकें। लेकिन एक बात तो है कि किसी प्रश्न पर टाईम को मैनेज करना आपका काम है। That is not my job. मैं तो उस प्रश्न के लिए उतना ही समय दूंगा जितना वांछित है। अगर आप यह कहें कि एक प्रश्न पौना घण्टा चलता रहे, then I will not allow it. यह व्यवस्था मैंने करनी है। आप अपना समय डिवाईड कर लीजिए। जब कोई किसी सब्जैक्ट पर बोलता है, जैसे अभी बजट के ऊपर बोलना शुरू करना है ..

जारी ..गर्ग जी

24/03/2015/1205/RG/JT/1

अध्यक्ष महोदय-----क्रमागत

जब आप किसी विषय पर बोलते हैं, जैसे अभी बजट की चर्चा पर आप लोगों ने भाग लेना शुरू करना है ,यदि किसी को 15 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया है, तो he cannot expect कि वह एक घण्टा बोलता रहे ,यह तो आप लोगों ने मैनेज करना है; otherwise I will stop you there. इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रश्न कीजिए और सभी सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिए। यह समय तभी मैनेज हो सकेगा। धन्यवाद।

24/03/2015/1205/RG/JT/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15) के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

1. समिति का **10वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है; और

2. समिति का **11वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **लोक निर्माण विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है ।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।
श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का 35वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं ।

24/03/2015/1205/RG/JT/3

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2014-15) के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति(वर्ष 2014-15) -: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता** विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति का12 वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

4/-

24/03/2015/1205/RG/JT/4

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान-ः

सामान्य चर्चा

अध्यक्ष ः अब वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा आरम्भ होगी। अब मैं माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में बजट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है ,लेकिन लोगों के बीच में बजट की आलोचना करना अब विपक्ष की परम्परा बन गई है। इसका हमें दुःख होता है और सभी को इस बात का अफसोस होता है कि इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं! यह आलोचना तथ्यों और आर्थिक हकीकत पर आधारित नहीं होती। इस बार माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी जिन्दगी का यह 18वां बजट पेश किया है। आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। ये अपने आप में ही एक ऐसी मिसाल है और यह एक ऐसा आदर्श बजट इन्होंने दिया है जिसमें सभी वर्गों के लिए और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्र सरकार की तरह हमारा बजट बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देती हूं कि इन्होंने इस बजट में वे बातें लाई हैं जिसकी गरीब आदमी एवं छोटे आदमी को आवश्यकता है और इन्होंने इन वर्गों के लिए सोचा।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 का यह बजट 28,339 करोड़ का होगा जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 4,726 करोड़ ज्यादा होगा। यह एक बहुत बड़ा इज़ाफा है और अपने में एक रिकॉर्ड भी है। वित्तीय मानकों पर यह बजट देश के श्रेष्ठ बजटों में से एक है। मैं समझती हूं कि हमारा फिसकल डेफिसिट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडैक्ट 2.91% होगा। इसके अलावा यह बजट जी.एस.डी.पी. का 0.04% रैवेन्यु सरप्लस है। यह नहीं है कि प्रदेश का डेट जी.डी.पी. रेशो40 % से कम हो गया है। तो हम समझते हैं कि यह प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें

जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की यह हमेशा कोशिश रही है कि इस प्रदेश को आगे-से-आगे बढ़ाएं।

24/03/2015/1205/RG/JT/5

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वित्तीय मानकों पर देश में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसने ऐसा अच्छा बजट बनाया हो। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तारीफ ही नहीं कर रही हूं बल्कि मैं यह सच्चाई कह रही हूं। इसीलिए मैं समझती हूं कि पिछले बजट के मुकाबले इस बजट से ब्याज अदायगी और कर्ज अदायगी पर केवल 15.71% खर्च होगा। यह पिछले बजट के मुकाबले में 2.50% कम है------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1210/MS/JT/1

श्रीमती विद्या स्टोक्स जारी-----------

यह पिछले बजट के मुकाबले में 2 50.फीसदी कम है जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे वर्ष 16-2015के बजट में विकास पर 40.80 फीसदी धन खर्च होगा। विकास के क्षेत्र में इतना धन उपलब्ध करवाने का मतलब है कि प्रदेश में विकास के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। हमारी सरकार की सोच रही है कि सामाजिक न्याय के साथ संतुलन हो और हमारी सरकार ने ऐसा ही बजट पेश किया है। वर्ष 2 05-004के आधार वर्ष के साथ तैयार आकलन के अनुसार वर्ष 2014-15 में राज्य की आर्थिकी के 6.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की संभावना है। इसीलिए आर्थिक वृद्धि का यह साल हमारे लिए बेसलाइन है। जबकि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 को बेस ईयर माना है। अगर हम केन्द्र सरकार के ही बेस ईयर को माने और आर्थिक दर निकाले तो हम समझते हैं कि दर बढ़कर 8 प्रतिशत हो जाएगी। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी 2014-15 में एक लाख का आंकड़ा पार करके 1 लाख 4 हजार 944 पहुंच गई है। प्रतिव्यक्ति आय में देश में हम दूसरे नम्बर पर हैं। गरीबी उन्मूलन हमारे प्रदेश में खासकर राष्ट्रीय औसत की एक तिहाई है और यह आंकड़ा विकसित देशों के आसपास का ही है। मैं समझती हूं कि

जो बात हमने करनी है वह सच्चाई से करनी है ताकि हरेक आदमी को पता चले कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारी कांग्रेस सरकार का आर्थिक विचार रहा है कि आर्थिक वृद्धि सामाजिक न्याय के साथ संतुलित होनी चाहिए, यही मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस बजट में पेश किया है। हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 550रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 600 रूपये कर दिया है और 80 साल से ऊपर के वृद्धों की पैंशन, जो कोई अन्य पैंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उसको 1100रूपये किया है। इससे लगभग तीन लाख लोगों को फायदा भी मिलेगा। अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, जिसकी आम आदमी बहुत चिन्ता करते हैं। इस मानदेय को 1500 रूपये से बढ़ाकर 1700 रूपये कर दिया है और मजदूरों की दिहाड़ी भी 170रूपये से बढ़ाकर 180 रूपये कर दी है। यह हमारी सरकार की एक शानदार बात रही है कि जहां भी देखा कि लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है, उनको लाभ देने की कोशिश की है। इसी तरह से पांच साल पूरे

24/03/2015/1210/MS/JT/2

करने वाले अनुबंध कर्मियों को भी स्थाई किया जाएगा तथा 8 साल पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बना दिया जाएगा।

इसी तरह से महिलाओं की मैटरनिटी लीव 112 दिनों से बढ़ाकर 135 दिन कर दी है। होमगाड्‌र्ज का मानदेय 260 रूपये से बढ़ाकर 280 रूपये कर दिया गया है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है जिसके लिए हमें गौरव होता है। कर्मचारियों के लिए 7 फीसदी डी0ए0 की किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा किसान और खेतिहर मजदूरों को जीवन बीमा प्रदान कने की दृष्टि से 'मुख्य मंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' आरंभ की गई है। आम आदमी के लिए सबकुछ हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात इस प्रदेश के लिए है और मैं समझती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच बहुत लम्बी और बड़ी है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

4.03.2015/1215/जेके/एजी/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः जारी---------
हमारे मुख्य मंत्री की सोच बहुत बड़ी है इसलिए यातायात की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार 200 करोड़ रूपये की ग्रांट आम आदमी को देगी। इसका मतलब यह है कि आर्थिक वृद्धि इन्क्लुसिव डवैल्पमैंट जो है उसके साथ होनी चाहिए, यह भी किया जाएगा। फूड सबसिडी की बात भी इसमें है कि 210 करोड़ रूपये खर्च करेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने पर 380 करोड़ रूपया सरकार खर्च करेगी। मैं समझती हूं कि कितनी मेहनत हमारी सरकार ने की है खासकर हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच बहुत लम्बी है, इसका हमें बहुत गर्व है क्योंकि ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। अपनी जिंदगी में इन्होंने हमेशा सोचा है कि आम आदमी को लाभ कैसे दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी और सिंचाई क्षेत्र के विकास की हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। उसमें भी हम डवैल्पमैंट कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बजट में 2013 करोड़ रूपये रखे गए हैं जो कि बहुत बड़ा इज़ाफा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इस बढ़े हुए बजट से प्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सुन्दर बना सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें। कृषि में खास करके सिंचाई योग्य क्षेत्र बढ़ेगा, उससे कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी जिससे इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। यह कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, बागवानी के बारे में मैं यहां पर विशेष बात करना चाहती हूं। इसके लिए बजट में 280 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके तहत एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जाएगा और तीन हजार हैक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त बागवानी में उन्नत किस्म की फसलों के तहत लाया जाएगा। ग्रीन हाऊस पर 85 प्रतिशत की सबसिडी दी जाएगी। सेब के लिए खास करके आधारित फसल बीमा योजना को 17 खड्डों से 35 खड्डों तक किया जाएगा। आप

4.03.2015/1215/जेके/एजी/2

समझ सकते हैं कि यह काम काफी मुश्किल से होगा फिर भी आम का क्षेत्रफल 10 ब्लॉकों से बढ़ा कर अब 42 ब्लॉकों तक किया जाएगा। इनको बढ़ाया जाएगा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बागवानी में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1 हजार करोड़ रूपये का नया प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। यह माननीय मंत्री जी की सोच है। मैं जानती हूं कि कृषि ग्रामीण विकास पंचायती राज के क्षेत्र में बजट में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों के किसानों की क्रय शक्ति में इज़ाफा होगा और हिमाचल के 90 फीसदी लोगों के लिए खुशहाली का एक आर्थिक माहौल बनेगा। ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि उनको कितना लाभ मिले और उनकी खुशहाली हो, यही हमारी सोच रहती है।

सड़क निर्माण के बजट में 2,732/- करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इससे नई सड़कों के निर्माण और रख-रखाव में भी इज़ाफा हुआ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी रात-दिन चिन्ता करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5,777/-करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार पर ज़ोर दिया जाएगा। स्क्लि डवैल्पमैंट वैकेशनल कोर्सिज रोजगार के बढ़ा दिये जाएं। यह बहुत अच्छा रहेगा और लगातार इस काम को करने की आवश्यकता है। लोगों को खाली चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको एक सोच भी रखनी चाहिए कि हम किसलिये यहां आए हैं और किसलिए यहां पर खड़ें हैं। यह हमारी सरकार की सोच है और जनता की भी वही सोच होनी चाहिए। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, परिवहन के क्षेत्र में 800 नई बसें खरीदी जाएगी जिससे कि पूरे प्रदेश में यातायात की सुविधा बहुत मज़बूत बनेगी। हमारी सरकार ने पहले से ही लोगों की सेवा की है और पहले से ही 500 बसें चला भी दी हैं। केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा भी दी जा रही है। वह हमेशा से हम देते रहे

4.03.2015/1215/जेके/एजी/3

हैं और सरकारी स्कूलों में यह सुविधा पहले ही दी गई है। आज हमारे मंत्री जी यहां पर नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

24.03.2015/1220/SS-JT/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः
मैं जानती हूं कि बेरोजगार युवकों के लिए स्किल डिवैल्पमैंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उसके अलाऊसिज़ के लिए जो हम 100 करोड़ रुपये की बात करते थे उसका प्रावधान किया गया है। स्किल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन की स्थापना भी की जायेगी। हम चाहते हैं कि इसको जल्द-से-जल्द लागू करना चाहिए ताकि युवकों में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में हमारा प्रदेश सोशल सैक्टर स्पैंडिंग में प्रति व्यक्ति के लिए पहले स्थान पर है। मैं जानती हूं कि इससे यह साबित होता है कि हमारा विकास सामाजिक, हर दर पर इंक्लूसिव है। यह बात हाल में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है और रिपोर्ट में भी कही गई है। मैं समझती हूं कि हम प्रदेश में हर चीज़ में बड़ी समझदारी से मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। सारा काम ठीक-ठाक चल रहा है। उसमें हमारी शान और मान है। मैं जानती हूं कि केन्द्र सरकार के अधिकतर विभागों के आकलन के मुताबिक हमारा प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में पहले और दूसरे नम्बर पर है। आप कहीं भी जायेंगे तो इस बात को सुनेंगे तो वह गलत बात नहीं है। वह सच्ची बात है। सही बात है। केन्द्र की मोदी सरकार जो है वह हमारे माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी के विकास के आदर्श मॉडल की तारीफ करती है। लेकिन विपक्षी भाजपा विकास और बजट पर राजनीति करती है। यह गलत बात है। हर वक्त इसी चीज़ पर फंसे रहें कि इसके साथ कैसे झगड़ा करना, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति, प्यार और सद्भावना से काम हो। विपक्षी राजनीति को जिन्दा रखने के लिए यह उनकी मजबूरी है। मैं यह समझती हूं कि आज हमारे सामने विपक्ष के चिन्तनशील नेता इस बजट की गुणवत्ता को समझ रहे हैं और अंदर-ही-अंदर तारीफ भी करते हैं। शायद पीठ के पीछे नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लगता है। कई जगह ऐसी बातें मेरे सुनने में आईं। अध्यक्ष

महोदय, मैं जानती हूं कि लोकतंत्र में बजट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है। लेकिन बजट की आलोचना करना अब विपक्ष की परम्परा बन गई है। यह आलोचना तथ्य और आर्थिक हकीकत पर नहीं होती। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपनी जिन्दगी का 18वां बजट पेश किया तो आप सोच लीजिए कि क्या यह बड़ी मिशाल नहीं है? क्या यह छोटी मिशाल है? बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उद्योग घराने बनाये गए हैं। इसके लिए मैं माननीय

24.03.2015/1220/SS-JT/2

मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि इस साल 2015-16 का बजट बहुत अच्छा रहे और हर तरह से हम बहुत खुशी से मान-सम्मान से जाएं, यही मुझे आप सबको दास्तां देनी है। आप सब को धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी क्षमता से अपनी बात कर सकी हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

24.03.2015/1220/SS-JT/3

अध्यक्षः अब श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने अपना 18वां बजट प्रस्तुत किया।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

ये सुनकर कि यह इनका 18वां बजट है हमें भी व प्रदेशवासियों को भी बहुत आशाएं और उम्मीदें थीं कि इस बजट से प्रदेश को एक दिशा मिलेगी। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति को एक विजन इस बजट से मिलेगा, ऐसी उम्मीद थी। क्योंकि केन्द्र सरकार से भी 14वें वित्तायोग में पैसा मिला था और माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुभव के आधार पर भी ऐसा लगता था। परन्तु जो बजट 18 मार्च को प्रस्तुत हुआ उससे निश्चित रूप से निराशा हमारे मन में भी आई और प्रदेशवासियों के मन में भी आई। इस बजट में कोई विजन, कोई

दिशा नज़र नहीं आती। इस बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो इस दृष्टि से कोई प्रयास नहीं देखे जा रहे। कुल मिलाकर यह दिशाहीन बजट है। ऐसा मैं मानता हूं। मुख्य मंत्री जी ने 3 घंटे खड़े होकर इस बजट को पढ़ा। बजट से तो शायद कुछ नहीं मिला पर एक बात इन्होंने ज़रूर सिद्ध कर दी। जो इनकी पार्टी के लोग कहते थे कि मुख्य मंत्री जी बूढ़े हो गए। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं तो अभी जवान हूं..

जारी श्रीमती के0एस0

/1225/24.03.2015केएस/जेटी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

कि मैं तो अभी जवान हूं। उनका मुंह इन्होंने जरूर बन्द कर दिया परन्तु मुझे और इस बजट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी हमारी वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स जी ने इस बजट पर बोला। बहुत अनुभवी नेता है। मेरी तो माताजी की उम्र से भी ज्यादा उम्र की हैं इसलिए मैं इनके बोलने पर क्या बोल सकता हूं परन्तु जो मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े पढ़े थे, उन्हीं आंकड़ों को इन्होंने पढ़ दिया। कोई नई बात, कोई नई क्लैरीफिकेशन या कोई लॉजिक इन्होंने नहीं दिया। जो हमारे साथियों ने आलोचना की, कमियां बताई, उनको दूर करने के लिए उस आलोचना को गलत करने के लिए कोई तथ्य हमारी मंत्री महोदया नहीं दे सकीं। इसलिए मैं इनके भाषण पर बोलना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह मौका था कि केन्द्र सरकार ने 14वें वित्तायोग में 234 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि करके हिमाचल प्रदेश को भरपूर आर्थिक सहयोग दिया था।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य, यह आपकी गलत-फहमी है।

श्री रणधीर शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है। मेरी कोई गलत-फहमी नहीं है। यही नहीं बजट में इन्होंने कहा कि केन्द्रीय करों और केन्द्रीय अनुदान में 66.65 प्रतिशत केन्द्र से मिल रहा है। इतना पैसा आज तक नहीं मिला। केन्द्र में इनकी यू.पी.ए. की सरकार रही। इनके पिछले साल के बजट में यू.पी.ए. की केन्द्र सरकार से केन्द्रीय कर और केन्द्रीय अनुदान के रूप में मात्र 59.28 प्रतिशत

मिला था। हमारी सरकार ने इसमें 7 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की है । आपने धन्यवाद नहीं करना है तो न करो, आपके राजनीतिक कारण हो सकते हैं परन्तु आप

/1225/24.03.2015केएस/जेटी/2

उस पैसे का सदुपयोग तो करो। आप अपने प्रदेश के आय के साधन खड़े करके अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारो। अपने प्रदेश का काँट्रीब्यूशन का पार्ट दे कर उस पैसे को विकास के काम में तो लगाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, दुख का विषय है कि इतनी वृद्धि के बावजूद भी जो हमारा कैपिटल एक्सपैंडिचर है वह मात्र 4851 करोड़ है। हमारी सरकार थी तो 2012-13 में हालांकि 13वें वित्तायोग ने कितने कट लगाए थे, कितनी कटौती की थी उस समय भी हमारा कैपिटल एक्सपैंडिचर 4275 करोड़ के लगभग था और उसमें हमने 800 करोड़ की वृद्धि कर दी थी। इनको इतना कुछ मिल गया उसके बाद भी एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि इस बजट में इन्होंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम किया है । 3285 करोड़ तो वित्तीय घाटा चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एनुअल प्लान की चर्चा करते हैं, 4800 करोड़ रु0 की। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना है । 22 800,करोड़ रु0 की योजना है । मुझे तो लगता है जो हालात चल रहे हैं उसमें ये पिछली बार की तरह पैसा सरैण्डर करेंगें।12 वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा पहला साल था वर्ष 2012-13 का 3700 करोड़ की वार्षिक योजना थी। 2013-14 में इनकी 4100 करोड़ की योजना थी। 2014-15 में इनकी 4400 करोड़ की योजना होगी जो कि ज्यादा हो सकती थी । इस साल भी 2015-16 में 4800 करोड़ ही रह गए। अभी आपका कितना बचा है, 22,800 करोड़। क्या अगले साल आप इतनी वृद्धि कर पाएंगें 5500 करोड़ तक पहुंचा पाएंगें? अगर नहीं

/1225/24.03.2015केएस/जेटी/3

पहुंचा पाए तो आप सरेण्डर करेंगें और सरैंडर करने का नुकसान प्रदेश को होता है जो कि आपने पहले भी किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी जो 10 300,करोड़ की योजना थी उसमें भी इन्होंने उसके मुकाबले 8494 करोड़ खर्चा था। 1806 करोड़ रु0 उस समय भी सरैंडर किया था जिसके कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। मात्र 3478 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना 5700 करोड़ के मुकाबले आदरणीय धूमल जी ने 7899 करोड़ रु0 खर्च करके---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.3.2015/1230/ag/av/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---------

आदरणीय धूमल जी ने 5700करोड़ रुपये के बदले 7899 करोड़ रुपये खर्च करके 2199 करोड़ रुपये ज्यादा खर्चे थे और उसके कारण दसवीं पंचवर्षीय योजना में 4600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। परंतु आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में कम खर्च किया इसलिए कम वृद्धि हुई। हालात अब फिर वहीं पहुंच गये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आपका इतने सालों का तुजुर्बा था वह तुजुर्बा हमें इस बजट में नजर नहीं आया। इससे तो यह लग रहा है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होगी। दोष हमें देते हैं कि हमने कर्जे उठाये। हमने अपने 5साल के कार्यकाल में 8032करोड़ रुपये का कर्ज उठाया। अभी दो सालों में 8612 करोड़ रुपये का कर्ज उठाकर इन्होंने इस प्रदेश को कर्जे में डूबो दिया। उससे निकलने का प्रयास हमें इस बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने आय का कोई साधन खड़ा नहीं किया है। एक उम्मीद थी, इन्होंने धर्मशाला में केबिनैट में एक निर्णय लिया था कि हम शराब के ठेकों की दोबारा निलामी करेंगे। आपके आबकारी एवं कराधान मंत्री जी का बयान आया कि 500 करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ेगी और अधिकारी भी कहते हैं कि बहुत लाभ होगा। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में भी कहा था कि क्या कारण है कि केबिनैट में लिए गए निर्णय को 12 दिन बाद बदल दिया गया और शराब के ठेके दोबारा निलाम नहीं हुए। 500 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो गया। आज तक मुख्य मंत्री महोदय और आपके आबकारी एवं कराधान मंत्री इसका कारण नहीं बता रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया? आज बिजली प्रोजैक्ट्स पर कोई निवेश नहीं कर रहा है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था।

क्या सरकार की विश्वसनीयता यह हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी निवेशक बिजली प्रोजैक्ट लगाने के लिए नहीं आ रहा है। क्या सरकार की विश्वसनीयता इतनी गिर गई है? क्या भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है? क्या प्रोजैक्ट लगाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं? यही साधन थे जिनसे हम अपने प्रदेश की आय बढ़ा सकते थे। ज्यादा निराशा इसलिए होती है क्योंकि आय के

24.3.2015/1230/ag/av/2

साधन तो सरकार बढ़ा नहीं रही है उल्टे फिजूलखर्ची कर रही है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने कोई आय का साधन नहीं बढ़ाया और फिजूलखर्ची लगातार बढ़ रही है। मैंने धर्मशाला में एक प्रश्न किया था मगर वह उस समय लगा नहीं था। मैंने उस प्रश्न में यह पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में कितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऐडवाइजर और ओ.एस.डी. इत्यादि लगाये गये हैं? हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऐडवाइजर और ओ.एस.डी. इत्यादि की 45 लोगों की फौज खड़ी कर दी गई। उनके ऊपर प्रति माह तीन करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा आ रहा है। वे लोग दो-दो गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। 25 तो ऐडिशनल ऐडवोकेट जनरल बना दिए जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। आप रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए कमेटी बनाते हो मगर उसकी रिपोर्ट दो साल तक नहीं आती। रिसोर्स मोबलाइजेशन तो क्या आना उल्टे टी.ए./डी.ए. लेने में फिजूलखर्ची बढ़ा दी। अब आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। बड़ा दुख होता है, जब इतने अनुभवी मुख्य मंत्री ऐसा बजट पेश करते हैं तो यह हालत है और उसके बाद कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि आपकी सरकार है, पेकेज ले आओ। क्या यह ठेका हमारा ही है? हम अटल जी के टाइम भी पेकेज लाए और मज़े आप लोगों ने उड़ाए। हम औद्योगिक पेकेज लेकर आए और आपकी सरकार बनी, मज़े आपने उड़ाए। आज भी आपको बिना मांगे मोदी जी ने बढ़ोतरी देकर इतनी ज्यादा सहायता दे दी। आप तो एक लाइन में धन्यवाद तक नहीं कर सकते, फिर भी हमारा नेतृत्व प्रदेश को ज्यादा-से-ज्यादा आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगा। मगर एक कटसी (curtsy) होती है। एक प्रयास होता है। अपने समय में तो प्रधान मंत्री के साथ-साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी लिख दिया जाता था। आप यहां नाम न लिखो, प्रधान मंत्री लिख दो। केंद्र सरकार का ही धन्यवाद कर दो। आपका तो पूरा बजट ही केंद्र सरकार पर निर्भर है। 66.65 प्रतिशत की आय तो वहीं से होनी है। इसके अलावा सारे बड़े प्रोजैक्ट वहीं से

आ रहे हैं। इसलिए आप यह देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में सहयोगी है। वे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन,

24.3.2015/1230/ag/av/3

ऐडवाइजर और ओ.एस.डी. इत्यादि बने है और उन पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1235/negi/ag/1

श्री रणधीर शर्मा ..जारी..

मुख्य मंत्री व मंत्री कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है । हम कहते हैं आप फिजूल खर्ची रोको। वह कहते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। परन्तु आर्थिक स्थिति का दिवालिया क्या निकला है मैं उसका एक प्रमाण देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।...(व्यवधान) ..मैं कहता हूं। इस महीने में आपने तनख्वाह देने के लिए हिमाचल प्रदेश के 77 विकास खण्डों में जितना भी डिवलपमैन्ट का पैसा पड़ा था सबको आपने वापिस ट्रेजरी में मंगवाया और तब आपने मार्च महीने की तनख्वाह दी। आप क्या बात करते हैं, मुख्य मंत्री महोदय यह आपकी नोटिफिकेशन है और ये आपके लैटर्ज़ हैं। आपने 77 ब्लॉकों से करोड़ों रूपये मंगवाये। हमारे बिलासपुर के सदर ब्लॉक से ढ़ाई करोड़ रूपये आपने ट्रेज़री में वापिस मंगवा लिया। आप बुलाते जो स्टेट का पैसा है। एस.डी.पी. का पैसा आपने मंगवाया। आपने विकास में जन सहयोग का पैसा मंगवाया। उपाध्यक्ष महोदय, हद तो यह है कि इन्होंने विधायक निधि का पैसा भी वापिस मंगवा लिया और सांसद निधि का पैसा भी वापिस मंगवा लिया। उपाध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा बुरी स्थिति किसी प्रदेश सरकार की हो नही सकती । आपने 35 लाख रूपये विधायक निधि का सदर ब्लॉक बिलासपुर का वापिस मंगवा लिया। आपने 35 लाख रूपये एम.पी. लोक सभा के फंड का वापिस मंगवा लिया। आपने एस.डी.पी. का 10 लाख रूपये वापिस मंगवा लिया। आपने 13वें वित्त आयोग में जिला परिषद् सदस्यों के लिए जो एक करोड़ रूपये था वह वापिस मंगवा लिया। आपने पंचायत समिति सदस्यों का 50 लाख रूपये मंगवाया। ये कुल ढ़ाई

करोड़ रूपये आपने सदर ब्लॉक से मंगवाया है। धर्माणी जी आप स्माइल मार रहे हैं, आपके ब्लॉक घुमारवीं से 2.95 लाख रूपये वापिस आ गया। झण्डुता ब्लॉक से 1.54 लाख रूपये वापिस मंगवाया है। स्वारघाट ब्लॉक से 70 लाख रूपये वापिस आ गया क्योंकि यह छोटा ब्लॉक है। इस तरह 77 ब्लॉकों से करोड़ों रूपये वापिस मंगवा करके आपने इस महीने तनख्वाह दी है। मुख्य मंत्री जी फिर भी कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप धन्य हैं।

24.03.2015/1235/negi/ag/2

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह है कि यह पैसा तुरन्त वापिस जाना चाहिए। यह विधायक निधि का पैसा जो हमारी डिस्क्रिशनरी है, हमने लैटर दे रखे हैं और हमने पैसा सैंक्शन कर रखा है। प्रधान एग्रीमैन्ट करेंगे और पैसा होगा नही तो वह कहां जाएंगे? लोक सभा सांसद निधि का पैसा उन्होंने सैंक्शन कर रखा है और वो पैसा ब्लॉक में आया है, आपने वो पैसा भी वापिस मंगवा लिया। उसपर आपका कोई अधिकार ही नही है। आज भीख मांगने लगे हो। जहां आपने 8612 करोड़ रूपये कर्ज़ा लिया वहां और कर्ज़ा ले लेते। परन्तु ये जो छोटा-छोटा पैसा जो निर्माण कार्यों पर खर्च होना था उसको क्यों वापिस मंगवा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि इस पैसे को तुरन्त वापिस भजा जाए ताकि हमारे क्षेत्रों के जो विकास कार्य रूके हुए हैं वे आगे बढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी कानून-व्यवस्था पर चर्चा हुई। हमने चर्चा की कि किस तरह से 29 जनवरी को हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्य मंत्री जी के बेटे के नेतृत्व में हमला किया गया। वहां कार्यकर्ताओं को चोटें आई, एक कार्यकर्ता की आंख की रोशनी चली गई, कार्यालय टूट गया लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की । एम.एल.सी. की रिपोर्ट तक चण्डीगढ़ पी.जी.आई. से नही मंगवा सके और आप कहते हैं कानून-व्यवस्था ठीक है। क्या कानून किसी के लिए कोई और है और मुख्य मंत्री के बेटे के लिए कोई और है ? हमने जब सूचना दी थी तो क्यों पुलिस वहां मौक पर नहीं पहुंची? आज क्यों कानून-व्यवस्था की धज्जियां प्रदेश में उड़ रही है? आज चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं और ब्लातकार की घटनाएं बढ़ रही है। मुख्य मंत्री जी आंकड़े पुराने दे देते हैं। अरे, समाचार पत्र देखिए कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भयानक घटनाएं कानून-

व्यवस्था की प्रदेश में घटित नहीं होती ? आपने खुशफहमी में जीना है तो जीते रहिये परन्तु हालत प्रदेश की बदतर है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस पुलिस को प्रदेश की कानून-व्यवस्था देखनी है उस पुलिस का दुरूपयोग आप अपने

24.03.2015/1235/negi/ag/3

राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ षडयन्त्र रचने में कर रहे हैं। आप हमारे नेताओं पर, हमपर झूठे मुकदमें बना रहे हैं। पहले तो आपको आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी नज़र आते थे । लेकिन अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत हमारे विधायकों पर और उनके परिवार के सदस्यों पर केस बना रहे हैं। पुलिस को एक ही काम है। हमारे आरोप सत्य सिद्ध हुए उपाध्यक्ष महोदय जब पिछले कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रदेश सरकार की फाइल जिसमें इन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री महोदय पर चालान पेश करने की कोशिश की थी उसको यह कह कर वापिस कर दिया कि धूमल जी पर कोई केस नही बनता है। यह हमारी जीत है। यह राज्यपाल महोदय ने फाइल वापिस की है ।...(व्यवधान).. यह दैनिक ट्रिब्यून में छपा है । ई.टी.वी.में आ रहा है। ..(व्यवधान)..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

24/1240/03.2015.यूके/जेटी/1

श्री रणधीर शर्मा---जारी---

मुख्य मंत्रीः ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री रणधीर शर्माः मुख्य मंत्री महोदय, इसलिए आपकी पोल खोली है । आपने जो राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ षडयन्त्र रखने की कोशिश की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आदरणीय धूमल जी को बदनाम करने की कोशिश की, उस षडयन्त्र का पर्दाफाश हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं इन पत्रकार मित्रों का कि इन्होंने इस फाईल को रातोंरात उजागर कर दिया । ये पत्रकार मित्र बधाई के पात्र हैं । उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु मेरा यह कहना है कि अभी भी सुधरने

का समय है । आप पुलिस को ठीक काम पर लगाइए । आप पुलिस का जो काम बनता है, उनसे वह करवाइए । परन्तु इस तरह से हमारे राजनैतिक नेताओं पर झूठे मुकदमें बनाने में जो पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, उसको आप रोकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बजट में बहुत सी बातें कीं हैं और बहुत सी बातों पर हमारे साथियों ने यहां पर चर्चा कर दी है । शिक्षा के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की है जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी की थी । उस चर्चा में भी खड़े हो कर इन्होंने कहा था कि मैं तो वहां भी स्कूल खोल दूंगा जहां पर दो बच्चे होंगे । मुझे तो उस दिन लग रहा था कि ये तो यह भी कह देंगे कि मैं वहां पर भी स्कूल खोल दूंगा जहां कोई बच्चा नहीं होगा । क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो उसने भी तो पढ़ना है । यह कांग्रेस की प्रथा है ।

24/1240/03.2015.यूके/जेटी/2

मुख्य मंत्रीः मैं तो आपको ट्यूशन देने के लिए आपके घर में भी स्कूल खोल दूंगा ।
श्री रणधीर शर्माः क्योंकि ये जब ये जिसका वोट नहीं है, उसके लिए मुख्य मंत्री की, प्रधान मंत्री की कुर्सी रिज़र्व कर देते हैं तो पैदा होने वाले बच्चे के लिए स्कूल भी रिज़र्व कर सकते हैं । कांग्रेस वाले क्या करते हैं यह हैरानी की बात है क्योंकि ये अभी वोटर भी नहीं है तब भी मुख्य मंत्री का पद रिज़र्व, वोटर ही नहीं है तब भी प्रधान मंत्री का पद रिज़र्व । इसलिए जहां बच्चे पैदा भी नहीं होंगे वहां भी स्कूल । कल आपकी पोल खुली । हमारा प्रश्न लगा था । आपकी पोल खुली है । आज प्रदेश में......

मुख्य मंत्रीः अगर कहीं दूर-दराज में दो बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनके लिए स्कूल खोल दिया तो आपको कोई एतराज है? क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? आप समाज विरोधी हैं, आप जनता विरोधी है ।

श्री रणधीर शर्माः बिल्कुल खोलिए, मैं तो कह रहा हूं आप और भी खोलिए। परन्तु मुख्य मंत्री महोदय, बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक तो दे दो ।

मुख्य मंत्रीः सारी जगहों पर अध्यापक हैं ।

श्री रणधीर शर्माः कहां हैं? 943 स्कूलों में एक-एक अध्यापक है, वह खिचड़ी बनाए कि पढ़ाए ? खिचड़ी बनाने का काम भी उनका, डाक बनाने का काम भी उनका ।

24/1240/03.2015.यूके/जेटी/3

मुख्य मंत्रीः दो बच्चों के लिए एक अध्यापक काफी है ।

श्री रणधीर शर्माः 5 क्लासों को पढ़ाने का काम भी उनका । अगर वह बीमार हो जाए या उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो स्कूल में पार्ट टाईम वाटर कैरियर पढ़ाता है या फिर स्कूल में बड़ा सा ताला लग जाता है । यह स्थिति है आज हिमाचल प्रदेश की । उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां

मुख्य मंत्रीः ऐसा बिल्कुल नहीं है । यह बिल्कुल झूठा भाषण दे रहे हैं । ये कहते हैं कि स्कूल में मास्टर नहीं हैं । मैं कहना चाहूंगा कोई प्राईमरी स्कूली बिना मास्टर के नहीं है । और ये कहते हैं कि जो मास्टर है वही सारा काम करता है, खिचड़ी भी बनाता है । जब कि खिचड़ी बनाने वाले कोई और होते हैं । यह सही नहीं है । ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं ।

श्री रणधीर शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को ध्यान होना चाहिए कि खिचड़ी बनाता नहीं, खिचड़ी बनाने का सारा प्रबन्ध टीचर ही करता है । हिसाब-किताब, कितना प्याज आया, कितना नमक आया, कितनी मिर्च आयी, कितने चावल आए यह सारा वही करता है । डाक का काम सारा वही करता है । आपके 411 स्कूल ऐसे हैं, जहां 5 से कम बच्चे हैं।

मुख्य मंत्रीः तो क्या हुआ ?

श्री रणधीर शर्माः कुछ नहीं हुआ । परन्तु आप वहां टीचर दो ।

24/1240/03.2015.यूके/जेटी/4

मुख्य मंत्रीः अगर दो बच्चे भी होंगे, तब भी हम स्कूल देंगे। आपने स्कूल बन्द किए, हमने वह भी खोले हैं। आपको क्या एतराज है? अगर दूर-दराज इलाके में दो बच्चे भी हैं तो क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है?(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह :सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्षः यदि कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है तो बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य बजट पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इन्होंने ये सारे तथ्य जो प्रश्न के उत्तर हैं

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

24.03.2015/1245/sls-jt-1

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बजट भाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं ,यह सारे तथ्य जो प्रश्नों के उत्तर आए हैं, उन पर बोल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने इस चर्चा का जवाब देना है, आप अपनी बात जवाब देती बार कहें। ...(व्यवधान)...

Deputy Speaker: This is no Point of Order. Hon. Member, you continue.

श्री रणधीर शर्मा :इन्होंने जवाब देना है। अगर मैं कोई गलत आंकड़े दूं तो यह बोल सकते हैं। पिछले कल एक प्रश्न लगा था जिसके उत्तर में यह तथ्य सामने आए हैं। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

श्री रणधीर शर्मा :बोलें कैसे जब मुख्य मंत्री जी खड़े हो जाते हैं और बटन लाल हो जाता है।

उपाध्यक्ष : आपको पूरा मौका मिल रहा है। He (Hon. Chief Minister) can intervene any time.

श्री रणधीर शर्मा :उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि ये स्कूल खोलें, मैं कहीं ऐतराज़ नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां स्कूल खोलें, वहां अध्यापक भेजें। बच्चा एक हो तो भी स्कूल खोलें परंतु अध्यापक तो दे दें। अध्यापक नहीं हैं। 943 स्कूलों में केवल एक-एक अध्यापक है। वह छुट्टी चला जाए तो स्कूल बंद हो जाता है। वह बीमार हो जाता है तो स्कूल बंद हो जाता है। कहीं कमरे नहीं हैं, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने माना है और गलती सुधारी है। मुख्य मंत्री महोदय, आपने बजट में कहा है कि अब हम सुदृढ़ीकरण करेंगे। आप हमारी लाईन पर आए हैं। बाल्दी जी हमारे समय भी थे और उस समय पॉलिसी बनी थी कि स्कूल कैसे अपग्रेड होंगे। हमारे समय में तो ये हमें अकड़ते थे लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या जादू कर दिया कि अब अकड़ते नहीं हैं। जहां बोलते हैं, स्कूल खोल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि स्कूल खोलें, अच्छी बात है। आप घर-घर

24.03.2015/1245/sls-jt-2

स्कूल खोल दो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन अध्यापक दो। इतनी ज्यादा रिटायरमैंट्स होती हैं जितनी आप अप्वायंटमैंट्स नहीं करते। ...(व्यवधान)...
मुख्य मंत्री : इस साल भी हजारों की तादाद में जे.बी.टी. और अन्य अध्यापक भर्ती हुए हैं।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी सीटों पर बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। When he (Hon. Chief Minister) is speaking, let him speak.

श्री सुरेश भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री सदन के नेता हैं। इन्होंने चर्चा का जवाब देना है। अगर बीच-बीच में टोकते रहेंगे और साथ-साथ जवाब देते रहेंगे तो चर्चा खत्म ही नहीं होगी और कई हमारे सदस्यों का बोलने का नंबर नहीं आएगा। इसलिए इस बात को रैगुलेट करिए। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इन्होंने चर्चा

का जवाब एक बार देना है। ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं ,किसी का भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम तो जुनियर लोग हैं ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : भारद्वाज जी, मुझे चर्चा का जवाब देना है लेकिन जो इन्होंने कहा, मैं मौके पर इनको उसका जवाब दे रहा हूं। I have every right to correct him.

उपाध्यक्ष : रणधीर शर्मा जी, अब आप बाईंड-अप कीजिए।

श्री रणधीर शर्मा :उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार स्कूलों के खोलने को ही विकास मानती है। लोगों की ज़रूरत क्या है? लोगों की ज़रूरत है कि हर गांव और स्कूल तक सड़क हो और पीने का पानी मिले। सड़क पक्की होगी और स्कूल चार किलोमीटर दूर होगा तो बच्चे बस से चले जाएंगे। हॉस्पीटल दूर होगा तो एंबुलैंस से चले जाएंगे।

Deputy Speaker: Now, wind up please.

24.03.2015/1245/sls-jt-3

श्री रणधीर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं बोला ही नहीं । ...(व्यवधान)... अभी तो आधा भी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं।

मेरा कहना यह है कि आप गांवों में सड़कें बनाओ, वहां सड़कें चाहिए। वहां पर पीने के पानी की स्कीमें चाहिए। आप स्कूल पर स्कूल दिए जा रहे हैं। बात वही है कि बंदे को लंगोटी चाहिए, ये उसको टोपी दे रहे हैं। लंगोटी तो उपलब्ध करवा दो, टोपी बाद में देते रहना।

अब एक और योजना चला दी -'बच्चों को मुफ्त बस यात्रा', वह भी सैंट्रल स्कूल के बच्चों को। बाली साहब, कमाल है आपका। बच्चे कहां बस में जा रहे हैं? जब से यह सरकार बनी है ,मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 बस रूट बंद हो गए। मैं चार बार मिल लिया। हर विधान सभा सत्र से पहले इनका एक प्रेम पत्र आता है कि विधायक जी, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जो रूट चाहिए वह बता दो। हम

बता देते हैं। दो सालों से यही प्रेम पत्रों का सिलसिला चला है। कोई बस रूट बहाल नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुफ्त बस यात्रा देनी थी तो नए बस रूट लगाने पड़ने थे। उनके बस टाईम स्कूलों के टाईम के साथ एडजस्ट करने पड़ने थे ,तब बच्चों को फायदा होना था। इन्होंने न तो कोई नया बस रूट लगाया, न बसों के टाईम बदले बल्कि उनके बस रूट ही बंद कर दिए और जो फायदा मिल रहा था, वह भी नहीं मिल रहा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना का औचित्य क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, फिर ये कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हमने श्री आनन्दपुर साहिब नैणा देवी रोप वे बनाने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया।

जारी ...गर्ग जी

24/03/2015/1250/RG/JT/1

श्री रणधीर शर्मा------क्रमागत

हमने श्री आनंदपुर साहिब-नैनादेवी रोप-वे बनाने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया। समझौता हो गया और फॉरेस्ट लैण्ड की एन.ओ.सी. मिल गई , लेकिन सरकार बदली, तो एम.ओ.यू. ही रद्द हो गया। सरकार बदलने के साथ ऐसा हुआ। हमारी एक कोशिश थी दो अलग-अलग धार्मिक स्थानों को आपस में जोड़ने की, हमारी कोशिश थी भाईचारा बढ़ाना, एकता बढ़ाना और लोगों को सुविधा देना। अब इस सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित तो क्या करना था बल्कि उस एम.ओ.यू. को ही रद्द कर दिया और दो साल से ये ऐडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम हिमाचल से नया रोप-वे बनाएंगे ,लेकिन कोई निवेशक ही नहीं आ रहा है। क्योंकि वह टैक्नीकल फिजिबिल ही नहीं है। इसलिए यदि ये इस तरह की राजनीति करेंगे, तो पर्यटन को कहां से बढ़ावा मिलेगा? तभी तो पहले पांच लाख पर्यटक प्रदेश में आए थे और अब ये घटकर तीन लाख पर पहुंच गए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ई-विधान की बात की गई। इसकी पूरे देश में बहुत चर्चा है, बुटेल साहब को इसके लिए वाहवाही मिल रही है, राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी और सभी इसके लिए बधाई दे रहे हैं। बुटेल साहब कह रहे हैं कि मैं 15 करोड़ रुपये की बचत करूंगा और पेड़ कटने बंद हो जाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय पेड़ बचाएंगे और भरमौरी साहब पेड़ काटते

जाएंगे। इस तरह से उन पेड़ों को बचाने का क्या फायदा? मुझे नहीं पता कि ई-विधान से कितने पेड़ बचे, कितने नहीं बचे। लेकिन भरमौरी साहब ऐडवांस में ही लग गए, कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना सारा विधान सभा क्षेत्र ,अपना जिला, मुख्य मंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र, इनका जिला और एक सी.पी.एस. तो बेचारे इसी दुःख से त्याग-पत्र भी दे गए। यह हालत है। डेली एक-न-एक समाचार पढ़ने को मिल जाता है कि 50पेड़ अवैध रूप से कट गए।

Deputy Speaker: Now wind up, please. आपने बहुत समय ले लिया। अब कृपया समाप्त करें।

श्री रणधीर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने तो दीजिए। वन माफिया इतना सक्रिय हो गया। जितना समय इन्होंने लिया, मैंने कहां लिया? उद्योग मंत्री जी से बात करते हैं कि नए उद्योग कहां आए ,पुराने बंद हो गए। उनके विधायक कहते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रैसपॉसबिलटी पॉलिसी में दो परसेंट दें। उद्योग मंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो खाली फैलिसिटेटर का काम करते हैं। न आप उन

24/03/2015/1250/RG/JT/2

उद्योगों को रोक सकते, न आप उनकी सोशल रैसपौंसबिलिटी निर्धारित कर सकते हैं ,तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपका धंधा लाईसैंस देना और कमीशन खाना ही है और आप कुछ नहीं कर सकते। उद्योगपति आते हैं, हमारी सस्ती जमीन और बिजली लेते हैं ,यहां का पर्यावरण खराब करते हैं और आपका उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। यह प्रदेश सरकार आज क्या कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, सरेआम भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस कारण ही उद्योगपतियों को कोई कुछ बोल नहीं पा रहा और इसीलिए आज प्रदेश की यह हालत है। मुख्य मंत्री महोदय ने बागवानों के लिए एक अच्छी बात कही। मैडम जी ने उसका जिक्र किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। ये एक 'ऐप्पल रिजुविनेशन प्रोजैक्ट' ला रहे हैं, रूट स्टॉक ला रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मुख्य मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप यह रूट स्टॉक वह दें जो आपने अपने बगीचे में लाया था जिससे आपकी आमदनी

एक साल में 15 गुणा ज्यादा बढ़ गई। वही ऐप्पल रूट स्टॉक बागवानों को दें तब मुझे लगता है कि बागवानों का बेड़ा पार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां भानुपली-बरमाणा रेल लाईन की बात की। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आया करते थे और तब ये इसकी चर्चा किया करते थे। आज भी इन्होंने कहा कि हम इसके लिए 25% देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बजट में इसके लिए एक पैसा नहीं रखा। मुख्य मंत्री महोदय, इसके लिए आपकी नीयत में कमी है। मैं तो इसके लिए सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलकर इस रेलवे लाईन को बजट में डलवाया है और इस कारण से यह रेलवे लाईन बनेगी। परन्तु इसके लिए आप सहयोग करें, प्रदेश सरकार इस कार्य में सहयोग करे, यह मेरा आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें इन्होंने कीं। थोड़ी अच्छी भी कीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी गलत है। परन्तु देखने में आता है कि विकास की दृष्टि से हिमाचल का कोई योगदान नहीं है। आप लोक निर्माण विभाग का हैड पढ़ें, तो नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ,विश्व बैंक, सैन्टर रोड फण्ड आदि, ये सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं और इसी प्रकार से आई.पी.एच. के हैड में भी सभी सैन्टर की स्कीम हैं। हिमाचल क्या कर रहा है ,हिमाचल का योगदान कहां है? विकास में कहीं भी हिमाचल का योगदान नहीं है। इसलिए इस बजट का क्या समर्थन करना। यह जरूर है कि इन्होंने कुछ टौफियां बांटी हैं। मजदूरों की दिहाड़ी 10/-रुपये बढ़ा दी।

24/03/2015/1250/RG/JT/3

आज तो 10/- किसी शादी में बाजे वाले भी नहीं लेते ,कोई भिखारी भी नहीं लेता। लेकिन इन्होंने 10/-रुपये दिहाड़ी बढ़ाई। फिर हमें कहते हैं। मैडम कह रही थीं कि आप अपने समय में 200/-रुपये करते ,मैडम, हमने 75/- रुपये से 150/-रुपये की थी और आप तो 15-/0रुपये से 180/- तक ही पहुंचे। जरूरत है, इस बार कम-से-कम से 200/- रुपये तो कर देते ताकि पांच साल में 300/-रुपये कर जाते। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा निवेदन है कि उस रेशो में दिहाड़ी बढ़ाइए और एक मजदूर की दिहाड़ी को कम-से-कम 200/-रुपये किया जाए। होमगार्ड का मानदेय आप सिर्फ 20/-रुपये

बढ़ा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आज कोई बच्चा चॉकलेट मंगाता है, तो वह भी 20/-रुपये में नही आती----------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1255/MS/JT/1

श्री रणधीर शर्मा जारी-----------

बच्चा चॉकलेट मंगवाता है वह भी 20 रूपये में नहीं आती और आप उनका मानदेय 20 रूपये बढ़ा रहे हैं? पार्ट टाइम वाटर कैरियर का महीने का 200 रूपये बढ़ा रहे हैं यानी एक दिन के पांच या छः रूपये बनते हैं। कम-से-कम उसको 2000 रूपये कर दो। होमगार्ड का मानदेय 300 रूपये प्रतिदिन कर दो और कर्मचारियों के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है क्योंकि इसने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। 4-9-14 के बारे में हमने कहा था कि वर्ष 2009 से देंगे। फिर आप कहते थे कि हम तो वर्ष 2006 से करेंगे। अब अभी तक भी यह पूरी तरह से लागू नहीं है। आपने जिनको सेवा विस्तार दिया वे भी खुश नहीं और जो बाकी हैं, वे भी खुश नहीं है। आपने सबके साथ अन्याय किया। आप जिनको 31 मार्च को रिटायर कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि हमें तो एक साल की एक्सटैंशन मिली है, हम कैसे दो महीने बाद चले जाएंगे। वे कोर्ट से स्टे लेंगे और एक महीने का नोटिस जो चाहिए, वह आपने दिया नहीं है। उसके कारण जो लोग प्रमोशन से वंचित हुए, वे भी नाराज हैं। उपाध्यक्ष जी, जो इस साल रिटायर होंगे, हैरानी है जितने एक साल पहले रिटायर होने थे वे 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं परन्तु कुछ लोग 28 जनवरी को ही रिटायर हो गए। यानी जो बाद में रिटायर होने थे वे पहले रिटायर हो गए। कोई 31 जनवरी को रिटायर हो गए, वे उनके बाद रिटायर होने थे जिनको 31 मार्च को रिटायर कर रहे हैं। यह कहां का न्याय है? आप सबके साथ न्याय तो कर दो। इसलिए कर्मचारी जिनको आपने एक्सटैंशन दी, न वे खुश हैं और न बाकी खुश है। जो डी0ए0 की किस्त आपने अनाउंस कर दी है वह आपने फिर से बजट में बोल दी। इस बजट में नया कुछ भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। कहने को आपने कह दिया कि कर्मचारी रीढ़ की हड्डी हैं।

उपाध्यक्ष जी, एक योजना एल0ई0डी0 बल्ब देने की चलाई कि तीन-तीन बल्ब देंगे। यह केन्द्र की योजना है। वे एक बल्ब 120 रूपये में दे रहे हैं यहां 150 रूपये में दे रहे हैं। तो 30 रूपये कहां जाएंगे? यह कहीं सरकारी घोटाला तो नहीं हो रहा है? जब केन्द्र 120 रूपये में बल्ब दे रहा है तो यहां 150 रूपये में कैसे दे रहे हैं? अगर आपने लोगों के लिए कुछ करना है, आपने गरीब लोगों को फायदा देना है तो तीन

24/03/2015/1255/MS/JT/2

की बजाए पांच एल0ई0डी0 के बल्ब दीजिए और पैसा मत लो। तब तो आपका एहसान होगा। लेकिन आप बल्ब भी दे रहे हैं और पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं। कल तो प्रधान मंत्री जी ने कह दिया कि अब इनकी कीमत 80 या 85 रूपये तक आ जाएगी और आप एक-एक बल्ब का 150 रूपये ले रहे हैं। इसलिए यह सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा विधायक निधि 50 लाख रूपये से 7 0लाख रूपये की है।

उपाध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रणधीर शर्माः मैं समाप्त कर रहा हूं। तो इस निधि में जो राइडर लगा है उसके लिए इन्होंने वायदा किया है ,इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। ऐच्छिक निधि दो लाख रूपये है। इनके बड़े चहेते विधायक संजय रतन जी कल कह रहे थे कि इसको चार लाख रूपये कर देंगे।

उपाध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रणधीर शर्माः जी सर, वाइन्ड अप कर रहा हूं। इतनी देर में तो हो भी जाना है। मेरा आग्रह यह है कि मुख्य मंत्री महोदय इस राशि को 4 लाख रूपये नहीं बल्कि पांच लाख रूपये कर दीजिए। आपका लक्की नम्बर 5 है इसलिए 5 लाख रूपये कर दो और फिर माननीय धूमल जी जब मुख्य मंत्री बनेंगे तो उनका लक्की नम्बर 9 है तो फिर हम 9 लाख रूपये करवा लेंगे। इसलिए इसको 5 लाख रूपये कर दीजिए।

इसी तरह से आपने कर बजट में नहीं लगाया परंतु बस किराये पहले ही बढ़ा दिए और पेट्रोल/डीजल पर वैट लगा दिया। इसलिए मेरी यह मांग है, अभी बजट पारित होना है। क्योंकि हमारी केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की है इसलिए आप बस किराये में हुई बढ़ोत्तरी वापिस लीजिए और पेट्रोल / डीजल पर लगाया वैट भी वापिस लीजिए ताकि जो मोदी सरकार ने जनता को फायदा दिया है, वह सीधा जनता तक पहुंच सके। उसमें आप रूकावट मत डालें। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये फायदे आप लोगों को जरूर दें।

उपाध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

24/03/2015/1255/MS/JT/3

श्री रणधीर शर्माः उपाध्यक्ष जी, इस बजट में, जैसे मैंने शुरू में कहा, न तो कोई विजन है, न कोई दिशा है, न विकास की उम्मीद है और न ही लोगों के कल्याण की उम्मीद है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं कर सकता लेकिन कांग्रेसी विधायक बड़ा समर्थन करते हैं। हैरानी हुई, यहां कहते हैं कि मैं 1967का एम0एल0ए0 हूं। मेरे न सड़क, न पानी फिर भी वीरभद्र जी जिन्दाबाद। अब कांग्रेसियों की यह मजबूरी है। मैं इनके लिए सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूं।

राजा दिन को रात कहे, तो रात कहे सब कोय।
सांच झूठ का निर्णय नहीं, हां ,जी हां ,जी होय॥

ये इनका हाल है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः राजा के बदले में आप कहिए, धूमल साहब और जो कांग्रेस के लिए कहा है उसकी जगह भाजपा के एम0एल0ए0 ऐसा कहते हैं।

परिवहन मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, माननीय विधायक रणधीर जी ने एक-दो टिप्पणियां परिवहन विभाग के बारे में की हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

4.03.2015/1300/जेके/एजी1/

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभाक्ता मामले मंत्रीः-----जारी------
मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। आपने एक बात कही ,इन्होंने अपनी बात को कंट्राडिक्ट किया, यह कहा कि स्कूल के बच्चों को बसें नहीं मिलती है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हर जगह स्कूल खोल दिये। He is contradicting his own statement. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 1785 बसों का बेड़ा था उसको बढ़ा करके हमने 2255 किया। पहली बार इतिहास में 1350 नई बसें चली है। आप580 करोड़ रूपये छोड़ करके गए थे और जब हम गये थे तो सारी लायबिल्टीज़ पूरी करके गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो दूसरी बात इन्होंने कही कि किराया बढ़ा दिया। हमने 20 ये 40 परसेंट किराया कम किया है। सरकार ने यह किराया पारदर्शी तरीके से कम किया है। अब जो कंडक्टर हम रख रहे हैं उसकी इसी सदन में स्टेटमैंट दूंगा और उस दिन आप वाहवाही करेंगे कि बहुत बढ़िया स्टेटमैंट आई है।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

24.03.2015/1405/SS-AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 2ः05 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्षः अब मैं श्री रोहित ठाकुर, माननीय मुख्य संसदीय सचिव को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिवः उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को जो इस माननीय सदन में प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने आने वाले वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट प्रस्ताव रखे हैं मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि प्रदेश के सीमित साधनों के बावजूद भी एक अच्छा बजट दिया है। जो बजट हर हिमाचली, हर आम आदमी से जुड़ा है, उसको माननीय

मुख्य मंत्री ने लाया है। मैं समझता हूं कि यह डिवैल्पमैंट ओरिऐंटिड बजट है। एक प्रैगमैटिक बजट है और आने वाले समय में प्रदेश को एक नई दिशा देगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। साथ-ही-साथ जो इन्होंने 18वीं मर्तबा वित्त मंत्री के रूप में बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं वे अपने-आप में एक कीर्तिमान हैं। उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश का जो विकास का सफ़र है वे नये-से-नये मुकाम और मील पत्थर हमारे प्रदेश ने छुए हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का एक बहुमूल्य योगदान रहा है। मैं बजट अनुमान के दौरान पढ़ रहा था कि आज हर हिमाचली की, हर व्यक्ति की जो औसतन आमदन है, पर-कैपिटा इन्कम है, वह 1 लाख 4 हजार से अधिक हो चुकी है। आज जहां पूरे राष्ट्र की पर-कैपिटा इन्कम 88 हजार के आसपास है हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल की रही है। जिसका श्रेय जैसे कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी के योगदान को जाता है। मैं पिछले आंकड़ें भी पढ़ रहा था। जब 1971-72 में प्रदेश को स्टेट हुड का दर्जा मिलने का दौर चला हुआ था उस वक्त हिमाचल की पर-कैपिटा इन्कम मात्र 688 रुपये थी। जो आज बढ़कर 1 लाख 4 हजार रुपये हो चुकी है। जो एक बैरियर एक लाख का था उसको क्रॉस करके मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यह और बढ़ेगी। एक मॉडल स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य ने जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के बुनियादी सैक्टर्ज़ हैं जो हमारे कोर सैक्टर्ज़ हैं उनको और सुदृढ़ करने का हर सम्भव प्रयास किया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सीमित साधनों के बावजूद भी चाहे हम सड़कों

24.03.2015/1405/SS-AG/2

की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, उसमें हम आगे बढ़े हैं। कृषि और बागवानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे हम इन क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें या सामाजिक न्याय विभाग की बात करें, हर क्षेत्र में मैं समझता हूं कि रचनात्मक विकास की दृष्टि से पिछले दो वर्षों में कार्य हुआ है। जहां मैं सड़कों की बात कर रहा था, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 33,700 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है जो पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के पास है। मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया, हमें आज़ादी मिली, 1947 में हिमाचल प्रदेश में मात्र 288

किलोमीटर सड़कें थीं। हमारे हिमाचल निर्माता डॉ0 यशवंत सिंह परमार से लेकर सभी सक्सैसिव गवर्नमैंट ने भरसक प्रयास किया है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पर सड़कों का और जाल बने। इसी को देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने सड़क निर्माण क्षेत्र में प्राथमिकता दी है जो सही मायने में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। आज मैं समझता हूं कि एक अन्य उपलब्धि है जो हमारे दूसरे चरण का वर्ल्ड बैंक ऐडिड प्रोजैक्ट सड़क निर्माण क्षेत्र में लगभग 3800 करोड़ का हिमाचल प्रदेश के लिए आना है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए होगी..

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1410/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव, श्री रोहित ठाकुर जारी---

जो हिमाचल प्रदेश के लिए आना है, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए होगी। आपको याद होगा, हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भी 2003 से लेकर 2007 के मध्य लगभग 1365 करोड़ का प्रोजैक्ट सड़क निर्माण के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस प्रदेश के लिए लाया था जिसके अंतर्गत पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 10 हमारे इम्पोर्टेंट रोड़ज़ हैं, जो जिला हैड क्वार्टर्ज़ को जोड़ते थे, चाहे वह चम्बा की बात हो, ऊना की बात हो चाहे कुमारहट्टी-नाहन की बात हो जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, इसके तहत इनकी अपग्रेडेशन का कार्य हुआ और आज यह 3800 करोड़ रु0 का प्रोजैक्ट बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जो हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो मैं समझता हूं कि इस वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजैक्ट में आनी चाहिए उसमें हमारी छैला, नैरीपुर, यशवंत नगर, सोलन, ओच्छघाट कुमारहट्टी सड़क है जो जिला शिमला को ही नहीं हमारी सोलन ,सिरमौर और समस्त क्षेत्रों को कवर करती है और हमारे किसानों और बागवानों की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर ये जो स्टेट हाई-वे नं0-6 है, इसको आने वाले समय में जब हमारा वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश को आएगा, प्राथमिकता के आधार पर इसको इस प्रोजैक्ट के तहत लिया जाए।

इससे विशेषकर जो हमारा सेब बाहुल्य क्षेत्र है, सेब सीज़न के दौरान जो कंजैशन शिमला और सोलन शहर में रहती है उससे भी

24.03.2015/1410/केएस/एजी2/

निज़ात मिलेगी और डायरैक्ट कनैक्टिविटी प्रदेश की और देश की भिन्न भिन्न मार्किट्स में हमारे बागवानों और किसानों को सबको उपलब्ध होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसी तरह से हमारी अन्य सड़क जो रोहडू से प्रारम्भ होती है, मैंदली टिक्कर, बागी गुम्मा होते हुए जाती है यह भी हमारे जिला शिमला की महत्वपूर्ण सड़क है और एक तरह से जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसको आज पूरे भारतवर्ष में फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे जिला शिमला का उसमें एक अग्रणी योगदान है और उसमें भी जो जिला शिमला का हार्ट है उस एरिया को कवर करती हुई यह ठियोग खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड़ को जोड़ेगी और इसकी भी अपनी महत्वत्ता है। अभी भी सी.आर.एफ. के तहत कुछ कार्य इसका चला हुआ है लेकिन जब से केन्द्र में अभी नई सरकार बनी है वहां पर भी थोड़ा संशोधन हुआ है कि इस वर्ष सी.आर.एफ. के तहत जो फंड्ज़ मिले हैं, वे ब्रिजिज़ के लिए मिले हैं, सड़क निर्माण के लिए नहीं मिले हैं। आने वाले समय में जब वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट प्रदेश को आता है तो यह सड़क भी हमारी वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजैक्ट के तहत डाली जाए जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इसी तरह से यहां पर ठियोग -खड़ा पत्थर -हाटकोटी रोड़ जो जिला शिमला की जीवन रेखा है, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट अनुमान में भी बात रखी है, प्रतिपक्ष के नेता धूमल जी ने भी कहा, डॉ0 बिन्दल ने भी कहा, आपको पता होगा कि इस महत्वपूर्ण सड़क को हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ल्ड बैंक के तहत

24.03.2015/1410/केएस/एजी3/

सेंक्शन किया गया था। 7 अगस्त, 2007 को मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केन्द्र में दिल्ली में इसका हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी और तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम जी थे, उनकी उपस्थिति में लगभग 1365 करोड़ रु0

का प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश को मिला था और इसके तहत ही ठियोग-खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड़ का कार्य भी होना था। 7 अगस्त और 10 अक्तूबर, 2007 के बीच में कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं था मात्र दो महीने के बाद, समय से पूर्व चुनाव घोषित हो चुके थे और साथ ही साथ जो इससे सम्बन्धित औपचारिकताओं की यहां पर बात बीच में आई, हमारी पूर्व सरकार ने समय के साथ उस प्रोसैस को प्रारम्भ कर दिया था । इसी तरह से भूमि अधिग्रहण की बात आती है। ठियोग-खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड़ के अंतर्गत लगभग 79 गांव आते हैं जिसमें से 65 गांव की सेक्शन 4 तक के नोटिसिस मार्च, 2007 को हो चुके थे। मैंने उस दौरान भी विधान सभा में एक प्रश्न किया था, मैं अपना पिछला प्रश्न देख रहा था और अक्तूबर तक आपके जो फरदर आपके सेक्शन 5-6 तक के नोटिसिस हो चुके होंगें और मैं समझता हूं इसी तरह से फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ जो अत्यन्त महत्वपूर्ण थी इसकी भी हमारी इन- प्रिंसिपल अप्रूवल 22 अक्तूबर, 2007 को, क्योंकि इसके अंतर्गत दो डिविज़न फोरैस्ट के आते हैं, रोहड़ू डिविज़न की आ चुकी थी और एक तरह से काफी हद तक हमारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.3.2015/1415/ag/av/1

श्री रोहित ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव)----------जारी

मैं समझता हूं कि काफी हद तक हमारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। सरकार कन्टिन्युटी में काम करती है। वर्ष 2007 में जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई तो उनके पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर खेद का विषय है कि उस समय पूरे कार्यकाल की जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि रही वह मात्र 18 प्रतिशत रही। यहां पर सेब सीजन की बात आई। वर्ष 2013-14; दोनों एप्पल सीजन में हमने बहुत ही सुचारु रूप से सेब विपणन का प्रबंध किया। वर्ष 2013 और 2014 में रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। इसके विपरीत अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तुलना करें तो वर्ष 2008 में जोकि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम वर्ष था। उस दौरान भी आपकी मार्किट इनटरवैंशन स्कीम के तहत जो सेब खरीदा जाता है उसके तहत लगभग 1.10 00लाख बोरी मौके पर ही नष्ट करनी पड़ी। यह सिद्ध करता है कि उस दौरान सरकार की कितनी नाकामी रही होगी। यही स्थिति वर्ष 2009 में रही और यही स्थिति वर्ष 2010 में रही। जब 28 करोड़ रुपये का सेब यानि लगभग 9.11 लाख बोरियां मौके पर ही नष्ट करनी पड़ी; यह दर्शाता है कि उस

समय सड़क की कितनी दुर्दशा रही होगी। आज हमारी वचनवद्धता है कि आने वाले तीन वर्षों में यानि 2017से पूर्व हम निश्चित रूप से ठियोग-खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड में सुधार लायेंगे। हमारी यह वचनवद्धता जनता-जनार्दन के साथ है। इस ओर कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करुंगा क्योंकि आपने मॉनिटरिंग की बात की है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो हमारे हालात है क्योंकि अभी भी यहां मात्र चार महीने कार्य हो सकता है। इस साल प्रोलोंग्ड विंटर के कारण यहां पर लगभग एक महीने की क्षति हुई है। आने वाले तीन-चार महीने हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी मीटिंग माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हो। इसमें हमारे सारे प्रतिनिधि चाहे इसमें हमारे वर्मा जी की बात हो, ब्राक्टा जी की बात हो या हमारी बात आती है; हम सब मिलजुलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे ताकि आने वाले दो-ढाई वर्षों के अंदर हम जनता के सामने अपनी वचनवद्धता को पूरा कर पायें। ऐसा मेरा मानना है।

24.3.2015/1415/ag/av/2

यहां पर टनल के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात आई है। मैं सहमत हूं, आज के समय में हमारे पहाड़ी राज्य में टनल्ज का बनना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2003-07 के बीच प्रदेश के अंदर लगभग 8 टनल्ज की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी। उनके बारे में जियोलोजिकल सर्वे किया गया था और डी.पी.आर. बनाई गई थी जो लगभग 1800 करोड़ रुपये के करीब थी। वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस दौरान भी इस पर संज्ञान लिया गया और 13वें वित्तायोग को आपने इसको अनुमोदित किया था। चाहे इसमें रानीताल(कांगड़ा) की टनल की बात हो। चाहे शिमला शहर की टनल की बात हो। चाहे खड़ा-पत्थर टनल की बात हो। चाहे उसमें ऊना जिले में हरोली-तराला में टनल की बात हो; ये लगभग 8 टनल्ज बननी थी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा जहां हर क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमें प्रोजैक्ट मिल रहे हैं। चाहे वह हॉर्टिकल्चर का लगभग 1000 करोड़ रुपये का जो प्रोजैक्ट आया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्यान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लगभग 3800 करोड़ रुपये आपका फेज़-ii का प्रोजैक्ट आने वाले समय में हमारी सड़क निर्माण के लिए आना है, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह से टनल्ज के निर्माण के लिए भी आज

समय आ चुका है। 21 वीं शताब्दी में इस तरह की टनल्ज का निर्माण पूरे प्रदेश में हो। जहां इससे हमें बेहतर कुनैक्टिविटी मिलेगी वहीं हमारे डिसटैंसिज शॉर्ट होंगे और ऐनवायर्नमैंट का कम नुकसान होगा। हमें इस बारे में विचार करना होगा। हमें इस ओर अपनी प्राथमिकता देनी होगी।

आज प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर काफी सड़कें बन चुकी है। मगर आज इसके कोर नैटवर्क को जो आज से लगभग 10-15 साल पहले बना था उसको फिर से रिवाइज किया जाए। उसके लिए 10-12 साल हो चुके हैं। उस दौरान वर्ष 2001 के सेनसिज के हिसाब से पूरे प्रदेश का एक कोर नैटवर्क बना था। आज वर्ष 2011 के सैनसिज के मुताबिक यहां कोर नैटवर्क बने

24.3.2015/1415/ag/av/3

ताकि इसमें प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत हमारे प्रदेश को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके।

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1420/negi/ag/1

श्री रोहित ठाकुर माननीय मुख्य संसदीय सचिव.. जारी..

आज आवश्यकता है कि 2011 के सेंसिज़ के मुताबिक कोर नेटवर्क बनें ताकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी सड़क की बात आई। मैं समझता हूं कि हम सब इसकी महत्वता से सहमत हैं। आज इस सड़क की दशा के कारण हमारे क्षेत्र के वासियों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है । मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्ज़ा दिया जाए ताकि आने वाले समय में, दो-तीन वर्षों के बाद जब हमारा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद

इसके रख-रखाव, रिपेयर/मेन्टेनेंस की कोई समस्या न हो। मैं समझता हूं कि इसका समाधान यही है कि ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ जो रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र तक जाता है और उसको कवर करता है इसको राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्ज़ा मिले। जो माप-दण्ड और पैरामीटर्ज़ नेशनल हाईवे के होते हैं उसके अन्तर्गत ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड आता है। जहां ठियोग की तरफ से यह एन.एच.-22 से कनैक्टिड है वहीं दूसरी तरफ से पांवटा-रोहड़ू रोड -एन.एच.-72(b) से ये कनैक्टिड है। ठियोग-हाटकोटी रोड के निर्माण के लिए जो सत्यग्रह की बातें भी बीच में करनी पड़ी है । मैं समझता हूं कि अपने कार्यकाल की सारी बातें जो मैंने पहले कही है उन बातों को

भूला जा रहा है। ठियोग-हाटकोटी रोड को नेशनल हाईवे का दर्ज़ा दिया जाए।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि कृषि और बागवानी क्षेत्र हमारे प्रदेश की बुनियाद है और हमारी पहले प्राथमिकता रही है और मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से हर सम्भव प्रयास किया गया है कि हमारा किसान और बागवान खुशहाल हो। हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। आज बहुत सी स्कीमें इस बजट के माध्यम से मैं समझता हूं किसानों और बागवानों के हित में लायी

24.03.2015/1420/negi/ag/2

गई है । जहां लगभग 154 करोड़ रूपये की इरिगेशन की स्कीम आगामी 5 वर्षों के लिए किसानों व बागवानों के हित में लायी गई है वहां 60 करोड़ की ऑफ सीजन वैजिटेबल योजना प्रारम्भ की गई है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है । क्योंकि ऑफ सीजन वैजिटेबल भी हमारी आर्थिकी का एक मुख्य बिन्दु बन रहा है । इसी तरह से मार्केटिंग यार्डज़ के लिए बजट में लगभग 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसमें भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे पूरे प्रदेश में जहां भिन्न-भिन्न मार्किट्स बनें हैं वहां आवश्यकता है कि सी.ए. स्टोरज़ का निर्माण भी साथ में हो। एच.पी.एम.सी. का 5-6 स्टोरज़ हैं, इसके अतिरिक्त हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पास भी सी.ए. स्टोरज़ हो, जो मैं समझता हूं कि यह समय की जरूरत है। इसके निर्माण के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। हालांकि एच.पी.एम.सी. को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट के माध्यम से जो हमारे 3 कोल्ड स्टोर थे उनकी अपग्रेडेशन के लिए लगभग 5 करोड़ रूपये का प्रावधान

किया है, पतलीकूहल ,ओडी और रोहड़ू का कोल्ड स्टोर उसके अन्तर्गत आते हैं। इससे भी निश्चित रूप से किसानों और बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि जहां हमने वर्ष 2007 में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एच.डी.ओज., ए.डी.ओज., ए.ई.ओज. और एच.ई.ओज. की काफी पोस्टें कैबिनेट के द्वारा एप्रूव करवायी थी और उनकी भर्ती 2008 में हुई लेकिन आज मैं समझता हूं कि इन दोनों महत्वपूर्ण विभागों में इनकी काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं। जैसे कुछ पोस्टों की आपने एप्रूवल दी हैं लेकिन ए.डी.ओज. की लगभग 80 पोस्टें खाली पड़ी हैं । इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर की 350 पोस्टें खाली हैं जिसमें से 150 पोस्टें भरने की आपने एप्रूवल दी हैं और इसके अतिरिक्त 200 पोस्टें इनकी रिक्त हैं। इसी तरह से हार्टीकल्चर विभाग में एच.डी.ओज. की 127 पोस्टें खाली हैं और एच.ई.ओज. की 137 पोस्टें खाली हैं। मैं समझता हूं कि जितनी भी रिक्त पद हैं इनको भरने के लिए कैबिनेट/ सरकार द्वारा मंजूरी मिले। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कृषि और बागवानी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर किसान और बागवान

24.03.2015/1420/negi/ag/3

खुशहाल रहेगा तभी मैं समझता हूं कि विकास के मामले में जो हम बात कर रहे थे उसमें हमारा प्रदेश आगे की ओर जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले कल यहां पर सुजानपुर रैली की बात आई थी । वहां पर जो हमारे डेजिगनेट प्रधान मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के और जो आज हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री हैं श्री मोदी जी...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

24.03.2015/1425/यूके/जेटी /1

श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव---जारी

आज हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री हैं, श्री मोदी जी, इन्होंने सोलन में एक रैली हुई थी, मई के पहले हफ्ते में, वहां पर इन्होंने सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी तीन गुणा बढ़ाने की बात कही थी । आज मैं समझता हूं, मैं पीछे "ट्रिब्यून" पढ़ रहा था, उसमें जब फैक्ट्स पढ़ रहा था जो बड़े अलार्मिंग थे, जहां इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही थी । उसके विपरीत आज के समय में पिछले वर्ष के मुकाबले 33% अतिरिक्त इम्पोर्टिड सेब

आपका वाशिगंटन, पोलैण्ड ,फ्रांस, इटली, ईरान इत्यादि ऐसी-ऐसी कंट्री से आ रहा है और एक अनुमान के अनुसार मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अन्दर लगभग 3 लाख पेटी प्रति हफ्ते आजादपुर मंडी में डम्प की जायेंगीं । जिसका निश्चित रूप से किसानों और बागवानों को बड़ा नुकसान होगा । इस पर भी मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव केन्द्र को जाना चाहिए । प्रधान मंत्री जी ने कमिटमैंट यहां की जनता-जनार्द्धन से की थी, वह मैं समझता हूं कि उसको पूरे करने का समय आ चुका है । ऐसा न हो जैसे भूमि अधिग्रहण बिल में भी किसानों से वोट तो लिए लेकिन सत्ता में आने के बाद एकदम से उसमें भी कहीं न कहीं एक बड़ा यू-टर्न लिया है । ये सारी बातें, हिमाचल की भी और पूरे राष्ट्र की जनता-जनार्द्धन देख रही है ।

मैं समझता हूं और भी जो दो वर्षों में हमारी उपलब्धियां हुईं, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात आती है, जहां हमारे को3 - 3मैडिकल कॉलेज मिले हैं । इसके लिए हम UPA सरकार, डा0 मनमोहन सिंह जी, श्री गुलाम नबी आजाद जी, अपने माननीय मुख्य मंत्री जी, ठाकुर कौल सिंह जी, हमारे

24.03.2015/1425/यूके/जेटी/2

को 300 करोड़ रूपए की सुपर स्पेशियलिटी के रुप में हॉस्पिटल टांडा और आई0जी0एम0सी0 को दिए थे । आपके कैंसर हॉस्प्टिल मंडी और शिमला के लिए 90 करोड़ रूपए दिए । जो हिमाचल के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

इसी तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट महकमें में लगभग 1310 बसें जो अपने आप में कीर्तिमान है, वह प्रदेश को उपलब्ध होगी । इसके माध्यम से भी विशेषकर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश बसता है, वहां पर इसको बहुत लाभ मिलेगा और इस तरह से मैं समझता हूं कि कोई ज़ीरो वैल्यू की बस हमारे प्रदेश में नहीं रहेगी । जो अच्छी बसें आयी हैं, जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत उसकी सेवाएं पूरे प्रदेश को मिलेगी ।

इसी तरह से मैं पीछे जेतली साहब का बजट भी देख रहा था ,उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है, वह है पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीटयूट ऑफ हार्टिकल्चर,

जो उन्होंने इस दफा अमृतसर में दिया है। आने वाले समय के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा यह हमारा एक तरह से पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक फ्रूट बाऊल है। इस तरह के इन्स्टीट्यूट की हमारे क्षेत्र में भी आवश्यकता है। यह इन्स्टीट्यूट आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हो।

Deputy Speaker : You please wind up now.

24.03.2015/1425/यूके/जेटी/3

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रोहित ठाकुर): इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। जहां मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की। इसी तरह से आयुर्वेदा विभाग में मैं समझता हूं कि काफी लम्बे समय से हमारी पोस्टें खाली थीं उनको भरा जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 250 पोस्टें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की खाली हैं। इस ओर भी हमें रिक्रूटमैंट करनी पड़ेगी। हर संभव प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है। इस बजट के माध्यम से कि हमारा हिमाचल प्रदेश आज जो विकास के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है।

यहां शिक्षा की बात हो रही थी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 16 000से अधिक आपके स्कूल खोले गए हैं। इन्हीं दो वर्षों के दौरान लगभग 14 कॉलेज खोले गए हैं। जिनकी हर बिल्डिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सारी बातें है लेकिन आने वाले समय के लिए जहां 14वें वित्तायोग ने बहुत बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश को दी है साथ ही साथ हमारी सैंट्रली स्पोंर्स्ड स्कीम में कटौती होनी है। यह भी एक चिंता का विषय है। इस बजट में जो मैं समझता हूं कटौती चाहे वह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात हो चाहे वह ट्राईबल सब प्लान की बात हो चाहे वह एस0सी0 सब प्लान की बात हो, चाहे आई0सी0डी0एस0 की बात हो, मिड डे मील की बात हो, भाई साहब, रणधीर जी कह रहे थे, सर्विशिक्षा की बात हो, भारी कटौती इस बजट में हुई है, इसका कहीं न कहीं प्रतिकूल असर हमारे प्रदेश को भी पड़ेगा। यह जो बजट है इसमें हर संभव प्रयास किया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को जो आज मैं समझता

24.03.2015/1425/यूके/4

हूं कि एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है। उसकी जनता-जनार्द्धन को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। जहां 5 वर्ष में हमारे कांट्रैक्ट के एम्पलॉयज को रेगुलर किया गया। आपके PTA और पैरा टीचर्स को काफी समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें कांट्रैक्ट दिया गया। पेंशन में बढ़ोत्तरी की गयी। ये सारी बातें मैं समझता हूं कि विकास से जुड़े मामले थे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक नया क्षितिज छूएगा । मैं एक बार फिर से उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.03.2015/1430/sls-jt-1

श्री रोहित ठाकुर (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी
आपने मुझे समय दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

24.03.2015/1430/sls-jt-2

उपाध्यक्ष : अब श्री आई.डी. धीमान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने 18 मार्च को जो यह बजट पेश किया, इसकी चर्चा में मैं भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

मुझे लगता है कि लोग बजट को आंकड़ों की दृष्टि से देखते हैं। धूमल जी ने यहां पर स्पष्ट किया है और उसमें त्रुटियां निकाली हैं। उस पर ज्यादा समय न लेते हुए, यह 28,339 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें से सैलरी में 8,2 85करोड़ रुपये, पैंशन में 4041 करोड़ रुपये और जो कर्जो का इंट्रस्ट है, उसके लिए 2950 करोड़ रुपया है। लोन पेमैंट के लिए 1503करोड़ रुपये हैं। जो फिसकल डैफिसिट है वह 3285 करोड़ रुपये है। डवलपमैंट के लिए 40% पैसा बचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खैरात से किसी प्रदेश को ऊंचा नहीं किया जा सकता। प्रदेश को सही योजनाएं चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले के 1, 2, 3पृष्ठों में ही जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहना शुरू किया है वह सामाजिक सुरक्षा पैंशन से संबंधित है। इस पर आप इतरा रहे हैं कि यह हमने 500 रुपये से 550 रुपये कर दी। अरे, इसमें आपका क्या योगदान है? यह पैंशन तो वर्ष 1977 में शांता जी ने शुरू की थी और उस समय यह 50 रुपये थी। बीच में दो बार आपकी सरकार आई, तब क्या आपने इसमें कोई पैसा बढ़ाया? आपने समाज को बड़ा सुरक्षित रखा है और आप बड़ा ध्यान रखते हैं। आप बड़ी देर से शासन कर रहे हैं। उसके बाद 1990 में फिर शांता जी आए और उन्होंने इसको 100 रुपया किया। बीच में फिर आपकी सरकार आई, आपने टका नहीं बढ़ाया। सिर्फ़ इसलिए कि आप हिमाचल प्रदेश के बहुत हितैषी हैं। जिस राशि से बूढ़े का, अपंग का, अनुसूचित जाति का, निर्धन का पेट भरता है ,उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया? धूमल जी आए, 1998 में इन्होंने इसे 100रुपये से 200 रुपये किया। बाद में फिर आये तो 200 रुपये से 400 रुपये किया और फिर 400 रुपये से 450 रुपये किया। अब कौन-सी ऐसी अक्ल ऊपर से आ गई कि आपको पैंशन बढ़ाने का ख़याल आ गया? इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अगर आते ही दो-अढ़ाई वर्षों में 100 रुपया बढ़ा दिया, उसका आज कोई

24.03.2015/1430/sls-jt-3

मूल्य नहीं है। यहां से आपने शुरू किया। मुझे लगता है कि आप प्रदेश की बड़ी चिंता करते हैं।

जारी ..गर्ग जी

24/03/2015/1435/RG/JT/1

श्री ईश्वर दास धीमान--------क्रमागत

मुझे लगता है कि आप इस प्रदेश की बहुत चिन्ता करते हैं कि आपने मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई। दिहाड़ी वह लगाता है जो निर्धन है, 80-80 वर्ष का आदमी भी दिहाड़ी लगाता है जिसके पास सुबह खाने को है, शाम को नहीं है और शाम को है, तो सुबह नहीं है। उसके आपने कितने रुपये बढ़ाए हैं? आपने उसके सिर्फ 10/-रुपये बढ़ाए। आज तो 10/-रुपये में एक चाय का कप भी नहीं आता है। आपने उसका रोज़

का एक कप चाय का बढ़ा दिया। आप उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। प्रदेश में जो सबसे निर्धन या असहाय है, जिसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है उसके लिए आप बजट में वृद्धि कर रहे हैं। बहुत अच्छा यह आपका बजट है। मेरे ख्याल से आपकी दृष्टि में पृष्ठों का बहुत महत्व है कि जितना लंबा बजट होगा, उतना ही वह अच्छा होगा। इस बजट का बोझ तो लोगों के ऊपर पड़ा है कि आपने उसकी दिहाड़ी मात्र दस रुपये बढ़ाई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार होमगार्ड्स की दिहाड़ी 260/-रुपये से 280/-रुपये की। इस प्रकार मजदूर को एक कप चाय के पैसे बढ़ाए और होमगार्ड को दो कप चाय के पैसे बढ़ाए। आजकल चाय का एक कप 10/-रुपये से कम नहीं आता। यही आपके इस बजट की झलक यहां नजर आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बेरोजगारों का कोई वर्णन नहीं किया है जो आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया था। उनका वह 1000/-रुपया कहां गया, किसको मिला, कितनों को मिला ,वह सूची कहां है? आपने तो सबको कहा था। साढ़े ग्यारह लाख बेरोजगार नौजवान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। जिनका पंजीकरण हुआ है क्या उनको मिला? कुछ नहीं मिला। मुझे लगता ही नहीं है कि जो आप कौशल विकास की बात करते हैं उसमें कोई प्रगति हुई हो। कतई कोई प्रगति नहीं हुई। इनफॉरमेशन टैक्नॉलॉजी टीचर्स जो 12-13 वर्षों से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और जो सिस्टम यहां विधान सभा में स्थापित हुआ है यह भी उनकी देन से हुआ है। माननीय धूमल जी के समय उनको रखा गया था। उनके लिए भी तो कोई नीति बनाने की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह उचित नहीं समझा। आप इनफॉरमेशन टैक्नॉलॉजी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उनके लिए कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहूंगा कि इस बजट में कर्मचारियों को क्या दिया इन्होंने? यहां के कर्मचारियों को तो पंजाब के वेतनमान मिलते हैं। वे आस लगाए बैठे थे कि पंजाब की तर्ज पर हमें भी कुछ मिलेगा। मुझे नहीं

24/03/2015/1435/RG/JT2

लगता कि उन्हें 4-9-14 का लाभ मिला या पंजाब की तर्ज पर रिवाइज्ड पे स्केल में मदद मिली हो। उनके साथ यह बहुत अन्याय हुआ है। हां, एक बात का आप और श्रेय ले रहे हैं कि आपने 719 विद्यालय खोल दिए। रोहित जी, आप बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे थे ,लेकिन केवल बजट ही पढ़ रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। इसमें यह देखने वाली बात है कि आपने कितने टीचर्स की भर्ती की? आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना पैसा लगाया, कितने स्कूल हैं जो आज बिना अध्यापकों के चल रहे हैं या एक या दो अध्यापक से चल रहे हैं? वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने है!----------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1440/MS/AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी----------

आप स्कूल खोलने का श्रेय ले रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री सभाओं में कह रहे हैं , यहां विधान सभा में कह रहे हैं कि दो बच्चों पर भी स्कूल खोलेंगे। जो अगले साल बच्चा पैदा होगा, उसके लिए भी स्कूल खोलेंगे। कितनी देर से धूमल जी यह कह रहे हैं कि काफी हो गया, काफी हो गया। अब इस ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और हमने किया है। वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रदेश का भला होता है। आपने वाह-वाह लूटने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मेरे कांग्रेस के साथियों, जो कुछ आपने कह रखा था, वह कोई वायदा पूरा नहीं किया। आप कहते हैं कि इसको सरकारी दस्तावेज बना दिया और सबकुछ दे दिया। आपने आंशिक रूप से प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए क्या किया? जैसे अभी कहा कि जो कुछ आप देते हैं, वह खैरात के रूप में देते हैं। आपने गरीब और शिक्षिक के लिए क्या किया? जो आपने वोकेशनल एजूकेशन चलानी थी उसके लिए क्या किया? उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आप मुझे यह बताइए कि महाविद्यालय हमारे समय में भी खुले हुए थे। लेकिन वे डि-नोटिफाई कर दिए। किसलिए कर दिए कि उनके लिए भवन नहीं है। बजट का भी शायद बहाना लिया और फिर छः महीने के बाद वे फिर

खोल दिए। तो क्या अब भवन बन गए? आधारभूत ढांचा और टीचर्स क्या पूरे हो गए? आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैब और लाइब्रेरी क्या वहां पर बन गई? ये क्या सिस्टम है, क्या सोच है कि छः महीने के बाद उन्हीं जगहों पर संस्थान खोल दिए? मेरे साथ यहां पर कंवर जी, गुलाब सिंह जी और दूसरे साथी बैठे हैं। ये जानते हैं कि जितने बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनको कितनी परेशानी थी। उस परेशानी को हम कहते रहे। बजट दिया हुआा था और मुझे यह लगता है कि उस वक्त का बजट शायद 15 करोड़ रूपये था। आपने उनको 15 बनाकर एक-एक करोड़ रूपये देकर उनको चलाने की बात कर दी और वहीं पर ही कर दी। अब कौन सा बदलाव आ गया? आपको कौन सी आवाज ऊपर से आई कि स्कूल खोल दो ,स्कूल खोल दो। आप इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं? मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े 80-90 पृष्ठ के इस बजट में कोई वजनी बात हो या ऐसा कुछ लगता हो कि प्रदेश आगे

24/03/2015/1440/MS/AG/2

बढ़ेगा। आपने तो हमारी सरकार के सिले हुए कपड़ों को उधेड़ करके फिर से सिल दिया है और आपने कुछ नहीं किया। शांडिल जी बैठे नहीं है। वह छात्रवृत्तियों की बात कर रहे थे। बाली जी भी स्कूल खोलने की बात कर रहे थे कि क्यों खोले। हमें बता रहे थे कि क्या जरूरत थी। छात्रवृत्तियों में 75 प्रतिशत पैसा तो केन्द्र से आता है लेकिन आपने स्वयं क्या दिया? आपने सरकार की तरफ से क्या दिया है? इसमें मैरिट का चलता था, चलता है। अनुसूचित जाति का चलता है, चलता है। यानी उसमें शेयर चलता है लेकिन अपनी तरफ से प्रदेश सरकार ने क्या किया है? आपको यह ख्याल नहीं आया कि जब धूमल जी की सरकार वर्ष 1998 में बनी थी,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

4.03.2015/1445/जेके/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः-----जारी-----
इस प्रदेश के दो हजार अनुसूचित बच्चों को चुन-चुन कर जमा एक और जमा दो में एक साल के लिए 10-10 हजार रूपये दिये गये। ओ.बी.सी. बच्चों को भी छात्रवृत्तियां दी गई। अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना और विवेकानन्द मेधावी छात्रवृत्ति योजना दी गई। हम लोगों के पास आवाज़ आई कि सामान्य वर्ग के लोगों का क्या

कसूर है? अभी भी पत्र माननीय धूमल जी के पास पड़े होंगे और मेरे पास भी हैं। उन जातियों का कितना उत्थान हुआ? कितने बच्चे डॉक्टर्ज और इंजीनियर्ज बनें? जब सामान्य वर्ग की बात आई तो 4 हजार बच्चों को 10-10 हजार रूपया सालाना जमा एक और जमा दो में आगे बढ़ने के लिए दिया गया। इस तरह से प्रदेश आगे बढ़ेगा। 10 रूपये, 20 रूपये और 30 रूपये बढ़ाने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। सबसिडी मत दो और अगर देनी है तो अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा दो। पिछड़े वर्ग के बच्चों को ,गरीब के बच्चों को प्रशिक्षण दो। राजाओं की तरह जो आप खैरात देते हैं उसको बन्द करो। इससे प्रदेश ऊंचा नहीं होगा। प्रदेश अगर ऊंचा होगा तो शिक्षा के स्तर से ऊंचा होगा। आप उस 10 हजार में 2 हजार रूपया ही डाल देते तो अच्छा होता। लेकिन आप तो शासक है। शासक कहां जानता है गरीब की तकलीफ? आपने तो अंकुश लगाया। क्या अंकुश लगाया कि 5 परसेंट उसमें बढ़ाया और 5 परसेंट दूसरे में बढ़ा दिया? इस तरह से आपने संख्या बढ़ा दी। हमारे समय में 9 हजार बच्चों को जब छात्रवृत्ति देने की बात हुई तो लगभग साढ़े आठ हजार बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिलने लगी। हमने कहा था कि फर्स्ट डीविजन तक जाओ या उससे नीचे भी जाते हैं तो भी दी जाएगी। अगर बच्चों का कोई भला होता है तो करना चाहिए। लेकिन आपने उसमें एक रूपया भी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। शुरू-शुरू के पन्नों में ही माननीय मुख्य मंत्री जी परिंदा बन गये, उड़ान लगाने लगे और डरे हुए से थे। ऐसा नहीं चलेगा, परिदों के लिए कहा गया है किः

तालीम नहीं दी जाती है परिदों को उड़ने की,
ये खुद ही मंजिल तय करते हैं आसमानों की,

4.03.2015/1445/जेके/एजी/2

रखते हैं जो हौंसला आसमान को छूने का,
वे परवाह नहीं करते हैं ज़मीन पर गिर जाने का।

माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ करना है तो गट्स से करो, डर के न करो और ये करते रहे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

24.03.2015/1450/SS-AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः
मैंने तो उनके शेर पर शेर बोला। मैडम, अब शेर सुनने के लायक नहीं हैं। आपके इन्हीं पृष्ठों पर और खास कर बजट के पृष्ठ-42 पर हमें बड़ी संतुष्टि हुई। वीरभद्र जी, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ा हो गया, अब स्कूलों को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। ये ख्याल इनको 20 वर्षों के बाद आया। हम बार-बार कहते रहे कि अगर स्कूल खोलने हैं तो पहले प्रबंध करो। हमने अपने वक्त में माननीय धूमल जी के समय में जो भी स्कूल खोले उनके लिए पहले बजट का प्रबंध किया। टीचरों का प्रबंध किया। आपने तो 32 विभागों में 5 हजार नौकरियों का ऐलान कर दिया। अरे, हमने तो एक ही विभाग में 18 हजार नौकरियों का ऐलान किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते कि आप बेरोजगारों के कितने हितैषी हैं। एक जगह वीरभद्र जी ने लहरों की बात भी कर दी। मुख्य मंत्री जी, यहां बैठे नहीं है लेकिन सुन रहे होंगे। मैं इनको यह सलाह देता हूं कि लहरों से मत छेड़ना, बड़ी खतरनाक होती हैं।

"साहिल पर बैठा हुआ तमाशायी,
साहिल पर बैठा हुआ तमाशायी,
हर डूबने वाले पर तरस तो करता है
इम्दाद नहीं करता।"

पठानिया जी, हालत क्या है? मैं शर्मा जी को भी नहीं बोलूंगा। ये भी शरीफ आदमी हैं। पंचायतों का सत्यानाश कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 13757 पाठशालाएं हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ही कहते हैं कि नामांकन कम हो गया। यह हमारे वक्त में 99.7 परसैंट था। आपके वक्त में यह 99कैसे रह गया? और उसका कारण दे रहे हैं। साक्षरता हमारे वक्त में तो 84.87 थी। आपके वक्त में यह 82 कैसे रह गई? यह क्यों कम हो रही है? गुणवत्ता नीचे क्यों जा रही है? क्या इसका जवाब आपके पास है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब देता हूं। निजी स्कूल जिस गांव में खुल गया, उस गांव में निजी स्कूल में बच्चे चले गए। अरे, हद तो यह है कि गरीब का बच्चा भी वहां चला गया। जो 170 रुपये दिहाड़ी लगा रहा है वह भी 500 रुपया दे रहा है। क्यों दे रहा है? आपके स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। आपके स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आधारभूत ढांचा नहीं है।

24.03.2015/1450/SS-AG/2

आपके स्कूलों में पढ़ाने का वह समर्पण नहीं है, वह भी बताऊंगा कि क्यों नहीं है।

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1455/केएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी---

उपाध्यक्षः धीमान जी, कृपया अब वाइंड-अप करिए।

श्री ईश्वर दास धीमानः काई रोस्टर नहीं था, ये गरीबों के रक्षक थे? पिछले दरवाजे से 65प्रतिशत वाला रहने दिया और 35 प्रतिशत वाला रख दिया । ये यही करते रहे। माननीय धूमल जी ने सबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड की स्थापना की जिसको इन्होंने मुर्गीखाना कहा। पांच साल कोई नियुक्ति उसके द्वारा इन्होंने नहीं की लेकिन प्रदेश का जो नुकसान हुआ, यहां पर अयोग्य अध्यापक आ गए। टैन्योर शुरू किया, कॉंट्रैक्ट शुरू किया, पैट, पैरा टीचर,पी.टी.ए. शुरू किया, उनको संरक्षण दिया। कहीं पर रोस्टर का ध्यान नहीं रखा गया, कहीं पर चयन प्रक्रिया नहीं हुई। अध्यापक सेवा निवृत्त होता है या तबदील होता है उसके बाद ज्वाईन करता है, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं । अगर हमने 961 अध्यापकों को निकाला था तो इसलिए निकाला था क्योंकि वे अयोग्य थे। वे पढ़ाने के लायक नहीं थे। हम बच्चों के दुश्मन नहीं है लेकिन मेरे मित्रो अगर आप प्रदेश का भला चाहते हैं, गुणवत्ता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो गुणवत्ता से समझौता मत करो। यह पिछले दरवाजे वाली बात छोड़ दो। जो हमारी सरकार ने अध्यापक चयन किए, बोर्ड और कमिशन द्वारा किए लेकिन जो आपकी तरफ से चयन हुए वे चोर दरवाजे से हुए। इस तरह का अगर स्कूल में अध्यापक होगा जो चार बार मैट्रिक में फेल हो कर पास हुआ होगा वह क्या पढ़ाएगा? आशा जी, मैं आपकी दिक्कत समझता हूं। मैं आपकी तारीफ करता हूं लेकिन आपने कहा कि हम लोग इस बजट के

24.03.2015/1455/केएस/एजी/2

खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सके। हम क्या नहीं बोल सके? क्या हम गालियां निकालें? शब्दों से ही बोलना था। और आपने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। हमें आपकी दिक्कत पता है। मैं तो मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि अगर आप इस प्रदेश की शिक्षा मंत्री होती तो यह हालत नहीं होती। आपने जो कुछ कहा, यह किसको खुश करने के लिए कहा? हमें लगता है कि आपने दिल से कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 35.2 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में चले गए और हमारे वक्त में यह प्रतिशतता 28 थी। इससे हमारा गरीब लुट रहा है। वह भी चाहता है कि उसका बच्चा भी टाई लगाए, अंग्रेजी पढ़े। क्या कमी है सरकार में? प्राईमरी में पांच साल का बच्चा दाखिल होता है निजी स्कूल वाले प्री प्राईमरी पढ़ाते हैं और प्री-प्राईमरी जहां पर कोई करता है वह छोड़ता नहीं है ।
उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप कीजिए। आधा घण्टा पूरा हो गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

24.3.2015/1500/ag/av/1

उपाध्यक्ष : जारी---
आधा घंटा पूरा हो गया है। धीमान जी, आपने बजट अभिभाषण का समर्थन करना है? आपने जो भी करना है, कीजिए। मैंने आपको पूरा समय दे दिया है, अब आप अपनी चर्चा यहीं पर बाइंड-अप कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आधा समय हुआ है।

उपाध्यक्ष :आपको आधे घंटे का समय दे दिया है। अब आप बाइंड-अप कीजिए।(---व्यवधान---) इनकी उम्र को देखते हुए ही मैंने इनको आधे घंटे का समय दिया है। आप अपनी बात दो मिनट में खत्म कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमानः उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपके स्कूलों में 64 प्रतिशत बच्चे रह गये हैं। क्या आप साहस कर सकते हैं? जब तक प्राइमरी स्कूलों में प्री नर्सरी, नर्सरी क्लासिज एड नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। इधर-उधर से जो करना है; करो वरना इन निजी स्कूलों की वजह से प्रदेश लुट गया है। यह ठीक है कि कई जगह अच्छी तालिम होगी मगर लोग लुटते भी है। पैसे वालों को लूटे, गांवों के लोगों को तो न लूटे। यह मेरा सुझाव रहेगा।

यहां रोहित जी कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उत्थान हुआ है। रोहित जी, क्या उत्थान हुआ?1 , 117स्कूलों में एक अध्यापक है और 6,786 स्कूलों में दो अध्यापक है। प्राइमरी स्कूल्ज में 10 हजार टीचर की कमी है। अगर मैं कमरों की बात करुं तो 510स्कूलों में 510 कमरे यानि एक स्कूल में एक कमरा है। आपने अपने ढाई वर्षों के कार्यकाल में किया क्या? हमने 126 करोड़ रुपये की सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना चलाई जिसमें 12000 कमरे का संकल्प लेकर 13, 000से ज्यादा कमरे बनाये। हमारी सरकार ने हर स्कूल को कमरा देने का प्रयास किया। आपने क्या किया? आपने आराम किया। मुझे लगता है कि इस सरकार में कुछ करने का जज्बा नहीं है। 'खुद माली के हाथों इस गुलेस्तां की तबाही देखी तो नहीं जाती ,पर

24.3.2015/1500/ag/av/2

देख रहे हैं'। एजोक, तकल्फ में तकलीफ सरासर, आराम से है वे लोग जो तकल्फ नहीं करते। आप लोग तकल्फ करते ही नहीं। आप आराम करते रहे हैं, करते रहो मित्रो लेकिन प्रदेश का ध्यान रखें।

पर-केपिटा इनकम बढ़ी, मगर आपकी वजह से नहीं बढ़ी। यह सेब बैल्ट की वजह से बढ़ी है। ऊपर के जिलों में सेब बैल्ट है, सारे जिलों में सेब बैल्ट नहीं है। वहां की आय से आपकी प्रदेश की पर-केपिटा इनकम बढ़ी। निचले इलाकों में नहीं बढ़ी, यह तो एवरेज है। आशा जी, अगर आप समझें कि देश में यह प्रदेश दूसरे नम्बर पर है तो वह सेब की वजह से है। उनका अगर फायदा पहुंचा है तो सेब वालों को पहुंचा है। उनका फायदा निचले वालों को नहीं पहुंचा। ऐवरेज के लिए उन्होंने प्रदेश को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। मगर यदि आप यह सोचें कि यह आपकी मेहनत

का नतीजा है तो यह गलत बात होगी। यह सिर्फ प्रदेश के बागवानों की मेहनत का नतीजा है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए। मैं अब श्री कुलदीप कुमार जी को बुला रहा हूं। आप बाइंड-अप कीजिए।

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1505/negi/jt/1

श्री ईश्वर दास धीमान ..जारी..

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में शब्द व पृष्ट बहुत हैं लेकिन सार कुछ नही है। इस बजट के अन्दर कुछ नही है, यह खोखला बजट है। मुझे ऐसी कोई योजना इसमें नहीं लगती है जो प्रदेश को आगे ले जाने वाली हो। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कौल सिंह जी इसीलिए बाहर चले गए कि शायद कुछ तफ्सरा न हो जाए।

उपाध्यक्षः धीमान जी अब आप प्लीज़ समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : शिक्षा और सड़कों का सुधार नही हुआ है । चाहे कोई भी विभाग हो, जैसे मैंने कहा आपने तो हमारी पुरानी नीतियों को ही।...(व्यवधान)..

उपाध्यक्षः धीमान जी, बहुत समय हो गया है। Not to be recorded.

अब माननीय सदस्य, श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

24.03.2015/1505/negi/jt/2

श्री कुलदीप कुमारः माननीय उपाध्यक्ष जी...(व्यवधान) ...मैंने तो काफी आपकी बात मान ली । ...(व्यवधान) ..हम भी तैयार हैं।

उपाध्यक्ष जी, 18 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी 1993से लेकर इस मान्य सदन में हूं, तब से मुझे जनता ने

चुन कर यहां भेजा है। मैं 1993 में पहली बार चुनकर इस मान्य सदन में आया था। तब से ये बजट भी पेश हो रहे हैं और बजट पर चर्चा भी हो रही है। ....(व्यवधान) ...मैंने कई बजट देखें और कई चर्चाएं हुई । लेकिन अब की बार जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है यह बहुत ही शानदार बजट और बहुत ही संतुलित बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है । उसमें जो उनका तजुर्बा है18 वीं बजट पेश करने का वह झलकता है । मैं उनको ऐसा संतुलित और शानदार बजट पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस सरकार की जो प्रतिबद्धता है सर्व कल्याण और समग्र विकास की वह इस बजट में झलकती है। यह बजट सब वर्गों के लिए, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे महिला वर्ग हो , चाहे नौजवान वर्ग हो और चाहे व्यापारी वर्ग हो, सब वर्गों के लिए यह बजट पेश हुआ है और इसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया है । कुछ मेरे दोस्तों को छोड़ करके सारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, चाहे किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला वर्ग हो और चाहे नौजवान वर्ग हो सबने इस बजट को सराहा है। ...(व्यवधान) ...कुछ लोगों को छोड़ करके, क्योंकि इनकी मजबूरी है, अन्दर से यह कहते हैं कि हमें 7 0लाख रूपये मिल गया है बहुत खुशी की बात है, आप इसको एक करोड़ रूपये कर दो।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

24.03.2015/1510/यूके/जेटी/1

श्री कुलदीप कुमार---जारी

बहुत खुशी की बात है । आप एक करोड़ कर दो । अन्दर से खुश हैं । लेकिन मजबूरी में ये विरोध कर रहे हैं । इनकी भी मजबूरी है । हालात जो प्रदेश के आप छोड़ कर गए थे । आपके ही पिछले 5 साल थे । (व्यवधान) नहीं मैं तो किताब से ही ले रहा हूं, उसमें हालात ये हैं कि 100 पैसे में से सैलरी में 29.23 पैसे चले जाते हैं । पेंशन में 14.26 पैसे चले जाते हैं, इन्टरस्ट में 10.43 पैसे चले जाते हैं, लोन की रिपेमेंट 5.30 पैसे निकल जाते हैं और बाकी जो बचा, 40.80 पैसा केवल विकास के लिए रहता है । यह हालत है आज हमारी आर्थिक पोजीशन की । उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना बढ़िया बजट पेश किया है । मैने पहली दफा देखा है कि विपक्ष के पास

कोई मुद्दा नहीं रहा। इनकी कोई सॉलिड आलोचना नहीं है ! इनको आलोचना करने को कुछ नहीं मिला । केवल आलोचना के लिए आलोचना इन्होंने की है । कभी बिंदल जी पिछले बजटों के ऊपर बोलते रहे। वर्ष 2013-14 और 2014-15 पर बोलते रहे। जब कि बहस बजट 2015-16 पर हो रही है। लेकिन वे पिछले बजटों के ऊपर बोलते रहे। कोई बोलता रहा कि आंकड़ों में गलती हो गयी है, कोई कहता है कि क्लैरिकल मिसटेक हो गयी है या कोई टाईपिंग मिसटेक हो गयी। वह आलोचना हुई है। कोई सॉलिड आलोचना विपक्ष की ओर से नहीं आयी और मैं तो यह कहूंगा कि विपक्ष इस बार चारों खाने चित्त हुआ है। इनके पास कोई भी (व्यवधान) आपका धन्यवाद । यहां पर शेरो-शायरी बड़ी हुई है। माननीय धीमान साहब जी भी शेरो-शायरी कर रहे थे। तो मैं भी कुछ बोल देता हूं। कहते हैंः-

24.03.2015/1510/यूके/जेटी/2

माना कि हम आसमान नहीं छू सके।
लेकिन मुख्य मंत्री ने गरीब किसान-बागवानों का मन जरूर छू लिया है।(व्यवधान) यह मेरा है।

Deputy Speaker: Ravinder Ji, please do not interrupt. Let him speak. Please keep quiet.
(व्यवधान)
श्री कुलदीप कुमारः इन्होंने अपना बनाया है, तो मैने भी अपना बनाया है।

माननीय आई0डी0 धीमान जी अभी अभी बोल कर गए । ये बुजुर्ग हैं, हम इनका मान-सम्मान करते हैं। इनकी बातों को हम कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनका मान-सम्मान करते हैं, जो इन्होंने बोला। लेकिन मेरे भाई रणधीर जी बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जोर-शोर से कहा और एक बात तो मानने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं। इन्होंनें यही तो ट्रेनिंग ली है। पता नहीं नागपुर से ली है या नागपुर में सिखाया गया है। भाषण इनका बहुत बढ़िया होता है और भाषण दे कर ठगने में ये बड़े माहिर हैं। ऊपर से ले कर नीचे तक

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.03.2015/1515/sls-jt-1

श्री कुलदीप कुमार...जारीः
पिछले लोक सभा इलैक्शन्ज में इन्होंने भाषणों से ही हिंदुस्तान को ठग लिया। रणधीर जी भी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। यह भी चर्चा कर रहे थे। यह सही बात है कि ये प्रवक्ता ज़रूर अच्छे हैं, झूठ बोलने में एक बार भी नहीं सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूं।...(व्यवधान).. .मैं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि यह बजट निराशाजनक है, प्रदेश अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। इन्होंने बजट नहीं पढ़ा होगा। इसमें लिखा है कि ...(व्यवधान).. .आप चुप रहें।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया बीच में न टोकें। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। इनको अपनी बात रखने दें।

श्री कुलदीप कुमार : हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा दर 32 प्रतिशत हुआ करती थी वह आज लगभग 83 प्रतिशत हो चुकी है। क्या यह तरक्की नहीं है? अभी सबने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 1,04, 943रुपये हो गई है जबकि नेशनल लेवल पर यह 85, 500के लगभग है। क्या यह तरक्की नहीं है? हिमाचल प्रदेश का गरीबी स्तर जो 36.80 प्रतिशत् हुआ करता था अब वह 8.5 प्रतिशत् रह गया है। क्या यह तरक्की नहीं है? इसी बजट में लिखा है कि वर्ष 2014-15 में राजस्व अधिशेष 1.61 प्रतिशत् अनुमानित था वह 2015-16 में 0.04 प्रतिशत् रह जाएगा। वर्ष 2014-15 में राजस्व का सकल घरेलु घाटा जो 4.01 प्रतिशत् था वह इस वर्ष 2.91 प्रतिशत् रह जाएगा। क्या यह तरक्की नहीं है? आप कहते हैं कि प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। आज हिमाचल प्रदेश ने जितनी तरक्की की है ,वह कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकारों की ही देन है। माननीय मुख्य मंत्री जी का तजुर्बा सरकार चलाने का है और आपका अपोजीशन का है। आप उसी के लायक हैं। मुख्य मंत्री जी के तजुर्बे से हिमाचल प्रदेश आज लाभ उठा रहा है। यह बजट सभी वर्गों के हित में है लेकिन खासकर के किसानों और बागवानों का इसमें ज्यादा ख़याल रखा गया है। ...(व्यवधान).. .आपको किसानों का क्या ख़याल होगा? मैं जानता हूं कि आप भी गावों से आते हैं फिर भी आप किसानों को भूल जाते हैं।

24.03.2015/1515/sls-jt-2

हमारे प्रदेश में 90 प्रतिशत् किसान हैं और यह किसानों का प्रदेश है। जो ज्यादातर किसानों का हित करेगा वही हिमाचल प्रदेश का हित करेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी हर बार मन की बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई बात नज़र नहीं आई। अभी पीछे किसानों के साथ मन की बात हुई।

जारी...गर्ग जी

24/03/2015/1520/RG/JT/1

श्री कुलदीप कुमार--------क्रमागत
मन की बात किसानों के साथ हुई और रेडियो पर ही बात होती है, लेकिन प्रैक्टिली इम्पलीमेंटेशन जीरा है। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश कि किसानों की मन की बात को और उनके मन की पीड़ा को समझा है। इसलिए यह किसानों के हित का बजट बनाया है। आज हर खेत को पानी देने के लिए 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' बनाई गई है जिसमें 154 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें 8500 हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी जिससे 14,000 किसानों को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त कृषि का 4 50करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और 268 करोड़ रुपये इसमें बागवानी विभाग का बजट भी रखा गया है। लिफ्ट इरीगेशन एवं प्राइवेट बोर वैल लगाने के लिए आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50% सबसिडी का भी प्रावधान किया है। छोटे-छोटे पहाड़ी इलाकों, आपका भी पहाड़ी इलाका है और मेरा भी पहाड़ी इलाका है ,इनमें लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्ज के लिए यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा और जो किसान लोग बोरवैल कराना चाहते हैं उनके लिए यह सुविधा बहुत फायदेमंद रहेगी। जब यह स्कीम शुरू होगी इसका फायदा लेने के लिए आज किसान उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो इरीगेशन की पोटैन्शियल है ,वह 1,62,335 हैक्टेयर जमीन को इरीगेशन के अण्डर लाने की है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है ताकि भिन्न-भिन्न विभागों से जो सिंचाई के काम होते हैं वे सैन्ट्रलाइज हो जाएं और ज्यादा-से-ज्यादा किसानों की जमीन सिंचाई में आ जाए। यह भी किसानों के हित की बात है। लेकिन आप इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त Soil Health Services ऑन लाईन शुरू की है जो स्वायल टैस्ट करने के लिए है और

इसके लिए Mobile Soil Testing Laboratories स्थापित की जा रही हैं। इसमें लगभग एक लाख हैल्थ काड्र्ज बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा 'डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना' आरम्भ की है जिसमें पॉली हॉऊसिज बनाने के लिए 85प्रतिशत उपदान का प्रावधान किया गया है। इसमें 10 हाई टैक पॉली हॉऊसिज बनाने का प्रावधान किया गया है। यह भी किसानों के हित की बात है। आप क्या जानें कि किसान क्या होते हैं? आप इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, फ्लॉरीकल्चर का प्रोफैशन जिन लोगों ने अपना रखा है। उन्हें मार्केटिंग के लिए अपना माल दिल्ली या चण्डीगढ़ भेजना पड़ता है उसमें फ्लॉरीकल्चर का जो किराया लगता था उसको भी आधा कर दिया गया है। यह भी

24/03/2015/1520/RG/JT/2

किसानों के हित की बात है। लेकिन आपको तो सिर्फ इस बजट का विरोध ही करना है। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'मुख्य मंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' चालू की है जिसमें यदि किसी किसान या खेतीहर मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए डेढ़ लाख रुपये का इन्तजाम किया गया है और आंशिक स्थाई अपंग होने पर प्रभावित को 50,000/-रुपये का इन्तजाम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशु-पालन विभाग में 313 करोड़ रुपये का इन्तजाम किया है। आप तो गऊ को माता समझते हैं, आप क्या सारे ही माता समझते हैं। लेकिन आप उसके नाम पर राजनीतिकरण करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 'गोवंश सम्वर्द्धन बोर्ड' गठित करने का फैसला लिया है। यह भी किसानों के हित की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा से गांव के एक गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठता था और वह लोगों की रोटी रोजी का साधन हुआ करता था। लेकिन केन्द्र की सरकार ने उसका बजट 670 करोड़ रुपये से घटाकर 355करोड़ कर दिया है। इसको चलाने के लिए मुश्किल आ रही थी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें जो 40 प्रतिशत मैटीरियकल कम्पोनेंट का था इसको हल करने के लिए लगभग 20

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि स्कीमों को पूरा किया जा सके।----------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1525/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----------

उसको भी हल करने के लिए लगभग 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ताकि जो स्कीमें हैं, उनको पूरा किया जा सके। इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजनाओं के अन्तर्गत जो पिछले साल 6021 घर स्वीकृत हुए थे, अब 10,000 घरों का प्रावधान किया गया है। यह भी गरीब लोगों के लिए मुख्य मंत्री जी ने अच्छा काम किया है।

इससे भी बढ़िया काम आपको बताते हैं लेकिन आप अच्छी बातें नहीं सुनते, बुरी बातें सुनते हैं। जो बी0पी0एल0 की शिकायतें किया करते थे कि बी0पी0एल0 की सूची में गलत लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया ,उस वजह से आपको भी परेशानी थी और हमें भी परेशानी थी। अब एस0डी0एम0 को पावर्ज दे दी हैं कि अगर बी0पी0एल0 सूची में गलत आदमी का नाम दर्ज हो जाता है तो उसको एस0डी0एम0 डिलीट कर सकता है। आप लोग अच्छे काम के लिए तो धन्यवाद कर दिया करो।

इसके बाद व्यापारियों के भी भले की बात है। जो व्यापारियों को पहले 5 लाख रूपये तक टैक्स रिबेट था अब वह बढ़ाकर 8 लाख रूपये कर दिया गया है। उसके बाद 25 लाख रूपये तक जिन व्यापारियों की टर्नओवर है, उनको भी दो लाख रूपये का इन्श्योरेंस कवर दिया गया है। यह व्यापारियों के फायदे की बात है। उसका भी आप धन्यवाद नहीं करते।

नौजवानों के लिए (व्यवधान) इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया है। एक 'कौशल विकास निगम' बनाने की बात कही गई है और इसके अलावा 10 मॉर्डन आई0टी0आई0 भी प्रदेश में खोलने की बात कही गई है। युवा मण्डलों को 18,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई ट्राइबल में या पिछड़ी पंचायतों में आई0टी0आई0 खोलता है तो उसको लीज पर जगह देने का

प्रावधान किया गया है और उसके बाद भवन बनाने के लिए भी 10लाख रूपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह भी आपके फायदे की बात है। इसके साथ-साथ जितने सामाजिक सुरक्षा पैंशन के मामले हैं। जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसके लिए 1503 करोड़ रूपये बजट प्रावधान किया गया है। आज उसमें3 ,04, 921लोगों को पैंशन मिल रही है और जितने अप्रैल,

24/03/2015/1525/MS/AG/2

2015से ऐसे लम्बित केसिज हैं, जो योग्य हैं, उनको पैंशन देने का फैसला किया गया है। इसके साथ-साथ जो 80 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनकी पैंशन को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1100रूपये किया गया है। इसी तरह से जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन 550रूपये मिलती थी उसको 600 रूपये कर दिया है। आप इसकी भी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आपने तो विरोध करना है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनका कोई सहारा नहीं है तो यह उनको भी सहारा देने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया है। जो 70 प्रतिशत परमानैंट अपंग है उनको भी 1100रूपये पैंशन कर दी है। जो मानसिक रूप से अक्षम लोग हैं। आपको पता है कि ऊना में एक प्रेम आश्रम है। वहां पर वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इसकी 30 की क्षमता को बढ़ाकर 50 किया है और जो 3000 रूपये हरेक बच्चे को मिलता था ,अब उसको 4500 रूपये कर दिया गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से दिहाड़ीदारों को जो 170 रूपया दिहाड़ी दी जा रही थी, उसको 180 रूपया कर दिया है। इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और वाटर कैरियर के मानदेय को भी बढ़ाया गया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

4.03.2015/1530/जेके/एजी/1

श्री कुलदीप कुमारः----जारी-------

यह सारे का सारा बजट माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो 18 बजट पेश किये गये हैं उनका जो यह तुजुर्बा है उसके मुताबिक हर वर्ग का, चाहे गरीब हो, मज़दूर हो, व्यापारी हो, नौज़वान हो और चाहे महिला वर्ग हो सबके हितों का इस बजट में

ख्याल रखा गया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया और शानदार बजट पेश किया। धन्यवाद, जय-हिन्द।

4.03.2015/1530/जेके/एजी/2

उपाध्यक्षः अब श्री हंस राज, माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राजः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 18 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट अनुमान पेश किये हैं उनमें चर्चा करने के लिए आपने समय दिया आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मात्र पांच मिनट ही लूंगा। बजट अनुमान की पुस्तिका को जब मैं शुरूआत में ही पहले पन्ने को पढ़ता हूं तो वहीं से शंका और संशय होता है कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं? वह एक ही पैरे में नज़र आ जाता है- मेरी सरकार ने दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तथा इन दो वर्षों में हमारी उपलब्धियां और आगे तीन-चार शब्द शब्दकोषों से चुन-चुन कर इसमें समाहित किए गए हैं। उन पर ही मैं दो-चार शब्द बोल करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। क्षेत्र, धर्म, जाति एवं मत से ऊपर उठ कर राज्य के समग्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम सर्व कल्याण और समग्र विकास की कामना करते हैं। जब मैं चुराह की तरफ देखता हूं और सिरमौर की तरफ देखता हूं तब अफसोस होता है। सभी ने कहा कि राजा साहब ने, महाराजा साहब ने 18वीं बार और 18 तारीख को बजट पेश किया। उसके लिए सभी ने बधाईयां दी और मैं भी इनको बधाईय देता हूं। पूरे चुराह की तरफ से बधाई देता हूं। उसी दिन जिस दिन बजट पेश हुआ चुराह के लोगों के फोन आने शुरू हुए कि आपने हमें दो सालों से ठगा हुआ है। वह भी सच्चे हैं। उन्होंने वोट तो मुझे ही दिए हुए हैं। वे कहते हैं कि आपने हमें सवा दो सालों से ठगा हुआ है। तीसरा बजट जब भी आएगा मुख्य मंत्री जी,उनके मंत्रिगण या उनके पूर्व में जो विधायक रहे, अलग-अलग जगह भाषणों और जन सभाओं में ये चीजें बोलते हैं कि आज तक जितना भी विकास किया है वह सारे का सारा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसका श्रेय मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को देता हूं। इन्होंने जितना भी विकास किया है क्योंकि बाकी सरकारें तो रही ही नहीं हैं।

इसमें मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। विकास का लैवल देखो। किस तरह का विकास आप लोग करते हैं? दो-चार स्पष्ट आंकड़ें मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें ही पता

4.03.2015/1530/जेके/एजी/2

लग जाएगा कि विकास किस तरह का होता है और पिछड़े इलाकों को किस तरह से विकास में आप लोग या आपकी सरकारें शामिल करती है वह एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षा से ही शरूआत करते हैं। विभिन्न चुनाव आते हैं। सभी नेताओं का जज़बाती तौर पर फर्ज़ बनता है या स्वार्थीपन से हमारा फर्ज़ बनता है कि हमें वोटें पड़े और हम जीत करके आगे बढ़ें। लेकिन इतना भी क्या स्वार्थ कि आप 60- 70 सालों से और माननीय मुख्य मंत्री जी इतने सालों से सत्ता में हैं। हम तो बचपन में सुना करते थे कि माननीय वीरभद्र सिंह जी बड़े सालों से सत्ता में हैं। वे पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को समझते हैं। समझने का तरीका देखिए। स्कूलों को खोला गया हमने इसका स्वागत किया। लेकिन इसके लिए मैं अलग से प्रार्थना करता हूं और इस पर यह चीज़ बोलना चाहूंगा कि पूर्व की सरकारों ने जो स्कूल खोलने चाहिए थे, जिन-जिन गांवों में, जिन-जिन पंचायतों में उनको क्यों नहीं खोला गया? एक हमारी देवीकोठी पंचायत है उसका लड्डुन गांव है उसका केस हाई कोर्ट में चला हुआ है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

24.03.2015/1535/SS-AG/1

श्री हंस राज क्रमागतः

उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तीन-चार गांव के बच्चे चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर से आते हैं। जनवास पंचायत है, दो पंचायतें वहां कवर होती हैं, हाई स्कूल की ज़रूरत है, वह हमें नहीं मिल रहा। इससे सीधा ही स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग मत से उठ करके सम्पूर्ण राज्य का विकास करेंगे। धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पर नहीं। अब धर्म ,जाति और साम्प्रदायिकता क्या है? जब सैंटर के चुनाव थे तो आपके सभी लीडर लोग साम्प्रदायिकता को परिभाषित करने में जुटे थे और आज भी जुटते हैं। मैं इस पर सिर्फ इतनी ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि साम्प्रदायिकता

और जातिवाद क्या है? साम्प्रदायिता, हर धर्म को आप लोगों ने संरक्षण कैसे दिया है, उसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। एक बीवी नाम की औरत है झूरी गांव से। पंचायत चरड़ा है। वह गुज्जर समुदाय से है और मुसलमान है। उसकी बेटी पिछले दो महीने से गायब है। वह एस0पी0, एडिशनल एस0पी0, पुलिस थाना सब के चक्कर लगा चुकी है लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली है क्योंकि वह बेचारी गुज्जर है ,मोहम्डन है। दलितों के साथ क्या किया है इसका भी मैं थोड़ा-सा उदाहरण आपको दे दूंगा। पी0टी0ए0 पर भतियां हुईं, पैरा लगे। अभी एस0एम0सी0 में भर्तियां हो रही हैं। चाहे वे एस0सी0, एस0टी0 या ओ0बी0सी0 हों कहीं पर रोस्टर लागू नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का रोस्टर लागू किया ही नहीं गया। भर्तियां टैम्पोरेरी बेसिज़ पर होती हैं और बाद में आप लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए उनको रेगुलर कर देते हैं। हमें एक षड़यंत्र लगता है। विशेषकर जब-जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तब-तब आप लोग मैं सीधे-सीधे आरोप लगा रहा हूं कि जितनी भी आजकल एस0एम0सी0 पर भर्तियां हुई हैं या पीछे भी भर्तियां हुई हैं, जिन अध्यापकों को पी0टी0ए0, एस0एम0सी0 या पैरा टीचर आधार पर रेगुलर किया गया है उसमें कोई रोस्टर लागू नहीं हुआ। षड़यंत्र के तहत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ0बी0सी0 के बेरोजगार युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का हाल देखिये। आज ही मेरा प्रश्न था। अतारांकित प्रश्न लगा हुआ था कि प्रदेश में कितने एफ0आर0यू0 हैं। 47 पंचायतें हैं। मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से आग्रह किया कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक एफ0आर0यू0 है। मामूली-सी चोट लगे तो 100 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता

24.03.2015/1535/SS-AG/2

है। मुझे स्वयं और मेरे बच्चों को 100 किलोमीटर दूर चम्बा में आना पड़ता है। विधायक को तो छोड़िये लेकिन आम जनता का भी ध्यान रखिये। इसीलिए हमने बोला था कि हर विधान सभा क्षेत्र में एफ0आर0यू0 है तो चुराह में क्यों नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस तरह के विचार में विश्वास करते हैं। क्षेत्रवाद की आपकी परिभाषा क्या है? क्षेत्रवाद को आप कैसे परिभाषित करोगे? पी0एच0सी0 ऐसी कोई नहीं है। भेज तो देते हैं वह पी0जी0 के लिए जा रहा है, वह

पी0जी0 के लिए जा रही है। अभी ज्वाइन नहीं किया होता, पीछे से डाक पहुंच जाती है कि अब पी0जी0 के लिए चलो। इस बजट में वे भी चीज़ें नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य को तो आप ले ही लीजिए। हमारे वहां पर डेली की ओ0पी0डी0 लगभग 500-600 है। गायनी मतलब स्वस्थ महिला और डिलीवरी की बातें करते हैं कि हम लोग घरद्वार पर सब व्यवस्थाएं देंगे। अब एक औरत मेरे मनसा गांव से तीसा के लिए आयेगी उसको 26 किलोमीटर आना पड़ेगा। बीच में 6-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। एक प्रेगनेट महिला को आप कैसे लाओगे? ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल में कोई हैली सुविधा पैदा की जाए, अगर आप लोग अन्य व्यवस्था नहीं कर सकते। आप लोगों ने किस तरह से उस इलाके का शोषण किया है वह चुराह का इतिहास मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूं। 70-80 के दशक का इतिहास आप निकाल कर देखिये, कभी चुराह क्षेत्र जे0एंड0के0, अफ़गानिस्तान और पांगी को अनाज सप्लाई करता था। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि पांगी की 16 पंचायतों में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क नहीं है। सिर्फ तीन गांव छोड़कर, एक फिंडरू, वह भी जुड़ रहा है पुल बन रहा है। एक तिनी गांव है जहां पर सड़क नहीं है बाकी हर जगह सड़क है। लेकिन चुराह की 9 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर सड़क का नामोनिशान ही नहीं है।

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1540/केएस/एजी/1

श्री हंस राज जारी---

चुराह की 9 पंचायतें ऐसी है जहां पर सड़क का नामो-निशान ही नहीं है। इस तरह का बजट आपकी सरकार ने 18 बार पेश किया है। आप लोगों को मुबारक हैं। मैं चुराह की जनता की तरफ से भी मुबारक देता हूं कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया हुआ है कि जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, चाहे वह सिरमौर हो या चम्बा हो आप लोग उसको पिछड़ा ही रखेंगें।

उपाध्यक्ष जी, कल मैडम आशा जी ने इस माननीय सदन में बहुत अच्छा भाषण दिया और दिल्ली लैवल की बातें की। जिनको अपने चम्बा का पता नहीं है

और बातें दिल्ली की करें तो यह भी चम्बा के लोगों के साथ अन्याय है। अपने चम्बा में हम बस स्टैंड नहीं दे सकते और गायनी एक्सपर्ट पकड़-पकड़ कर लाया जाता है। भेड्डू फार्म हमें मिला था क्योंकि अनुसूचित जनजाति के हम लोग हैं, भेड़-बकरियां पालने वाले लोग हैं, वहां एक इंस्टीट्यूशन देते हैं तो दूसरा उठा लेते हैं। इस तरह का रवैया आपकी सरकार ने चम्बा के प्रति रखा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़कर मुझे इस बात की हैरानी होती है कि कांग्रेस सरकार का प्रदेश के प्रति कोई विज़न नहीं है। न तो शिक्षा के सम्बंध में, न पर्यटन के सम्बंध में । हम आगामी 10-15 सालों के लिए अपनी आने वाली बेरोज़गार पीढ़ियों के लिए क्या विज़न रखते हैं, वह नज़र नहीं आता है। सिर्फ हम लोग पिछले बजट की किताबों को उठाते हैं उसमें कुछ डाटा ऐड करते हैं और कुछ डीलीट करते हैं और ऐड और डीलीट भी होता है जहां पर मंत्री चाहते हैं, ऑफिसर लोग चाहते

24.03.2015/1540/केएस/एजी/2

हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी चाहते हैं। अगर ऐड ही करना है तो ऐसे क्षेत्रों को करो जो कभी ऐड हुआ ही नहीं। मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा है, लिखूं क्या? मैंने एक भी शब्द नहीं पढ़ा है, पढ़ूं क्यों? ऐसा तो इस बजट में है ही नहीं कि उसको पढ़ा जाए और उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। आप लोगों ने कहा कि आपका काम है क्रिटिसिज्म करना पर आपकी भी ऐसी मजबूरी नहीं है कि किसी बेतूकी बात का समर्थन कर दो। ऐसा है कि वफादारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए परन्तु अंधविश्वास वाली निष्ठा नहीं होनी चाहिए। कल मैं मैडम आशा जी को सुन रहा था, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, ये बहुत इंटैलिजैंट हैं, पूरे चम्बा में एक तरीके से इनका ही नाम चलता है परन्तु जब कल इन्होंने भाषण दिया तो मुझे रात को सोते-सोते भी इनके भाषण के ख्वाब आते रहे कि इन्होंने क्या भाषण दिया? एक सीनियर महिला और एक उत्कृष्ट महिला, चम्बा तो चलो बैकवर्ड है परन्तु मैडम तो बैकवर्ड नहीं है क्योंकि ये दिल्ली में रहती हैं। माननीय भरमौरी जी भरमौर से हैं, जनजातीय क्षेत्र से हैं और मेरा क्षेत्र भी लगभग ऐसा ही है भले ही मेरे क्षेत्र को कांग्रेस ने जनजातिय क्षेत्र घोषित नहीं करवाया लेकिन ये भी कल चुप रहे। इस तरह का अपमान चम्बा का चम्बा के ही लोग कर रहे हैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। अपने दर्द को आप बयां

नहीं कर सकते लेकिन दूसरों पर छींटाकशी करते रहते हैं। ऐसा है, कि मलाई वहां पर लगाओ जहां पर कुछ उम्मीद हो। अब जो बीत गई सो बात गई। ढाई साल तो हो गए, अब आप क्या मंत्री बनेंगी? अब मलाइयां लगानी छोड़ दो क्योंकि अब हिमाचल की जनता आपको रिजैक्ट करने वाली है। बाकी जगह तो आप रिजैक्ट हो ही गए हैं ।

24.03.2015/1540/केएस/एजी/3

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे किसी भी बात का कोई खंडन नहीं करना है। किसी भी आंकड़े में नहीं जाना है क्योंकि हम अबोध लोग हैं हमें पता नहीं लगता। हम बैकवर्ड लोग हैं, हमें बैकवर्ड का दर्जा मिला हुआ है। हमारी 62 में से 52 पंचायतें बैकवर्ड में आती हैं। अंदाजा लगाओ यहां पर कौशल विकास भत्ते की बात की गई, कौशल कहां से लेंगें हम, आई.टी.आई. ही नहीं है और ये मॉडर्न आई.टी.आई. और पता नहीं कौन-कौन सी आई.टी.आई. की बात करते हैं। लोग पोलिटैक्निक इंस्टीट्यूशन्ज़ के लिए लड़ रहे हैं और हम आई.टी.आई. के लिए लड़ रहे हैं। लोग युनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम कॉलेज की बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हैं। यह आपका कौन सा क्षेत्रीय तरीका है? आप इस प्रदेश को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम तो समग्र विकास करते हैं और बिना किसी जाति, धर्म, द्वेषभाव के। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि आप लोगों ने पूरा जोर लगाया है, आप पी.टी.ए. वालों को रैगुलर कर देते हैं, एस.पी.ओज़. का, (स्पैशल पुलिस ऑफिसर)का कहीं जिक्र नहीं होता है। 1998 का कांड हुआ था, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हम लोग बचे कैसे?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.**3.2015/1545/ag/av/1**

श्री हंस राज जारी----------
मैं तो यह दुआ कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि हम लोग बचे कैसे हैं। मेरा घर बिल्कुल सीमान्त में है। माननीय भरमौरी जी को पता है,जहां कालावन-सतरुंडी में कांड हुआ था उसकी सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मैं रहता हूं। पिछली बार भी ऐसी शिकायतें मिली थी। हमारे जो गद्दी-गुजर पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने बताया था

कि हमने फिर लोग देखें हैं। जम्मू-कश्मीर का बद्रवाह-भलेजा हमारे साथ लगता एरिया है। थोड़ा ही डिसटैंस हैं, हम उसको तीन घंटे में क्रोस कर जाते हैं या तीन घंटे में वे लोग आ सकते हैं। मैंने एस.पी.ओज. के लिए एक प्रश्न लगाया था कि उनके पास पता नहीं किस जमाने की, मुझे लगता है कि अंग्रेजों के टाइम की राइफलें हैं। आप अगर उन्हें ऐक्सपीरियंस के लिए ले जाएं या उनसे फायरिंग के लिए जाएं तो पता नहीं वह उल्टी चल पड़े। ऐसी तो उनको राइफलें देकर रखी है। दूसरा अन्याय उन पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ यह है कि वे सभी मैक्सिमम दसवीं और बारहवीं पास हैं मगर उनके रेगुलेराइजेशन की बात नहीं होती क्योंकि एस.पी.ओज. केवल चम्बा में हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी उनकी बात नहीं करते। क्या यही समग्र विकास है? माननीय भरमौरी जी, क्या यही पूरे प्रदेश का विकास है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस को चेताना चाहता हूं। हमने व्यक्तिगत कटाक्ष बहुत कर लिए, अब हमें चम्बा के लिए कुछ करना होगा। आप वहां से इनस्टिच्यूशन मत लो। आप तो यह कर रहे हैं कि चुराह डिविजन ऐट सलूणी, फलां डिविजन ऐट सलूणी। ऐट जरूर लग जाता है, वहां उसको टिकने नहीं देते। पहले हम समझ सकते थे क्योंकि सभी लोग, हमारे आई.पी.एच. का सब डिविजन, फॉरैस्ट का, लोक निर्माण विभाग का और बी.एस.एन.एल. की जो एक ऐक्सचेंज थी उसको भी सुरग्वाणी में शिफ्ट किया हुआ है। अब ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया ,मैं आपका ऋणी हूं। लास्ट में सिर्फ इतनी ही बात करुंगा कि मैं बजट की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं बजट को अपने आधार पर,

24.3.2015/1545/ag/av/2

एक विधायक होने के नाते और चुराह जनता की तरफ से खारिज कर रहा हूं क्योंकि चुराह के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई रिलीफ नहीं है।

आपने शिक्षा में तो ऐसा गोरखधन्धा चलाया हुआ है कि जो एस.एम.सी. ने भर दिया, वही ठीक है। एक केस ऐसा है, देखो, भाई-भतीजावाद हो तो वह आपकी तरह हो। जिस बंदे को आपने लगाना है वह चाहे पाताल में भी हो उसको आप लेकर ही आयेंगे। एक अशौकत अली है। वह कांग्रेस कमेटी का प्रैजिडैंट रहा है। प्यार हो तो ऐसा हो। पार्टी हो तो आपकी जैसी। वह बंदा दो जगह से तनख्वाह ले रहा है और वह

भी सरकारी महकमों से और वह थर्ड डिविजनर है। जिस बच्चे ने यहां हाई कोर्ट में केस किया हुआ है उसने सीधे-सीधे यह आरोप लगा रखे हैं। मगर वह दोनों ही कांग्रेसी थे मगर अब वह इधर आ गया है। वह जायें तो किधर जाएं, बेचारा। हुआ ऐसे हैं, ये सारे कागजात है, उपाध्यक्ष महोदय। इसमें लिखा हुआ है और इसमें दोनों अप्वाईंटमैंट लैटर लगे हुए हैं। वर्ष 2005 में कस्तुरबा गांधी होस्टल में उसको एक टीचर अप्वाईंट किया हुआ है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष जी, यह उन बेरोजगार लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह से तनख्वाह कैसे ले सकता है। पहले तो इसकी जांच की जाए। वह पहले ही एक जगह टीचर लगा हुआ है और उसको दूसरी जगह भी टी.जी.टी. लगा दिया है। वह व्यक्ति विशेष दोनों ही जगह से तनख्वाह भी ले रहा है। इस प्रकार की पारदर्शिता इस प्रदेश में चली हुई है। बाकी जो धांधलियां गिनाई हुई है तो मुझे सम्पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं कि आगे तो हमें समय मिलेगा नहीं जिनको लगा सकते हैं आप लगा दो। हमारा पूरे देश से

24.3.2015/1545/ag/av/3

कांग्रेस मुक्त सरकार का सपना पूरा हो रहा है और हिमाचल भी उससे अछूता नहीं रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप जैसे आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि आप पहले यहां थे नहीं।

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1550/negi/ag/1

श्री हंस राज ...जारी..

अध्यक्षः मैं सुन रहा था।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अत्याचार, अन्याय इस चुराह के साथ चल रहा है, वह चल रहा है। तो ऐसे अन्याय और अत्याचार के माहौल में, मैं इस विकास की दृष्टि से इस बजट अभिभाषण पर कोई भी कमैंट्स नहीं करता हूं, हम लोग इस बजट को बिल्कुल ही खारिज़ करते हैं। हम एक रिक्वैस्ट करेंगे दो हाथ जोड़ करके कि भगवान थोड़ी सी बौद्धिकता आपको भी दे और उस इलाके की तरफ आपका दृष्टिपात हो और जो-जो हमारी बड़ी कठिनाइयां हैं अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो भी सही रहेगा अगर नहीं देंगे तो भी ढ़ाई साल ही बचे हैं, धन्यवाद।

समाप्त

24.03.2015/1550/negi/ag/2

अध्यक्षः श्रीमती आशा कुमारी जी आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में तो नहीं थी मगर मैं इनका भाषण सुन रही थी। इन्होंने मेरा नाम लेकरके एक बात कही कि मैं दिल्ली की बातें कर रही थी, चम्बा के बारे में मुझे पता नही है। मैं दिल्ली में भी रहती हूं और चम्बा में भी रहती हूं लेकिन आप पता नहीं कहां रहते हैं। हंस राज जी आपको मालूम होना चाहिए कि चम्बा में बस स्टैंड का काम जोर-शोर से लगा हुआ है । ...(व्यवधान) ...बिल्कुल लगा हुआ है। जेल डिसमेंडल हो चुका है। जहां पर आदरणीय धूमल जी ने...(व्यवधान)... मुझे बोलने दीजिए। You let me speak. Speaker, Sir, you have asked me to speak. _____(व्यवधान)____

अध्यक्षः प्लीज़ सुनिए-सुनिए। ....(व्यवधान)...

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कह रही हूं इसको यह सुनने को तैयार नही हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस साईट पर धूमल जी ने शिलान्यास किया था उस साईट को, जेल को डिमॉलिश करने के आर्डरज़ अभी हाल ही में मुख्य मंत्री जी

वहां गए थे और उन्होंने दिए हैं। अब वह जेल डिमॉलिश हो गया है, उसी साईट पर बस स्टैंड बन रहा है। This is what I am saying. _____(interruption)___ Don't talk. You listen to what I am saying. नम्बर-2, आपने कहा कि एक इंस्टीट्युशन दी है, भेडू फार्म ले गए। आपकी सूचना इतनी गलत है, आपको मालूम होना चाहिए कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने ठाकुर सिंह भरमौरी जी के आग्रह पर उसी भेडू फार्म को रि-इस्टेबलिश करने के लिए बनौता में परमिशन दे दी है। ...(व्यवधान)...

श्री बी.के. चौहानः बनौता में तो 100 बीघे का फोरेस्ट लैंड है जिसमें नर्सरी लगी हुई है और 20 साल से वहां पर नर्सरी है। ...(व्यवधान) ....बड़े दरख्त तो खत्म हो गए

24.03.2015/1550/negi/ag/3

अब प्लांटेशन पर जाओ। ....(व्यवधान).... I know this is my Constituency. I have land my mind. लेकिन मैं बताऊंगा नहीं।

अध्यक्षः चौहान साहब, बैठ जाइये प्लीज।

श्री बी.के.चौहान : मैं समय आने पर ही बताऊंगा क्योंकि आप उसको भी अपना लेंगे। क्योंकि आप हर चीज़ में अपना नाम चलाते हैं। अब बस स्टैंड को हाईजैक करके कह रहे हैं कि यह हम बना रहे हैं। आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया है । मैं वहां पर था। ....(व्यवधान) ...उसके लिए आदरणीय धूमल जी के प्रयासों से 9 करोड़ रूपये एन.एच.पी.सी. ने दिया। आपका तो एक पैसा भी नहीं आया। आप हवा में क्या बातें करते हैं। ____(व्यवधान)__ठाकुर सिंह भरमौरी जी आप मेरा मुंह मत खुलवाइये। वरना मैं आज बहुत कुछ बोल दूंगा। ...(व्यवधान)... आप झूठ मत बोलिए।

अध्यक्षः आप चिन्ता क्यों कर रहे हो, सब कुछ चम्बा जिला में ही तो बन रहा है।
अब श्री नन्द लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

24.03.2015/1550/negi/ag/4

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो 18मार्च, 2015 को इस मान्य सदन में बजट एस्टीमेट्स प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस मान्य सदन में जो 18 वीं बार बजट पेश किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं अभी सुन रहा था कि जो 18वीं बार बजट पेश किया है उसके लिए भी लोग बधाई देते हैं। इसमें बधाई नहीं देंगे तो और क्या करेंगे ? हमें प्रदेश के अन्दर जो पिछले 2 सालों में विकास हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं है, वह जग ज़ाहिर है, पूरा हिमाचल जानता है। डिवलपमैन्ट की हर सेक्टर में, विशेषकर कोर सेक्टर में जो विकास हुआ है, चाहे एजुकेशन की बात करो,...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

24.03.2015/1555/यूके/1

मुख्य संसदीय सचिव, श्री नन्द लाल---जारी

उसमें जो विकास हुआ है, चाहे ऐजुकेशन की बात करो, चाहे हैल्थ की बात हो या इंडस्ट्रीज़ की बात हो । ये जितने भी मामले हैं, इन पर अद्भुत विकास हुआ है, इसमे कोई दो राय नहीं है । और इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का अपना एक विवेक है, अपना एक लम्बा तुजुर्बा है और एक बढ़िया फाईनैंशियल मैनेजमैंट की वजह से जो बजट उन्होंने पेश किया है, इसमें इन्होंने एक ऐसी सोच रखी है कि every section of the society has been benefitted. But for our esteemed colleagues sitting on that side, it is a compulsion for them. They have to oppose; they have to criticize. अगर आप देखेंगे कि जब गवर्नर एड्रैस था, उसमें भी जो एक साल की अचीवमैंट मेंशन की गयी थी, उसमें इनको कहने को कुछ नहीं मिला । इन्होंने उसमें कांग्रेस के इलैक्शन मैनीफैस्टों का सहारा लिया गया a bundle of newspapers. मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल की अचीवमैंट्स है, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको पढ़ा । तो उसमें आपको देखना था कि what all has been done in the last one year. उसकी बजाय खाली न्यूज़ पेपर्स का सहारा लिया गया और हमारे जो इलैक्शन मैनीफैस्टो की बातें थीं वे पढ़ी गयी । ये जानते हुए कि इलैक्शन मैनीफैस्टो में जितनी भी कमिटमैंट्स हैं,

that are to be completed in five years. There are short term policies; there are long terms policies.

24.03.2015/1555/यूके/2

यह सब जानते हुए भी इस तरह की बात की गयी कि इसमें किए गए वायदे पूरे नहीं हुए अभी तक । अगर आप बी0जे0पी0 की प्रिवियस पीरियड की बात करें तो उसके फाईनैंशियल मैनजमैंट में अगर आप देखे तो it was a total failure. 13वें वित्तायोग के सामने जिस तरह से बात रखनी चाहिए थीं और सरकार को उससे जिस तरह से लॉस हुआ है. it is irreparable. मैं आपको बताना चाहूंगा कि बातें तो बहुत होती हैं । The 13th Finance Commission recommended an increase of 126 per cent growth over the 12th Finance Commission to other States, whereas Himachal got 50 per cent, the lowest in the country. यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ । क्या कोई दुश्मनी थी? That means it clearly shows that we could not take up the matter with the Central Government. फाईनैंस कमिशन के सामने हम अपनी बात नहीं रख सके । इसलिए जो कट लगा यह उसी का एक नतीजा है । इससे अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को 10725 करोड़ रूपए का फाईनैंशियल लॉस हुआ है । It is not a small amount. इस तरह से फाईनैंशियल मिसमैनेजमैंट की वजह से लॉयबिलिटी पाइलअप होती गयी और हमारे मुख्य मंत्री जी को हम एक बार फिर से बधाई देना चाहते हैं कि 14th Finance Commission है, उसमें इन्होंने अपनी बात इफैक्टिवली रखी । with facts and figures रखी और उसमें हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में एक रीज़नेबल इन्क्रीज़ जो मिला है, उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं ।

24.03.2015/1555/यूके/3

भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं । पिछले रिज़ीम में जो विकास था, उसमें प्रोपोगंडा बहुत रहा और उसके चलते हुए एक मिशन रिपीट की बात करते थे कि 2012 के इलैक्शन में Mission Repeat is going to be repeated. और क्या हुआ ? ये आप सभी जानते हैं । That is the reason you are sitting that side. और मैं आपको कि अभी दो साल में जो यहां विकास हुए हैं, माननीय मुख्य

मंत्री महोदय के नेतृत्व में, अभी सिर्फ सवा दो साल हुए हैं । बाकी जो remaining period of this term है, इसमें आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में चहुंमुखी विकास होगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है and I can assure you कि यदि इस तरह यह विकास चलता रहा और उस तरह का ऐटिट्यूड बना रहा तो जो अगले इलैक्शन होंगे उसमें भी the friends would be sitting on that side only. This I can say to you.

अध्यक्ष महोदय, आजकल डिबेट के अन्दर एक नया ट्रैंड चला हुआ है । क्या हो रहा है, यह जानते हुए भी कि we have to maintain certain norms here. एक सदन की गरिमा है, सब कुछ है, फिर भी हम बीच में इस तरह की बातें करते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.03.2015/1600/sls-jt-1

श्री नन्द लाल (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी

वैसे तो रिफ्रैशर कोर्स आप करवाते हैं। आपने करवाया भी है for the new comers last year. I personally feel कि इस तरह के कोर्स, they are beneficial for all of us, जिसमें हम सीखें कि how to maintain the norms. I am a new comer. This is my second term, but I can say कि कम-से-कम इस तरह के नार्मज के लिए, इस तरह के डैकोरम के लिए we should be trained. ताकि हम यहां की गरिमा को मेंटेन कर सकें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक बात और बीच में आ रही है कि हम केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं करते। जो भी हमें केंद्र सरकार से मिल रहा है, उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। मेरा इसमें यह कहना है कि हम ज़रूर धन्यवाद करेंगे और करते हैं। हम धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फैडरल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट्स का जो डैब्ट शेयर है, जो ग्रांट्स हैं, it is a Constitutional right of the State. उसको आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां से कोई तोहफ़ा नहीं मिल रहा है। It is not with Himachal only. यह सब स्टेट्स के साथ होता है। यह संवैधानिक अधिकार है। हम धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? हम धन्यवाद करेंगे अगर देश के

किसानों का भला सोचा जाए। कशमीर के अंदर मसरत अली खान को किस तरह रिहा किया गया? अगर उसको रोकें तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। जो कशमीर के अंदर अलायंस पार्टी है, उनकी जो स्टेटमैंट्स हैं immediately after taking over the reins there, इस तरह का जो रवैया है, हम चाहेंगे कि देश की national integrity के लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि कशमीर भारत का अभिन्न अंग है, उसमें the stand of the Government should be that Kashmir is the part of our country. उसमें हम उनका पूरा समर्थन करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे । So, this has to be checked. हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर यह काला धन वापिस आ जाए। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर यह अच्छे दिन वापिस आ जाएं और हमें जो 15-15 लाख रुपया मिलना है, वह मिल जाए। हम केंद्र

24.03.2015/1600/sls-jt-2

सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर सैंट्रली स्पाँसर्ड स्कीम्ज पर कट न लगे। वह फैडरल स्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखें, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। आज सुबह प्रश्न काल में जो चर्चा हो रही थी कि नैचुरल कैलेमिटीज में जो वहां से रिलीफ डिमांड किया है; चाहे स्नो फॉल की वजह से है, बाढ़ की वजह से है, पानी से रोड की खराबी की वजह से है, जितना भी हिमाचल के अंदर लॉस हुआ, असैस होने के बाद it is all with the Central Government. हम उनका धन्यवाद करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी वह रिलीफ मिल जाए ताकि हमारे लोगों के ऊपर जो आपदा आई है, उनको राहत मिले।

स्पीकर सर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐन्वल प्लॉन के साईज को इस बार 400 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4800 करोड़ रुपया किया गया है। इसमें शैड्यूल कॉस्ट सब प्लान में 12 09 करोड़ रुपये, ट्राईबल प्लॉन में 425 करोड़ रुपये और बैकवर्ड एरिया प्लॉन में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग का 2015 का जो स्टेक है, इसमें नेशनल सैंट्रल असिस्टैंस, स्पैशल सैंट्रल असिस्टैंस और जो स्पैशल प्लॉन असिस्टैंस है ,उसमें करीब-करीब 3000करोड़ रुपये का लॉस एक्सपैक्टिड है और आने वाले पांच साल के अंदर this would be nearly 15,000 to 20,000 crore. जो सैंट्रली स्पाँसर्ड स्कीम्ज हैं, इन पर तो कट लग ही गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी पैंशन में ,जिसकी बहुत से लोगों ने चर्चा की ,उसमें एक नोमिनल एनहांसमैंट की गई है depending upon the available resources with us. उसको बढ़ाकर 500 रुपये से 55 0रुपये किया है। जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनको 1000 रुपया मिलता है without any income limit. यह हमारे मुख्य मंत्री की बहुत बड़ी सोच है कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को यह फायदा मिल रहा है।

जारी ..गर्ग जी

24/03/2015/1605/RG/AG/1

श्री नन्द लाल(मुख्य संसदीय सचिव)--------क्रमागत
तो इस तरह से कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए जो पहले 48, 500रुपये मिला करते थे उसको बढ़ाकर 75,000/-रुपया किया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। इसके अतिरिक्त मकान की मरम्मत के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो 15,000/-रुपये सबसिडी दी जाती थी उसको बढ़ाकर 25,000/-रुपए किया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जो पहले ऐनुअल इनकम 20,000/-रुपये होती थी उसको बढ़ाकर 35,000/-रुपये किया गया है। इसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की ऐनुअल इनकम चार लाख, 50 हजार रुपये से बढ़ाकर छः लाख रुपये की गई है। डेली वेजिज को 150/-रुपये से बढ़ाकर 160/-रुपये किया गया है। पार्टटाईम वाटर कैरियर का मन्थली आनरेरियम 1,300/-रुपये से बढ़ाकर 1,500/-रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगाड्र्ज का जो आनरेरियम है, this has been enhanced from Rs. 260/- to Rs. 280/- per day. ये सारी बातें इकॉनॉमी से हटकर नहीं हैं। हमें इकॉनामी के साथ चलना पड़ता है। Nominal enhancement, whatever enhancement you are doing यह इकॉनामी के हिसाब से होती है, खाली कहने से नहीं होतीं।

अध्यक्ष महोदय, आज यहां शिक्षा पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। मुझे यह कहना है कि सबसे पहले तो we talk about Right to Education और शिक्षा के अधिकार की जब हम बात करते हैं ,how can we talk about closure of the schools. हमको स्कूल चालू रखने हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले भी अपने समय में दूरे-दराज़ के क्षेत्रों में जहां बच्चे कम भी थे वहां स्कूल का प्रावधान किया so that they have the Right to Education. वे पढ़ सकें। दूर-दराज़ के जो गांवों के लोग थे, देहात के लोग थे वहां बच्चों को शिक्षा मिल सके। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि स्कूल खोलने के जो नॉर्म्ज होते हैं ,distance from one school to other और दूसरा होता है कि number of students available. कई बार ये चीजें रिलैक्स करनी पड़ती हैं। आप सोचिए जैसा बिक्रम जी

24/03/2015/1605/RG/AG/2

कह रहे थे कि जो दूर-दराज की गुजर बस्तियां होती हैं वहां के जो लोग हैं ,गांव के लोग हैं उनको शिक्षा तो देनी है ,तो कई बार उन नॉर्म्ज को रिलैक्स करना पड़ता है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वे रिलैक्स किए और वहां स्कूल खोले। लेकिन पिछली सरकार के समय में क्या हुआ कि almost around 150 schools were closed. इन्होंने एक रैशनलाइजेशन की। जैसे लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं कि एक स्कूल में एक ही अध्यापक है या दो अध्यापक हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि है तो सही , We talk about the quality of education later. पहले तो होना चाहिए। मुझे स्कूल जाने का हक़ तो मिलना चाहिए। इसके लिए हम तो माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने नॉर्म्ज रिलैक्स करके जगह-जगह स्कूल खोले और सभी को पढ़ने का हक़ मिला।

अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग पी.टी.ए. या पैरा टीचर्स की बात करते हैं ,हम आज भी उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। वह, वे लोग हैं जिन्होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में बहत ही स्माल ऑनरेरियम के साथ बच्चों को पढ़ाया और स्कूलों को भी जिन्दा रखा ,बच्चों को पढ़ाई दी। आज हम इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन स्कूलों के जो पी.टी.ए. टीचर्स हैं उनको कॉमन कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया और पैरा टीचर्स को रैग्युलराज करने की बात हुई है। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इसलिए शिक्षा की जहां तक बात है, इसमें स्कूल खोलना, अभी जो

इस बजट में भी लिखा है कि क्वालिटी ऐजुकेशन के लिए, इसको न खोलने की बात कही। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जो हमारी पुरानी स्कीम है इसमें स्कूल खोले जाने चाहिए चाहे वे एस.एम.सी. के माध्यम से ही खोले जाएं। अभी एस.एम.सी. की भी काफी लोगों ने बात की। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू ताकि ये स्कूल चालू रहें और इसमें हमारी शिक्षा के स्तर को भी इंप्रूव किया जा सकता है। पद भरे जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सारे स्कूल भरे हुए थे। हमने भी धीमान साहब जो उस समय माननीय शिक्षा मंत्री थे, इनसे कई बार अनुरोध किया था क्योंकि हमारे स्कूलों में भी ऐसी हालत थी। There is nothing new in this. इसलिए इसमें ऐसा है कि with the passage of time जो भर्तियां हो रही हैं, पदोन्नतियां हो रही हैं ,इसके साथ-साथ सारे स्कूलों के पद भर जाएंगे। अभी एक स्कूल में एक टीचर तो है। In a primary School if there are five students तो अगर वहां एक

24/03/2015/1605/RG/AG/3

टीचर है, तो वह काम चला देगा। चाहते तो हम हैं कि स्कूलों में स्ट्रैन्थ पूरी दें ,but you know gradually this can be done.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकारी बसों में जाने के लिए फ्री ट्रैवल फैसिलिटी प्रदान की थी उसको अब केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों तक भी पहुंचा दिया है जिसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे।-----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1610/MS/Ag/1

श्री नन्द लाल जारी----------
अब थोड़ी विधायक निधि की बात करते हैं। विधायक लोगों को अपने चुनाव क्षेत्र के अन्दर काफी विकास के काम करने पड़ते हैं और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें भी होती हैं। जो उनको क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रूपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 70 लाख रूपये किया है। उसके लिए हम सब माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उसमें जो एक राइडर की बात कही गई है, उसमें हम भी अपने

आपको शामिल करते हैं कि यह राइडर हटाया जाए so that we are independent to do. You know जो विकास के कार्य हमें अपने क्षेत्र में करने हैं उसमें आप स्वतंत्र हो जाएं।

अब में खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। जो यहां पर खाद्य सुरक्षा बिल आया We are the second State in the country. जिसने इसको चालू किया। हमारे मुख्य मंत्री ने उससे पहले ही जो स्टेट सब्सिडी की स्कीम थी, यहां हिमाचल के अन्दर, जिसके अन्तर्गत तीन दालें, दो तेल और एक किलो आयोडाइज्ट सॉल्ट का प्रावधान तब भी था। यानी यह खाद्य सुरक्षा बिल से पहले भी था और आज भी उसको चालू किया है। उसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। कई बार ऐसा भी होता था कि जो राशन की स्टोरेज है, उसकी हालत अच्छी नहीं होती थी, उसकी वजह से बड़ी वेस्टेज होती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोदामों और वेयरहाउसिज के लिए 4 करोड़ रूपये अतिरिक्त फण्ड का प्रावधान किया है। वह भी एक सराहनीय कदम है।

यहां पर कानून-व्यवस्था के बारे में भी काफी चर्चा हुई। सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पुलिस अच्छा काम करे, क्राइम रेट कम हो और कत्ल न हो लेकिन फिर भी सबकुछ होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो पुलिस है, उसको चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए, उनको अच्छे टैक्निकल गैजेट्स दिए जाएं। अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और उनको अच्छा काम करने का मौका दिया जाए। उनके इंटेलीजैंस नैटवर्क को इम्प्रूव किया जाए ताकि इस पर चेक लग जाए, इसको कम किया जाए। हालांकि क्राइम फिर भी होते हैं।

मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। यह कहना कि उनके समय में यह हुआ, फलां के समय में हुआ। This is not the solution to the problem. यह

24/03/2015/1610/MS/Ag/2

सोल्यूशन नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे। मैं आपको आपके समय की बात बताना चाहूंगा कि हम लोग एक फंक्शन में थे। लवी मेले की क्लोजिंग सेरेमनी रामपुर बुशैहर के अन्दर थी। वहां पर रामपुर में पूरी सरकार और

पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उपस्थित था। जहां पर फंक्शन हो रहा था, उससे 50 मीटर दूर एक लड़के का कत्ल हो गया। इसका मतलब अब यह कहना कि उनके समय में ऐसा हुआ, उनके समय में वो हुआ, यह सोल्यूशन नहीं है। We need to check it. This has to be checked. Police people should be more alert. उसको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए और जो हमारा सिस्टम है, उसको और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए। जो यह दोषारोपण है and this is not the solution to the problem. तो मैं यह कहना चाहूंगा। इसमें क्राइम रेट को कम करने के लिए पुलिस को चुस्त-दुरूस्त होना चाहिए।

कृषि सैक्टर महत्वपूर्ण सैक्टर है। इसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बात मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही है, उसका भी हम स्वागत करते हैं और इसमें 150 करोड़ रूपये की जो सिंचाई योजना है, बहुत अच्छी चीज है। नैचुरल सी बात है जब सिंचाई अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस स्कीम के लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

जहां तक मोबाइल स्वाइल टैस्टिंग की बात है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जमीन में कौन सी फसल डालनी है, कब डालनी है और क्या खाद डालनी है उसके लिए we must know कि स्वाइल टैस्टिंग का सिस्टम क्या है। यह एक नया तरीका है। इसके लिए जो तीन और लेबोरेटरीज बनाई है, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नन्द लालः जो पॉलीहाउसिज के लिए सब्सिडी की बात है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसके लिए जो 30 करोड़ रूपये का आउटले रखा है, वह भी अच्छी बात है।

हॉर्टिकल्चर की बात यहां रोहित ठाकुर जी ने भी कही है। इसके लिए स्मॉल पीस ऑफ लैण्ड, जिसमें आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में इस तरह का

24/03/2015/1610/MS/Ag/3

एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें ऑलरैडी जो ग्रीन हाउस की सब्सिडी है और जो एंटी हेलनेट की सब्सिडी 80 प्रतिशत की है, वह तो चल रही है। अब एक अलग से 10 करोड़ रूपये का जो प्रावधान रखा है ,वह मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारी जो सेब की नई वैराइटी आएगी, पॉलीनाइजर आएंगे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

4.03.2015/1615/जेके/एजी/1

श्री नन्द लालः------जारी------

पॉलीनाईज़र आएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां पर मैं ट्रांसपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं। इसके बेड़े में बहुत ज्यादा बसें आ गई है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. 800 बसें अभी आनी है और 510 बसें उसके बाद आएगी। हिमाचल प्रदेश में पहले पुरानी फ्लीट थी। आए दिन यहां पर एक्सीडैंट्स हो रहे थे। गाड़ियां नहीं चल पा रही थी। यहां पर टूरिज्म के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रोपवेज़ अभी तीन-चार जगह बनाने की बात हुई है। सराहन में मेरे चुनाव क्षेत्र में वशलकांडा एक जगह है वहां पर रोप-वे का काम इसी साल शुरू होगा। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है और काम भी कम्पलीट हो जाएगा। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने हमारे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज ज्युरी में दिया है। उस कॉलेज को बनाने के लिए बजटरी प्रोविज़न भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि उसका जल्दी से जल्दी शिलान्यास किया जाए। एक डिग्री कॉलेज जो मेरे चुनाव क्षेत्र ननखड़ी में है उसका भी बजटरी प्रोविजन है। वहां पर लैंड भी चिन्हित् है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसका भी जल्दी से जल्दी शिलान्यास किया जाए। खराण में जो आई.टी.आई. है उसके लिए भी भूमि चिन्हित् हो चुकी है, उसका भी शिलान्यास किया जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट प्रस्ताव का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

4.03.2015/1615/जेके/एजी/2

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, बजट अनुमान वर्ष 2015-16 और जिस बारे में इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हूं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ नई योजनाएं लाँच करने की बात की है। कुछ पुरानी योजनाओं को थोड़ा-बहुत नया स्वरूप भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि कुल मिला कर यह बजट निराशाजनक है। यह बजट संतुलित नहीं है। इस बजट में लगता है कि केक कम है और आईसक्रीम ज्यादा है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में रोजगार पैदा करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज प्रदेश में लगभग साढ़े 11 लाख लोग बेरोजगार हैं। केवल 5 हजार बेरोजगार लोगों को नौकरी का वायदा किया गया है। अगर हम याद करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में कहा था कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। प्रदेश की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए, मंहगाई पर काबू लाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। फिज़ूलखर्ची को कम करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहां पर श्री रणधीर शर्मा जी ने ठीक कहा है लेकिन वे अभी यहां पर नहीं है। उन्होंने कहा कि फिज़ूलखर्ची बढ़ी है। मैं हाऊस के अन्दर की ही बात करना चाहूंगा कि कितने चेयरमैन, वाईस चेयरमैन बनाए गए हैं? कितने जनता द्वारा रिजैक्ट किए हुए पूर्व विधायक हैं, उनको सलाहाकार बनाया गया है? उनको केबिनैट स्टेटस दिया गया है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है? यह फिज़ूलखर्ची है I think it is an avoidable expenditure. माननीय वीरभद्र सिंह जी आप छः बार मुख्य मंत्री बने हैं। आपका इतना एक्सपीरियंस राजनीति में है जितनी हमारी उम्र है उतना एक्सपीरियंस है। क्या आपको किसी राजनीतिक सलाहाकार की जरूरत है? माननीय मुख्य मंत्री जी बाद में ऐसा न हो और आपको अपने इन सलाहाकारों को यह न बोलना पड़े कि आप भी डूबे सनम मुझे भी डुबा दिया। अब मैं कुछ ऐसी स्थिति देख रहा हूं। पर्यटन की

4.03.2015/1615/जेके/एजी/3

बात यहां पर की गई है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

24.03.2015/1620/SS-AG/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, कोयला उत्पादन पर राज्यों के लिए रायल्टी मिलती है तो हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और जलाधिकार के लिए क्यों हमें सैंटर की तरफ से मदद न मिले? आप इस कदम को उठाईये। यह मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। जैसा माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में गैर-टैक्स से होने वाली आमदनी लगातार कम हो रही है। यह चिन्ता का विषय है। सन् 2011-12 में 1915 करोड़ आपका गैर-टैक्स रेवेन्यू हुआ था जो घट करके 2014-15 में1379 करोड़ रुपये रह गया। यह चिन्ता का विषय है। इसका मतलब है कि प्रदेश की आय के साधन कम हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गर्व के साथ बार-बार कहा कि जहां दो बच्चे होंगे, हम वहां भी स्कूल खोलेंगे। क्या आपका वर्तमान आर्थिक ढांचा इसको मंजूर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा - हज़ारों ऐब ढूंढते हैं हम दूसरों में इस तरह। ऐसा शेर वगैरह बोला। माननीय मुख्य मंत्री जी हम आपमें ऐब नहीं ढूंढ रहे। हम मानते हैं कि जब सत्ता आती है तो सिर ऊंचा हो जाता है और जब सिर ऊंचा होता है तो जमीनी हकीकत नज़र नहीं आती। --(व्यवधान)—

मुख्य मंत्रीः मैंने कहा कि आप हमेशा मेरी नज़र में हैं।

श्री इन्द्र सिंहः धन्यवाद। हम आपको केवल इस बारे में आगाह करने जा रहे हैं। इस बजट के अनुमान में 3285 करोड़ वित्तीय घाटा दर्शाया गया है। कहां से पूरा करेंगे। कुछ नहीं बताया। 14वें वित्तायोग में 5 वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के हम आभारी हैं कि उन्होंने 42 हजार करोड़ रुपया प्रदेश को देना है। आपका हर साल 8500 करोड़ रुपया मिलेगा। उसकी मदद से एक प्रगतिशील बजट इस प्रदेश को दे सकते थे जो आपने नहीं दिया। आपने वित्तीय कुप्रबंधन के चलते एक लचर और दिशाहीन बजट प्रदेश को दिया है। अध्यक्ष महोदय ,इस साल सरकार ने क्या किया उसका आंकलन

आर्थिक सर्वेक्षण जो 2014-15 का है उसके इंडीकेटर्ज़ से मिलेगा। मैं कुछ इंडीकेटर्ज़ आपको देना चाहता हूं। एस0सी0 सब-प्लान में 1209 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया गया था। यह बात सुनने लायक है। माननीय मुख्य मंत्री जी, एस0सी0 सब-प्लान में 1209 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया गया था। 1108 करोड़ 40 लाख रुपया आबंटित हुआ। दिसम्बर तक 387 करोड़ खर्च हुआ। यानी केवल 35 परसैंट खर्च हुआ, अगले तीन महीनों में 65 परसैंट खर्च करेंगे। यह आपका कैसा

24.03.2015/1620/SS-AG/2

एडमिनिस्ट्रेशन है? स्वास्थ्य मंत्री जी, मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए आपने 6626.41 लाख रुपया दिया। उसमें से 2686 लाख रुपया खर्च हुआ। दिसम्बर तक 40 परसैंट खर्च हुआ। 60 परसैंट आपने तीन महीनों में खर्च करना है। वैसे ही आई0जी0एम0सी0 के लिए जो पैसा दिया, उसमें केवल 31 परसैंट खर्च किया। क्या 69 परसैंट तीन महीनों में खर्च कर देंगे? ये कहां की प्लानिंग है? स्किल डिवैल्पमैंट के लिए 100 करोड़ रुपया दिया और कुल खर्च 16करोड़ हुआ। 100करोड़ रुपया दिया लेकिन आपने एजुकेशन स्टैंडर्ड भी डाइल्यूट किया। प्लस-टू से मैट्रिक, मैट्रिक से 8^{th} क्लास, 8^{th} क्लास से कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कौशल विकास भत्ता लो। खर्च कितना हुआ 16 करोड़ और दिया कितना था 100 करोड़। Where do we stand? आप इस बात को सोचिये। मैडम, यहां पर नहीं हैं। मैं इरिगेशन की बात करूंगा। Most dismal display in irrigation. कमांड एरिया डिवैल्पमैंट के लिए 25 करोड़ रुपया दिया और एक करोड़ रुपया खर्च हुआ। आप अंदाजा लगाईये। लघु सिंचाई के लिए 12182 लाख दिया। 37 परसैंट खर्च हुआ।

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1625/केएस/जेटी/1

श्री इन्द्र सिंह जारी---

37प्रतिशत खर्च हुआ और मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3100 लाख दिया और दिसम्बर तक 9 लाख खर्च हुआ। यह क्या है? अगले तीन महीनों में क्या सारा खर्च कर देंगें? ऐसा ही बाढ़ नियंत्रण के लिए 33,927 लाख रु0 दिए और 49 प्रतिशत खर्च हुए। मैं कह रहा हूं कि अगले तीन महीनों में तो ठेकेदारों के मज़े ही मज़े हैं। क्या आप ऐसे ही पैसा खर्च देंगें without any planning; without any

control? जो मर्जी खर्च करो। यह कैसा संतुलित विकास है? शहरी पेयजल योजना के लिए 14 करोड़ रु0 का प्रावधान था जबकि 1 करोड़ 28 लाख रु0 खर्च हुए। What is this? यह क्या है? आप इस बात को सोचिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरशाही प्रदेश में top heavy हो रही है। आईडियल नौकरशाही होनी चाहिए like a pyramid structure, apex body and then पीरामिड के बेस पर वर्कर ज्यादा होने चाहिए। आपके वर्कर घट रहे हैं, आपका पिरामिड बेस बिल्कुल संकीर्ण होता जा रहा है। आप देखिए, आपका क्या हाल है? राज्य में कुल सरकारी नौकर दो लाख हैं जिनमें से 46 हजार पद खाली पड़े हैं। क्या एफिशियंसी है आपके एडमिनिस्ट्रेशन की वह आप जानें। शिक्षा में सबसे ज्यादा 18757 पद खाली हैं। स्वास्थ्य में 3847 पद खाली है, पुलिस में 2640, आई.पी.एच. में 1141 पद खाली है और इन्हीं विभागों में रिटायरमैंट्स भी ज्यादा है। Have you thought of this? How will you run the show? आप बिल्कुल बेस में जाएं, ग्राऊंड लैवल पर काम करने वाला किसी भी विभाग में आदमी नहीं है। आप आई.पी.एच. लें, पी.डब्ल्यू.डी. लें या बिजली विभाग

24.03.2015/1625/केएस/जेटी/2

लें। फ्यूज़ लगाने के लिए इलैक्ट्रीशियन नहीं है। आप कहते हैं कि संतुलित विकास हुआ है। बल्ले-बल्ले हुई है। हमें नहीं पता आप किसे बल्ले-बल्ले कहते हैं।

कृषि की बात करना चाहूंगा। हम सभी कृषक हैं। जब प्रदेश बना तो जी.डी.पी.ए. में कृषि का योगदान 49 प्रतिशत था जो आज घटकर 14 प्रतिशत रह गया है। कृषि घाटे का सौदा हो गई है। आप गांव में जाएं तो वहां फर्टाइल लैंड खाली पड़ी है। किसान कृषि में रूचि नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको प्रमाणित बीज नहीं मिलता, समय पर खाद नहीं मिलती, सिंचाई के साधन नहीं है। किसान को ये सभी चीजें चाहिए और समय पर चाहिए जो कि आपकी सरकार देने में असमर्थ है ऊपर से जंगली जानवरों की समस्या है। बंदरों की समस्या यहां हमेशा डिसकस होती है परन्तु यह यहीं पर डिस्कस होता है आगे कुछ नहीं होता। मैं अपने

क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, मैं धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं, तीन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्ज़ दी जिनका 70-70 लाख रुपये के करीब खर्चा था, वे चल रही थी, बड़ा अच्छा काम चल रहा था परन्तु अब वह काम बन्द पड़ा है। ग्रेविटी स्कीम्ज़ हैं पीने के पानी की जहां फील्टर नहीं है, अनगिनत हैंडपम्प खराब पड़े हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं है, let me tell you very frankly. शिक्षा की बात तो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री धीमान जी ने बहुत की लेकिन मेरा भी इस क्षेत्र में इंट्रस्ट है क्योंकि मैं समझता हूं कि विकास का रास्ता ही शिक्षा से हो कर गुजरता है। इस सरकार की कोई शिक्षा पॉलिसी नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि एक बच्चे के

24.03.2015/1625/केएस/जेटी/3

लिए स्कूल खोल दो और जो 1670 प्रश्न संख्या था मैंने उसको पूरा डिटेल में पढ़ा। कई स्कूलों में एक बच्चा, दो टीचर, यह क्या है? आप कहते हैं कि रैशनेलाइज़ करेंगें। कब करेंगें? स्कूल में एक बच्चा है और उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर, एक पानी देने वाली, एक खाना बनाने वाली, यह क्या है? एक बच्चे पर आप 35-40 हजार रुपये खर्च कर रहे हो। माननीय मुख्य मंत्री जी उस बच्चे को उठाइए और यहां किसी होस्टल में डालिए। He will be thankful to you throughout his life. वहां वह कुछ नहीं सीख रहा है। Please do something on this account. ऐजुकेशन होगी तो हम आगे बढ़ेंगें।

श्री कौल सिंह ठाकुरः इन्द्र सिंह जी, उस स्कूल का नाम क्या है?

श्री इंद्र सिंह अ0व0 की बारी में---

24.3.2015/1630/jt/av/1

श्री इन्द्र सिंह जारी----------

एक नहीं, मैं बताता हूं। एक मिनट, एक मिनट। 943 सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल, 172 सिंगल टीचर मिडिल स्कूल; आपकी ऐजुकेशन इस तरह की है? (---व्यवधान---) सिंगल टीचर, सिंगल बच्चे स्कूल तो बहुत है। (---व्यवधान---) बहुत हैं, बहुत हैं। 20 से कम छात्र के लिए 4301 प्राइमरी स्कूल, 6809 मिडिल स्कूल, 60 हाई स्कूल, 31 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल; जिस सीनियर सैकेंडरी स्कूल में 20 बच्चे हैं तो

आप सोच सकते हैं कि प्लस टू में 12 क्लासें होती हैं। What is that? तमाशा है क्या, क्या यहां सर्कस हो रही है? (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : अगर कहीं 20 बच्चे हैं, that is in the 11th and 12th Class and not in the primary and middle sections. आप ट्विस्ट करके बता रहे हैं।

श्री इन्द्र सिंह : इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक साल में 48000 बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में चले गये। आप क्या करोगे? 48000 बच्चे पिछले साल सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूल्ज में चले गये। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : आपके हलके में जो स्कूल गलत है, आप मुझे उनके बारे में लिखकर भेजिए। Within one week, I will close those schools.

श्री इन्द्र सिंह : आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। I am worried about my State. I am not worried about my Constituency. फोर्चुनेटली मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंगल टीचर स्कूल और सिंगल स्टूडैंट स्कूल है ही नहीं। (---व्यवधान---) इसलिए, मैं बंद नहीं करा रहा हूं। I am seeing the economy of it. You shift those students to a better hostel. They come to the hostel. आपको फायदा होगा, कुल मिलाकर फायदा होगा। Think on these lines, Sir. मैं माननीय धूमल साहब का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र

24.3.2015/1630/jt/av/2

के लिए 90-90 लाख रुपये की 6 साईंस लैब दी। आपने क्या दिया, कुछ नहीं। (---व्यवधान---) कुछ नहीं, एक ईंट भी नहीं लगी। आपने एक पॉलिटीकल सलाहकार जरूर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (---व्यवधान---)

सड़कों की हालत बहुत खराब है। आर्थिक सर्वेक्षण में सड़कों की लम्बाई 35356 किलोमीटर बताई जाती है और माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में

33737 किलोमीटर। अब इसमें भी 3 हजार की डिसपैरिटी है। आंकड़े कनफ्लिक्टिंग हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कें ठीक करने के बाद वह 15दिन में पहले की तरह खराब हो जाती है। पिछले सितम्बर महीने में 7.42 करोड़ रुपये में टारिंग हुई, उस पैसे को कौन खा गया? मैंने इस बारे में प्लानिंग की मीटिंग में भी बात की थी कि इतना पैसा खर्च किया। That has gone down the drain. No action has been taken. Kindly look into this. That is my request to you.

मेरे चुनाव क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कांडा-पत्थर से तीन पेयजल योजनाएं दीं। हम इनके धन्यवादी हैं और पूरा क्षेत्र इनका धन्यवादी है। एक 40 करोड़ रुपये, एक 29 करोड़ रुपये की और एक 15 करोड़ रुपये की योजना थी। कांडा-पत्थर से पानी उठाकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आया। एक डैहर से 23 करोड़ रुपये की स्कीम ,डैहर से सतलुज का पानी भी; मगर उसका अभी तक टैंडर नहीं हो पाया है। तीन स्कीमों पर पूरे जोर-शोर से काम चला हुआ था मगर जैसे ही सरकार बदली सबकुछ बंद हो गया। इसके अतिरिक्त कितनी ही स्कीमें मेरी रीमोडलिंग के लिए हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। आपने केवल फिल्टर बैड लगाने के लिए 20करोड़ रुपये रखे हैं। 20 crore is a peanut amount. कम-से-कम यह सरकार स्वच्छ पानी तो दे सकती है। Kindly look into this.

24.3.2015/1630/jt/av/3

पन बिजली हमारी आर्थिकी में एक दुधारु गाय है। अभी आप केवल 9432 मैगावाट बिजली का दोहन कर पाये हैं और इसमें भी काम स्लो चल रहा है। एच.पी.एस.ई.बी. घाटे में चल रही थी----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1635/negi/jt/1

श्री इन्द्र सिंह ..जारी..

एच.पी.एस.ई.बी. घाटे में चल रही थी और आपने इसको ट्राईफरकेट कर दिया। हमको एकॉउन्टेबिलिटी नहीं मिलती है इसलिए आपने इसके 3 विंग बना दिए। पहले एक बॉस होता था अब 3 बॉस होते हैं। एच.पी.एस.ई.बी.लिमिटिड, एच.पी.पी.सी.एल. और एच.पी. टी.एल.लिमिटिड । घाटा तो बढ़ गया क्योंकि 3

बॉसिज़ हो गए। जितने बॉसिज़ बढ़े उतने ही लॉसिज़ बढ़े। Look into this. आपके भाबा पावर प्रोजेक्ट के प्लॉट में कैसे आग लग गई ? क्या उस ट्रांसफार्मर में इन-बिल्ट फायर फाइटिंग इन्स्ट्रूमैन्ट की फैसिलिटी नहीं थी ? करोड़ों का ट्रांसफार्मर कैसे जल गया ? Please look into this. It is a gross negligence on the part of the maintenance staff. Please look into this. मेरी आपसे यह विनती है।

अध्यक्ष जी, अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में आदरणीय धूमल साहब ने बलद्धाड़ा हास्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए 40 लाख रूपये दिया था। जितनी बार मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछता हूं तो वह ऐसे सिर हिलाते हैं। यह आपका साऊथ इंडियन स्टाइल है या नोर्थ इण्डियन स्टाइल है । साऊथ इंडिया में अगर ऐसे करते हैं तो इसका मतलब न होता है और नोर्थ इण्डिया में ऐसे करते हैं तो हां होता है । अब बताइये आपका क्या है? आपका stance क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : हम पहाड़ी लोग हैं और मेरा तो पहाड़ी स्टाइल है।

Sh. Inder Singh: Please look into that. We have as many as six doctors short at Sarkaghat Referral Hospital. We have as many as 10 doctors short under the BMO. 18 डॉक्टर होते थे अभी 8 डॉक्टर्ज़ हैं और 10 डॉक्टर नहीं हैं। Kindly look into that area. My area is land-locked हमारे पास कोई फॉल बैक नही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे पास कोई फॉल बैक नहीं है। There is

24.03.2015/1635/negi/jt/2

no Civil Hospital. उस एरिया में कुछ भी नही है। We are totally dependent on Govt. hospitals. Kindly look into that. पूरे एरिया में ,सरकाघाट-मंधोल से ले करके घुमारवीं तक कोई गॉईनेक्लोजिस्ट नहीं है।... (व्यवधान) ...आप गर्दन नहीं बल्कि जीभ हिलाइये और यस बोल दीजिए। Thank you Sir.

अध्यक्ष जी, मैं फौजियों के बारे में बात करना चाहता हूं। भगवान की याद और फौजियों की याद तब आती है जब मुसीबत पड़ती है। जब मुसीबत टल जाती है तो

दोनों को बुला दिया जाता है I आप हमारे एक्स-सर्विसमेन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखते है। 45 साल की उम्र में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो 5-6 साल के बाद वह 50 या 51 साल का हो जाता है उसके बाद अगर उनको आप रेगुलर करते हैं तो क्या मिला उनको? No benefit . पिछली बार माननीय कर्नल धनी राम शांडिल जी से हमने बात की थी तो इन्होंने भी हां कर दी थी कि we will look into this. But I don't know how long will he take to look into this. Kindly look into this aspect. This is a very emotional issue for us. आपने हमारे जितने भी सैनिक रैस्ट हाऊसिज़ हैं उनके रिपेयर के लिए 2 करोड़ रूपये दिया I That is a peanut. आप सरकाघाट का सैनिक रैस्ट हाऊस देखिए फिर आप एमॉउन्ट दीजिए। वहां पर उसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है I इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसको आप जरूर देखिए। वॉर मैमोरियल के लिए आपने 3 करोड़ रूपये दिया, इसको भी आप बढ़ाइये। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और उन्होंने भी कहा था कि उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आखिर में, जो बजट अनुमान आपने पेश किया है वह बहुत ही निराशाजनक है। गरीबों के लिए तो आपने किया ही कुछ नही और मैं उसपर बोलना नही चाहता।

Speaker: Please wind-up.

24.03.2015/1635/negi/jt/3

श्री इन्द्र सिंहः एक मिनट सर। आपने दिहाड़ी 10 रूपये बढ़ाए-एक कप चाय। होम गार्डज़ जो बेचारे वर्दी पहनते हैं, गर्मी में खड़े होते हैं और बरसात में खड़े होते हैं उनकी दिहाड़ी 20 रूपये बढ़ाए- दो कप चाय। जो डाऊन ट्रोडन है, लाईन के आखिर में खड़े हैं उनकी तरफ तो आपकी नज़र नहीं पहुंची और आप फ्रंट लाईन में ही देखते रह गए। Kindly have this thing in mind also. Mr. Chief Minister, Sir, I am thankful to you for increasing the Vidhayak Nidhi to Rs. 70 lakh with a rider. Thank you for cutting the rider off. But it should be divisible by 25. So, make it Rs. 75 lakh or Rs. 1 crore.

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

24.03.2015/1640/यूके/जेटी1

श्री इन्द्र सिंह---जारी

बड़ा दिल है आपका ,आप कर दीजिए । इसी से विकास होता है । डिस्क्रिशनरी ग्रांट, 2 लाख रुपए, यह भी बहुत थोड़ी पड़ रही है । इसको भी बढ़ाने की कृपा करें, यह मेरी आपसे विनती है । जो आपने 3 LED दिए हैं, माननीय धूमल साहब ने 4 बल्ब दिए थे, मुफ्त में और आपने 3 दिए । Make it cost free. या इनकी संख्या बढ़ा दीजिए । इसमें बचत भी ज्यादा होगी । तो इसको बढ़ा दीजिए यह मेरी आपसे विनती रहेगी ।

अध्यक्षः कर्नल साहब, काफी टाईम हो गया आपको बोलते हुए ।

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इतना टाईम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं इस बजट को टोटली रिजैक्ट करता हूं ।

मुख्य मंत्रीः आपने इस बजट को रिजैक्ट कर दिया है, इसलिए हम आपके हलके में इस बजट को लागू ही नहीं करेंगे । यदि आपने रिजैक्ट कर दिया है तो आपका जो हलका है, it will not be applicable to your Constituency.

श्री इन्द्र सिंहः सर, नहीं हम यहां पर रिजैक्ट कर रहे हैं ।

24.03.2015/1640/यूके/जेटी/ 2

अध्यक्ष : अब श्री रवि ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे ।

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I rise to speak on the budget for the Year 2015-16 which I find the most popular and congratulate the Hon. Chief Minister and the people of Himachal Pradesh. I support the budget. Provisions have been kept and the budget has been enhanced in every department and for all communities i.e. farmers, industrialists, businessmen, old people, women and children. Schemes have been increased in the departments of horticulture, agriculture, IPH, PWD, etc. and also the scheme like Vidhayak Nidhi has been enhanced. PPP mode has been introduced in many places like tele medicine, education,

technical education, etc. Provisions for different categories like ex-servicemen, women empowerment, child development, pensions for different categories of society have been made to make them secure. Budget has been provided under the schemes for handicapped, disabled and SC categories for their upliftment. Budget has also been enhanced for fertilizer subsidy, sprinklers, carriage subsidy, ration depot,

24.03.2015/1640/यूके/जेटी/3

etc. Special schemes for Panchayati Raj and backward classes have also been kept in the budget in public interest.

Hon 'ble Speaker, Sir, regarding the budget I would like to mention that through it has been enhanced for tribal area for the year 2015-16, but still I would like to bring to notice that in certain specific departments some more schemes should be given. So far Lahaul-Spiti is concerned, I feel the Ministry of Defence, Govt. of India, has given Rs. 2200 crore to construct the tunnel with which lot of tourist traffic and other traffic will increase and with this, we need to enhance winter sports, ropeways, skiing, water sports, etc. in the area and a master plan has to be made for the area as Lahaul-Spiti covers 23 per cent of Himachal and which at the moment is barren. So, budget provisions may kindly be increased for this in the public interest in Lahaul-Spiti.

Contd. Ag/sls..

24032015/1645/SLS- AG/1

Shri Ravi Thakur Continued . . .

So, the budget provision may kindly be increased for this. This I feel will be in the public interest of Lahaul & Spiti. Under PPP mode, DPRs for bus stands, insinators, sewerage, ropeways, which will carry horticulture

and agriculture produce from Shimla to Parwanoo and other places etc. have been made by the Government of Himachal Pradesh. DPR has been made under PPP mode to construct lot of parking places. DPRs may also be considered for helipads and extension of airports and taken into task.

The buildings in Lahaul & Spiti under master plan should be made of a local style like Bhutan and other places so that the area is developed properly. There should be improvement in medical standards etc and specialists and other technicians should be provided in tribal areas as during six months in Winters due to heavy snowfall everything is stranded and the place is lifeless. There is no progress, no movement. Henceforth, in the interest of the people some more focus has to be made for evacuation of patients by helicopters and for other emergencies also. I feel there should also be enhancement in relief in case of natural calamity,

24032015/1645/SLS- AG/2

as during Winters there is lot of damage in irrigation, bridges, roads, water supply etc. They are damaged during Winters. In Summers also due to flash-floods and lake formations which are increasing due to global warming, there are lot of creation of floods which are happening in Lahaul & Spiti valley like Kir Nullah and Chokham Viar Nullah, which the Hon'ble Chief Minister has visited himself, and there has been damage in bridges, roads and other buildings in Sichling, Spiti etc.

In the tunnel, which is being constructed under Rohtang, the provision for transmission line may be kept. Provision is made for evacuation of power in case of generation of power in Lahaul from the hydel projects and whatever transmission lines are going overhead Rohtang Pass, the lines can be taken from the tunnel so that no damage

is made and supply is ensured to the people of Lahaul & Spiti. Hydel projects of Shansha, Sissu, Thirote, Beeling, Reinstall etc. may be revised in the public interest which will enhance the State economy.

For agriculture and horticulture produce, power tillers, power sprinklers, and power sprayer carriage subsidy etc. should be

24032015/1645/SLS- AG/3

enhanced which will be in the public interest otherwise the Government has given sufficient budget for these areas.

Regarding school, I differ slightly from the other Members. I would say that in Lahaul & Spiti we do require schools, especially primary schools which have two students because the distances are so much and there are so many avalanches and other floods in between and the little children cannot walk very far away. So, the system of school for 3, 4 and 5 children is also necessary because every parent wants his child to be educated. On the other hand, for higher education, Eklavya School and Nav Uday School and consolidation of schools for betterment of quality, good hostel and competition, is required for which good teachers are to be employed.

Apart from agriculture and horticulture produce like apple, potato, peas, kuth, sea-buckthorn, hops, herbs; medicinal plants may also be encouraged by cultivation. Installation of factories for raw-material should be made for the betterment of people. Flora, fauna, other species and wildlife may be protected. Budget

24032015/1645/SLS- AG/4

provision which has been kept for the wildlife may also be given same focus.

Old Buddhist culture, custom, monasteries and temple preservation in the tribal area is done by Art, Language and Culture and Tourism Department. Tabo Monastery got Rs. 22 crores from the GOI as a Buddhist institution where higher studies will be given to Buddhist. Sermons initiation and other functions will also be held in the institution.

Renewal Solar Energy should be enhanced in Spiti valley for which an agreement has been done by GOI of 2 mw and 500 kw high breed wind energy of Rs. 30 crores for which land provision has also been kept which will enhance the power supply and give electricity to the area. It may kindly be done speedily.

Exemption of income tax, excise and sales tax may be done in tribal areas on the precedence of North Eastern States, seven States which come under donor. In Ladakh also these taxes are exempted which will also encourage the employees like doctors and others to stay there and serve better.

24032015/1645/SLS- AG/5

The Mudh Bhawa road was declared State highway by the Hon'ble Chief Minister in Tribal Advisory Council meeting. I request that the steps may kindly be taken for the clearances of FCA and the road is started to its earliest as it cuts down 80 kms of the length. There is no landslide and other glacier points in between.

I also request that steps may kindly be taken for FRA for its completion as it is in the pipeline. In the country, many States have already distributed land as per the GOI policy, but in Himachal Pradesh it is still in the pipeline and much less not been done.

At last, I thank the Hon'ble Chief Minister and Government of Himachal Pradesh for giving popular Budget. I also thank the Hon'ble Speaker for giving me time. Thank you.

Contd. By RG in Hindi.

24/03/2015/1650/RG/AG/1

श्री रवि ठाकुर की अंग्रेजी के पश्चात

अध्यक्ष : अब बैठक का आज का निर्धारित समय समाप्त होने वाला है और अभी चार सदस्यों ने और बोलना है। यदि सदन की अनुमति हो, तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए या फिर कल बोलना चाहें ,तो कल भी बोल सकते हैं। जैसी भी सदन की अनुमति हो।

माननीय सदस्यगण : समय बढ़ा दिया जाए क्योंकि कल भी काफी सदस्यों ने बोलना है।

अध्यक्ष : समय बढ़ाना है, ठीक है। अब इस माननीय सदन का समय 6. 00बजे तक बढ़ाया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया संक्षेप में ही बोलें। अपना भाषण सीमित ही रखें।

अब श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

24/03/2015/1655/ms/ag/1

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री विजय अग्निहोत्री जी भाग लेंगे। कृपया अपना भाषण सीमित रखिएगा।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 18 मार्च को 18वें बजट अनुमान पेश किए हैं, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यहां चर्चा में भी आया और यह सत्य भी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वर्ष 1962से राजनीति में है। जवाहर लाल नेहरू जी के समय भी यह संसद में थे और पांचवीं या छठी बार मुख्य मंत्री भी बने हैं। इतने लम्बे समय से राजनीति में होते हुए हमें यह उम्मीद थी कि जब 18वां बजट यह पेश करेंगे तो उस बजट में एक विजनरी सोच के

साथ एक दिशा इस प्रदेश के विकास को देंगे। लेकिन तीन घण्टे 10 मिनट के लम्बे भाषण के दौरान बजट भाषण में कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी सोच के साथ, किसी दिशा की ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। बल्कि ऐसा लगा कि किसी स्कूल के रिजल्ट की तरह पहले स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में क,ख, और ग वैसे ही रहे। बस, 210 रूपये से 220 रूपये कर दिया और ऐसे ही पूरा यह तीन घण्टे दस मिनट का एक लम्बा भाषण इस करके दिया गया ताकि जो इनकी असफलताएं हैं, उनके ऊपर से सबका ध्यान हट जाए और किसी को समझ न आए। मुख्य मंत्री जी, हमारे यहां एक कहावत है। जब बेटी ससुराल जा रही होती है तो मां कहती है कि बेटी अगर आपसे कोई काम होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं लेकिन जुबां से हारना मत। वह आपका हाल है। उसकी लीपापोती करने की कोशिश की गई है। इस बजट में न कोई दिशा है, न कोई नई योजना है। (व्यवधान) मैं प्वाइंट पर ही आ रहा हूं। मुख्य मंत्री महोदय एक तो राहत भी दी है दूसरे, आप वर्ष 1962से राजनीति में है। तब टैस्ट मैच का जमाना था, उसके बाद वन डे इंटरनेशनल आया। अब ट्वेंटी-ट्वेंटी का जमाना है। आपको भी उस तरह से पेस बढ़ानी पड़ेगी, तब इस प्रदेश का भला हो पाएगा।

इस बजट में चाहे कोई भी क्षेत्र हो। चाहे मजदूर है, कर्मचारी है, किसान है, बागवान है, महिला है या युवा है, किसी के लिए नया कुछ नहीं है। आपने कहा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र को एक सरकारी दस्तावेज बनाते हुए उसके अधिकांश वायदे पूरे कर दिए हैं। लेकिन जो आपका बजट है, बजट अनुमान हैं उसमें ऐसा दिखता नहीं है। जब ऐसी बातें माननीय धूमल जी ने और अन्य लोगों ने

24/03/2015/1655/ms/ag/2

यहां रखी कि आपके घोषणा पत्र और बजट के बीच में कितना अन्तर है, वह सब लोगों के सामने आया तो आपने कहा कि पांच वर्ष के लिए यह मैनीफेस्टो होता है। मैं अध्यक्ष जी, यह जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष में विकास के काम करने के लिए कोई समय-सीमा तो हो सकती है। लेकिन आप पारदर्शी प्रशासन देने के लिए भी पांचवें साल के अंतिम महीने में बोलेंगे कि अब हमने इसको पूरा किया है। इस सरकार ने पिछले दो वर्षों में जो पारदर्शिता दिखाई और कानून-व्यवस्था की जो हालत इस प्रदेश की हुई, वह किसी से छिपी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर कांग्रेस समर्थित लोग जाकर हो-हल्ला और मारपीट करते हैं और हमारे

कार्यकर्त्ताओं की आंखें तक उसमें चली गईं ,वह कानून व्यवस्था है? जब यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और माननीय बंबर ठाकुर जी उस पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां कोई हो-हल्ला नहीं हुआ और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि वहां कोई पंगा नहीं हुआ। बल्कि वहां तो हमारे लोगों को बदनाम करने के लिए बी0जे0पी0 के कार्यकर्त्ताओं ने ही अपने कार्यकर्त्ताओं को चोटें पहुंचाई। (व्यवधान) बंबर ठाकुर जी ने बोला है, आप रिकॉर्ड निकालकर देख लेना। मैं यह बोलता हूं कि आप में से कोई अपनी आंख फोड़कर देख सकते हैं। आप अपने ही लोगों की आंखें फोड़ दो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

4.**03.2015/1700/जेके/एजी**/1

श्री विजय अग्निहोत्रीः------**जारी**-------

मैं यह बोलता हूं कि आप में से कोई अपनी आंख फोड़ करके देखे लो। आपके ही लोग फोड़ दो और केस मुझ पर बना देना। अगर किसी मैं हिम्मत है तो फोड़ो अपनी आंख।

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य, मैं आपकी इस बात को बजट चर्चा की रिप्लाई में सबसे पहले बोलूंगा।

श्री विजय अग्निहोत्रीः यहां पर एक बात बम्बर ठाकुर जी ने कही। उन्होंने कहा कि राजा साहब आपकी यह सरकार चट्टान की तरह चल रही है। उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि चट्टान चलती नहीं है। चट्टान या तो खड़ी रहती है या धंसती है। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि चट्टान खड़ी है या धंस रही है। मुझे तो लग रहा है कि धीरे-धीरे धंस रही है। अब तो बहुत कम समय रह गया है जब यह चट्टान लुप्त हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। उसको कौशल विकास भत्ते के नाम से उलझा करके लोगों के सामने रख दिया। इस प्रदेश में सुरंग बनाने की बात की गई। उस काम को उलझा कर रख दिया है। किसी बजट में आ जाता है और किसी में उसका उल्लेख तक भी नहीं आता है। सरकार की कोई दिशा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार की वह हालत हो गई है कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर मैं बात कर रहा था। इस प्रदेश में दो वर्षों से माफिया राज है। चाहे वह खनन माफिया हो, चाहे वह शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, वन कटान का माफिया हो और चाहे ट्रांसफर माफिया हो। हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही है। खनन माफिया इस ढंग से काम कर रहा है कि यहां का रेता,बज़री दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। हमीरपुर जिला में पिछले वर्ष एक घटना घटी। एक माइनिंग गार्ड ने कुछ लोगों को माइनिंग करने से रोका और उनका चालान किया। उस माइनिंग गार्ड को पीटा गया। उस माइनिंग गार्ड ने जब

4.03.2015/1700/जेके/एजी/2

पुलिस में रिपोर्ट की तो उसकी वहां से तीन दिन के अन्दर-अन्दर बदली कर दी गई। दो महीने के पश्चात जब मैंने पता किया तो बताया गया कि उसकी बदली भी केंसिल हो गई और एफ.आई.आर. भी केंसिल हो गई। यह आपकी ट्रांसपेरेंसी है। आज पुल के नीचे से खनन होता है। कोई अधिकारी/कर्मचारी वहां जाने को तैयार नहीं है। मैंने हमीरपुर के एस.पी को नाम लेकर बताया कि फलां दुकान में शराब बिकती है और पेटियों के हिसाब से बिकती है। लेकिन पिछले 8 महीनों के अन्दर उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया । उन्होंने कहा कि शराब बिकती है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ कैसे पाएंगे? जब आप बोलेंगे कि कहां रखी है शराब और उसे हमारे आगे-पीछे कर दे। यह आपकी ट्रांसपेरेंसी है। यह कानून-व्यवस्था है। यहां से कौल सिंह जी उठ करके चले गए। हमारे वहां पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिस ग्लोड़ में आशा वर्कर्ज़ की भर्ती हुई। ऊपर से जितना दबाव था उस सारे दबाव के बावजूद जब वहां के बी0एम0ओ0 ने आशा वर्कर्ज़ की लिस्ट निकाली और उसने कुछ को एप्वाईंटमैंट लैटर्ज दे दिए। ऊपर से फोन चला गया कि इसको रोको। इसमें अभी बदलियां करनी है। उसने जिन-जिन को एप्वाईंटमैंट लैटर्ज दिए थे उनसे वापिस लिए। उस अधिकारी के ऊपर प्रैशर डाला गया तो ग्लोड़ का बी0एम0ओ0 लम्बी छुट्टी पर गया। अगर आपको शक हो तो उसका रिकार्ड मंगवा के देख लेना। ये आपके पिछले दो सालों की ट्रांसपेरेंसी है।

आप एस.एम.सी के माध्यम से जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियां में धांधलियां हो रही हैं। पटवारियों की भर्तियों में धांधली हुई। जिन आई.आर.डी.पी. के लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से बहुत सारे लोगों का वहां से आई.आर.डी.पी. का फॉर्म

काट करके उनको जनरल में डाल कर फिर दूसरों को वहां पर नौकरी दी गई। जब वे लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में पूरे का पूरा रिकार्ड मंगवाया गया। फिर कई लोगों को पटवारी की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यह आपकी ट्रांसपेरेंसी है। इस प्रकार की कानून-व्यवस्था इस पूरे प्रदेश में चल रही है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन

4.03.2015/1700/जेके/एजी/3

की बात यहां पर हुई। उसको बढ़ा दिया गया। 80 साल के लोगों को जो नॉन पेशनर्ज़ हैं उन सब को पेंशन दी जाएगी। पिछले एक साल से मैं देख रहा हूं और मैं जहां भी जाता हूं बूढ़ी-बूढ़ी माताएं और बूढ़े लोग मिलते हैं और कहते हैं कि बच्चा पेंशन नहीं आई। मैं डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर ऑफिस हमीरपुर में चला गया वहां पर पता किया तो वहां पर बताया कि वह एन्हांसमैंट तो नहीं होगी क्योंकि उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

24.03.2015/1705/SS-JT/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। कोई पैंशनर मर रहा है उसकी जगह हम उनको दे रहे हैं। वे बेचारे 80 साल वाले मर रहे हैं और यहां कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनको पैंशन दी जाए। बजट में बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो हालात आज हैं, मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि आप बताओ कि कौन से स्कूल बंद कर देने, स्कूल बंद मत करो। आप खोलो। लेकिन यह सत्य है कि पिछले कल जो प्रश्न लगा हुआ था उसमें बताया गया कि जिनमें पांच से कम बच्चे हैं वे 411 हैं। जिनमें 10 से कम हैं वे 725 स्कूल हैं। सिंगल टीचर स्कूल 943 हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें दो बच्चे हैं और तीन अध्यापक हैं। हम कहां जा रहे हैं? जैसे कर्नल इंद्र सिंह जी ने कहा कि हम किसी विज़नरी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम पब्लिक स्कूलों से पीछे कैसे रह रहे हैं? मुझे याद है कि जब धूमल जी की सरकार थी तो मेरी कांस्टीचुऐंसी में एक स्कूल बंद हुआ। गांव के दस लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए और कहा कि स्कूल बंद हो गया, इसको खुलवाओ। मैंने जब उन लोगों से पूछा कि

आप बताओ कि आपके घर में कितने छोटे बच्चे हैं वे कहां पढ़ रहे हैं तो 10 में से 8 लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप दाखिल करवाओगे तो स्कूल दोबारा खुलेगा। जी0पी0एस0 मगरांह स्कूल है। जब उन्होंने वहां पर बच्चे दाखिल करवाने की कमिटमैंट की तो हमने स्कूल खुलवाया और उसमें 17 बच्चे दाखिल हुए। अब वे बढ़ भी गए होंगे। लेकिन अब उसको एजुकेट करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई ऐसी सोच नहीं है।

अध्यक्षः अग्निहोत्री जी, ज़रा संक्षेप में बोलिये। आपको 15 मिनट हो गए हैं। आप और कितना बोलेंगे?

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे 15 मिनट नहीं बल्कि 6 मिनट हुए हैं। इस सरकार ने रूसा आनन-फानन में शुरू किया। इंटर डिस्प्लनरी सब्जैक्ट च्वाइस रखी। कॉलेजिज़ में बैठने को जगह नहीं, 18 सब्जैक्ट के लिए कमरे नहीं, मेजर सब्जैक्ट रख दिए। बोले कि इंटर डिस्प्लनरी सब्जैक्ट कर लेंगे। कैमिस्ट्री वाला हिस्टरी पढ़ेगा। मैंने एक प्रश्न किया, उसमें बताया गया कि इस प्रदेश में कॉलेज गोइंग एक लाख छात्रों में से 1800 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटर डिस्प्लनरी सब्जैक्ट चूज़ किये हैं। बच्चे चाहते नहीं है और आप दिए जा रहे हैं। रणधीर जी ने ठीक कहा कि लोग लंगोटी चाहते हैं और आप टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं।

24.03.2015/1705/SS-JT/2

इस करके शिक्षा के बारे में बहुत गहन चिन्तन होना चाहिए। आज इतने वर्षों के पश्चात् भी शिक्षा किस दिशा में बढ़े, उसको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए ,उसके ऊपर मिनीमम खर्चा करते हुए ऑप्टिम यूज़ कैसे शक्ति का करें इन विषयों के ऊपर सोचने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी, उठकर चले गए। अभी कांस्टीचुऐंसी के हाल ही के दौरे पर गए थे और इन्होंने धूमल जी के समय में जो पुल बनकर तैयार हुआ था उसका उद्घाटन किया। धूमल जी के समय में एक रैस्ट हाउस बन कर तैयार हुआ उसका उद्घाटन किया। इनके समय में ही एक टूरिस्ट इंफोरमेशन सैंटर का जहां शिलान्यास हो गया था, वहां केस चल रहा था। इस करके दूसरी जगह उसका शिलान्यास किया। मिनी सचिवालय जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल 2010 में आई गई थी, उसका शिलान्यास करके आए। मंच

पर जहां जनसभा में गए, वह पढ़ा भी नहीं कि इन्होंने क्या-क्या मांगा, जो इसमें लिखा है मैं एप्रूव करता हूं। जो लिखा, वह सब एप्रूव कर दिया। अरे, भाई करना था तो गलोड़ में कॉलेज की आवश्यकता है उसकी घोषणा करते। आप आधे-आधे किलोमीटर पर प्लस-टू स्कूल कर दो, हम उसका विरोध नहीं करते। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां जो आवश्यकता है, वह होना चाहिए। नीड बेसड चीज़ होनी चाहिए। नीति आयोग ने जो एक बहुत अच्छा काम किया है वह यही किया है कि प्रदेशों को पैसा दिया है कि आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से योजनाएं बनाईये। आप लोगों की आवश्यकताओं के बारे में सोचते नहीं हैं। जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने लिख कर दे दिया, वह कर दिया। धर्माणी जी, आपको मुबारक हो, अगली लाइन बिल्कुल खाली हो रही है। आप ही यहां आयेंगे। मैं मुख्य मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग लोग आपके पास रखते हैं उनको पढ़ लिया करो। कौन-सी जायज़ है और कौन-सी नहीं, वह देख लिया करो। किसी व्यक्ति ने ऐसे ही बोल दिया या लिख दिया कि बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें आप बोलें कि मैंने कर दिया। ऐसा नहीं होगा।

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1710/केएस/जेटी/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----

मोदी जी का धन्यवाद करने से आपको गुरेज़ है । 21 हजार करोड़ की जगह आपको 72 हजार 47 करोड़ मिल रहा है। 32 प्रतिशत सैंट्रल टैक्स शेयर की जगह आपको 42 प्रतिशत मिल रहा है, इतना ह्यूज़ अमाऊंट मिल रहा है लेकिन आप कहते हैं कि हमारे तो पैसे कम हो गए। अरे भई, पुरानी बात सोचो, जब हम युनिवर्सिटी में पढ़ते थे श्री नरसिम्हा राव जी शिमला आए, राजा साहब ने उनका बहुत स्वागत किया। सोचा कुछ दे कर जाएंगें लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद यहां मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, वे यहां आए, आपकी सरकार यहां भी थी और केन्द्र में भी थी, आपको कुछ नहीं मिला। आपको किसने दिया? अगर 592 करोड़ रु0 का कोई पैकेज़ दे कर गए तो वे अटल बिहारी वाजपैयी जी कुल्लू में आ कर दे कर गए। केन्द्र में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश को तब पैसा मिला है। आज अगर मोदी जी ने हिमाचल के लिए पैसा बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से बढ़ाया। आपने हमें कहा कि हमने 13वें फाईनैंस कमिशन में अच्छी

बात नहीं रखी, हमने बड़ी अच्छी रखी। जब आपके प्रधानमंत्री होते हैं तो आप क्यों अच्छी बात नहीं रखते हैं? आपको नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी क्यों पैसा नहीं देते? आप वाजपैयी और मोदी जी से ही पैसा क्यों लाते हैं? जो मोदी जी की सरकार है या वाजपैयी जी की सरकार थी, वे विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जिसका जितना हिस्सा बनता है उससे भी ज्यादा देते हैं। श्री नंदलाल जी कह रहे थे कि यह तो हमारा संवैधानिक अधिकार है तो यह अधिकार पहले कहां था? केन्द्र में जब भी

24.03.2015/1710/केएस/जेटी/2

बी.जे.पी. की सरकार बनी है, इस प्रदेश को भरपूर पैसा मिला है और कल भी यहां पर हमारे बारे में कहा गया कि ये तो किसान विरोधी हैं और राहुल गांधी जी किसान चिंतक है, किसानों के नेता है। कुलदीप जी, उनको किसी किरयाने की दुकान में ले जा कर पूछ लो कि यह कौन-कौन सी दालें हैं तो काली और पीली के अलावा वे कुछ नहीं बता सकते, वे ऐसे किसान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि फाईनैंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है । अगर वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो आपने मितव्ययता की कौन सी कोशिश की? आपने कितने चेयरमैन, वाईस चेयरमैन और सी.पी.एस. बनाए और इतने लोगों की क्या आवश्यकता थी? अगर वित्तीय स्थिति कठिन है तो याद करो लाल बहादुर शास्त्री जी को जिन्होंने कहा था कि इस देश में अनाज की कमी है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति व्रत रखेगा । अगर आप मित्तव्ययता करना शुरू करेंगें तो लोग भी करेंगें। पूरे देश में सोमवार के दिन ढाबे बंद हो गए थे और लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया था लेकिन नेता को गुण पैदा करने पड़ते हैं। कुर्ते का साइज़ उन्होंने छोटा कर दिया था कि फौज को वर्दी चाहिए तो वर्दी भेजेंगें लेकिन सरकार या नेता जो मर्जी करते रहे और लोग और अपोजीशन वाले मित्तव्ययता करे और आपके फंडज़ का प्रबन्ध करें, ऐसा नहीं चलेगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

24.03.2015/1710/केएस/जेटी/3

श्री विजय अग्निहोत्रीः सर, कर रहा हूं। मैंने बहुत सी बातें सुनी थी। वीरभद्र जी 1962 में एम.पी. बन गए थे, मैं 1967 का जन्मा हूं । 1967 के मनसा राम जी यहां पर एम.एल.ए. हैं और उनके चुनाव क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है।

अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में दो-तीन बिल्डिंगों का काम चल रहा है उनकी बहुत बुरी हालत है। बाली जी, यहां पर बैठे हैं। एच.आर.टी.सी. में बहुत बसें आ गई। एच.आर.टी.सी. में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र को समान दृष्टि से देखा जा रहा है । किसी भी जगह नगरोटा बगवां के कम लोग नहीं पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं बाली जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाली जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी बसों के रूट बन्द है। इसमें पालमपुर-दिल्ली वाया नदौन वाया धनेटा, हमीरपुर-लुधियाना वाया धनेटा,

परिवहन मंत्रीः माननीय सदस्य, जो 2014 के बाद बन्द हुए हैं वह पढ़ दो।

श्री विजय अग्निहोत्रीः सर, मैं वही पढ़ रहा हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा--

24.3.2015/1715/ag/av/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----------

वही पढ़ रहा हूं, आप कनफर्म कर लेना। आप पता कर लेना। मैं आपसे जबरदस्ती थोड़े ही न लगा रहा हूं। हमीरपुर-परवाणू वाया धनेटा, सुजानपुर-कालका वाया धनेटा, सिविल खड्ड शिमला वाया कांगू-गलोड़, पंचधाम-धनेटा, रंगस-नैनादेवी, देहरा-बरठीं वाया धनेटा, ज्वालाजी-दिल्ली वाया धनेटा, नदौन-दियोटसिद्ध वाया कांगू-गलोड़ ,बैजनाथ-पालमपुर-बड़ा जो बलडूक से होकर जाती है। आपसे निवेदन है कि इनमें कुछ बसें दिल्ली जाती है, आप कुछ बसें बलडूक होकर कर दें। (---व्यवधान---) यह एक सिंगल बस है। वहां बसें बहुत आईं मगर हमारे यहां एक भी नहीं आई। सर, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक वाया नदौन-हमीरपुर-होशियारपुर रूट जो बंद हो गया था उसको आपने दोबारा शुरु किया, आपका धन्यवाद। मगर उसमें एक बढ़िया बात यह हुई कि जब वह बस रूट दोबारा शुरु

हुआ तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने नदौन में उसका उद्घाटन भी किया। उसमें दो किलोमीटर तक बैठकर गये। मैं कालिया जी और कुलदीप जी का नम्बर ढूंढता रह गया। मैं उनको यह कहना चाहता था कि आप भी उद्घाटन कर लो, मगर फोन ही नहीं मिला।

अध्यक्ष : प्लीज, बाइंड-अप।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बाइंड-अप कर रहा हूं। अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष : अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं। You cannot speak for two hours.

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, दूसरे लोग आधा-आधा घंटा बोले हैं। हमें कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है, आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए। नदौन में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। मुख्य मंत्री जी ने बसारल पुल का उद्घाटन किया।
24.3.2015/1715/ag/av/12

मैंने भी किया था, मैंने ऐसे ही शोर मचा दिया। वहां के लोगों को लगा कि कहीं रैस्ट हाउस का उद्घाटन भी न हो जाए इस करके ले गये। वहां जिस तरफ से उद्घाटन किया उस तरफ की सड़क बना दी और दूसरी तरफ से सड़क कच्ची थी, उसके बारे में किसी ने देखा नहीं। मुख्य मंत्री जी को उस तरफ से ले जाया भी नहीं गया। कितनी बुरी हालत है। रंगस से आप धनेटा चले जाओ, बड़ा चले जाओ। आप जीण वाली सड़क पर चले जाओ। भट्टा-सलौणी सड़क देख लो। पन्याली-धनेटा देख लो। कश्मीर-तुहनी देख लो। नदौन-बड़सर वाया धनेटा देख लो। कांगू-मालग-धनेटा वाया जनसूह देख लो। गलोड़-फाहल-टिप्पर देख लो। इसमें इन्द्र दत्त लखनपाल जी का भी कुछ निर्वाचन क्षेत्र आता है, उसका हाल बहुत बुरा है। गलोड़-झरमाणी-वाहल-कड़साई-दांदड़ू-गालियां इत्यादि ये सारी ऐसी सड़कें हैं। इनमें पता ही नहीं चलता कि सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। पिछले दो-तीन सालों से उसमें मैटलिंग ही नहीं हुई। वहां मुख्य मंत्री जी दौरे पर गये थे। मुख्य मंत्री जी को ऐसे शॉर्ट-कट रास्ते से लेकर गये ताकि इनको सड़कों की हालत का पता न चले। वहां वाया पणसाई दिल्ली-हमीरपुर शॉर्टेस्ट रोड है। पिछले साल के फरवरी माह में वहां

मेन रोड की पुली टूटी। हमने प्लानिंग की मीटिंग में भी इसके बारे में बात की थी और आज भी वह टूटी हुई है। हमने जबरदस्ती बार-बार बोलकर उसके टैंडर करवाये। टैंडर होने के बावजूद आज भी वहां काम नहीं चल पा रहा है। इस करके मैं यह कहना चाहता हूं कि हालत ठीक नहीं है। विधायक निधि बढ़ी, कंडिशन्ज हटनी चाहिए। पहले की गाइड लाइन्ज के ऊपर भी पुनर्विचार होना चाहिए कि हम उस पर कम्पलिशन के लिए नहीं दे सकते, ऐडिशनल बजट नहीं दे सकते। हम रिपेयर / मैंटेनैंस के लिए नहीं दे सकते। हम 33 प्रतिशत से ज्यादा ऐडिशनल अमाउंट अपनी ही स्कीमों पर नहीं दे सकते; इन सब चीजों को हटाना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं सरकार के ध्यान में और लाना चाहता हूं। मैंने करीब डेढ़ वर्ष पहले विधायक निधि में से कुछ पैसा लोक निर्माण विभाग में डाला मगर राजनीति के कारण डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्होंने वहां काम शुरु नहीं करवाया। आज यहां पारदर्शिता और गुड-गवर्नैंस की बात होती है। वहां आपने किस-किस को काम

24.3.2015/1715/ag/av/3

करने के लिए ऑथोराइज किया है? पिछले कल की ही बात है, वहां आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अनाउंसमैंट करवा दी कि मैं किटपुल में खुला दरबार लगाऊंगा और वहां पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन को बुला लिया जाता है। एक बार उन्होंने रंगस में सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया लेकिन उसी दिन बी.डी.ओ. के ऑफिस में बी.डी.सी. की मीटिंग थी ,उसमें कोई ऑफिसर हाजिर नहीं था। आप यहां पंचायती राज को मजबूत करने की बात करते हैं। अनिल जी, आपने जिला परिषद के लोगों का पैसा इस करके रोक दिया क्योंकि आपके निर्वाचन क्षेत्र के चारों जिला पार्षद दूसरी पार्टी के हैं और वे अनाउंसमैंट ज्यादा करते हैं---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

24.03.2015/1720/negi/jt/1

श्री विजय अग्निहोत्री .. जारी..

क्योंकि आपके कॉन्टीट्युएंसी के 4 जिला परिषद दूसरी पार्टी के थे और वह एनॉउंसमैन्ट ज्यादा करते हैं। मैं नही बोलता कि आपने ठीक किया। हम उनसे ऊपर

हैं और आप उनसे ऊपर हैं। लेकिन आप छोटी लाईन को छोटी करने के लिए उसको मिटाओ मत बल्कि उससे बड़ी लाईन खींचो। विधायक निधि को एक करोड़ से दो करोड़ पहुंचाओ। आप ज्यादा घोषणाएं करो। लेकिन आप पंचायती राज संस्थाओं को तंग कर रहे हैं लेकिन बजट में आप उनको मजबूत करने की बात करते हैं।

अध्यक्षः विजय जी, आप टाईम देखिए, बहुत टाईम हो गया है, और भी बोलने वाले हैं। आप प्लीज़ वाइंड अप करें।

श्री विजय अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात बोल कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी हाल ही के दौरे में कांगू सब तहसील बनायी गई और उसमें दूर के पटवार सर्कलों को डाल दिया गया और नजदीक का जो बडोग पटवार सर्कल है उसको गलोड में ही रहने दिया। यह विसंगतियां भी दूर होनी चाहिए। जहां तक बजट का प्रश्न है, वह जो कहते हैं :-

बहुत शोर सुना था पहलु में दिल का,
चीरा जो कतराए खून न निकला।

केवल मात्र इसको लिपापोती करने की कोशिश की गई। इसमें कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नही है। इस सरकार की कठिन परिस्थितियों का हाल इससे पता चलता है, जैसे भाई रणधीर शर्मा जी ने भी बताया कि सेलरी देने के लिए ब्लॉक से पैसा मंगवाया है। मैंने भी पता किया ।...(व्यवधान)..

अध्यक्षः प्लीज़ समाप्त कीजिए।

24.03.2015/1720/negi/jt/2

श्री विजय अग्निहोत्री : सर, बस एक बात रिकार्ड में आने दो। नादौन ब्लॉक से भी 1.09 करोड़ रूपये दोबारा सरकार ने वापिस ट्रेजरी में जमा करवाया। हमीरपुर ब्लॉक से 47 लाख रूपये जमा करवाया। सुजानपुर से भी वापिस मंगवाया। यानि हरेक जगह से पैसा वापिस मंगवाया गया। इस सरकार के पास तनख्वाह देने के

लिए पैसे नही है और आप फिजूल खर्ची में मुस्तैद हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं बजट का समर्थन तो नहीं कर सकता हूं लेकिन कौन समझेगा यहां दिल की जुबां यही सोच कर खामोश हो गया।

24.03.2015/1720/negi/jt/3

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो 18 मार्च को माननीय सदन में अपना 18 वां बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 6वीं बार मुख्य मंत्री बन कर यह बजट पेश किया है और इससे यह साबित होता है कि लोगों के दिलों में मुख्य मंत्री जी के लिए जगह है। यह जो बजट यहां पर रखा गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट विकासोन्मुखी, हर वर्ग को राहत देने वाला तथा कल्याणकारी बजट है जिसकी झलक यह जो बजट बुक है इसको पढ़ने से मिलती है। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हर बिन्दु को अपने 3 घंटे के भाषण में छुआ है। इस बजट पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो हर वर्ग को इसमें राहत मिली है। यहां मेरे एक साथी ग्राम पंचायतों की बात कर रहे थे। मैं ग्राम पंचायत बैजनाथ का एक बार उप-प्रधान और 25 साल प्रधान रहा हूं। जहां तक ग्राम पंचायतों की बात है कोई समय था कि ग्राम पंचायतों में केवल पुरूषों को जगह मिलती थी और एक महिला को पंच बनाया जाता था। लेकिन केन्द्र में जब आदरणीय राजीव गांधी जी हमारे प्रधान मंत्री हुआ करते थे तो उस समय ग्राम पंचायतों को नई दिशा मिली और महिलाओं को 50 परसेन्ट आरक्षण उस समय मिला। प्रदेश में थ्री टायर सिस्टम शुरू हुआ जो पहले नही हुआ करता था। ग्राम पंचायतें बनी, पंचायत समितियां बनीं और जिला परिषदें बनीं और महिलाओं को पंचायत में पंच, प्रधान, उप-प्रधान, जिला परिषद मेम्बर और हमारे पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जिला परिषद के मेम्बर, जिला परिषद के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज महिलाएं ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

24.03.2015/1725/यूके/1

श्री किशोरी लाल--- जारी----
आज महिलाएं पुरूषों के बराबर पंचायतों में काम कर रही हैं। जो हमारा इस साल का बजट आया है, उसमें 109 करोड़ रूपए की जगह आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 195 करोड़ रुपए का बजट पंचायतों को जारी करने का यहां प्रस्ताव किया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पंचायत एक ऐसी कड़ी है, जो सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन्हें लागू करती है और गांवों में सस्ता न्याय, सरकार की सारी योजनाएं, जिनको सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए, गांव में जरूरतमंद लोगों को रोजगार जैसे मनरेगा स्कीम, हमारी केन्द्र सरकार ने शुरु की थी। कई गांववासियों को व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, गांव से पलायन रुका।IRDP का सर्वे जो हमारी ग्राम सभा होता है, आज प्रदेश में साल में 4 ग्राम सभाएं होती हैं, उनमें होता है। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर कहीं बेहतर हुआ है। उनको घर द्वार पर सस्ता न्याय मिला है। ग्राम पंचायत में वकील नहीं करने पड़ते। आदमी खुद ही आरगुमैंट करता है और सस्ता न्याय उनको वहां घर द्वार पर मिलता है। तो यह जो मेरे साथी कह कह कर गए कि हमारे आदरणीय शर्मा जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने जिला परिषद का बजट कम कर दिया। अरे, यह बजट तो केन्द्र से प्रदेश को आता है, वहां से कम हुआ तो यहां पर भी कम हो गया। इसमें कोई विसंगति नहीं है। यहां पर बहुत हल्ला सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हुआ कि यहां केवल 50 रुपए बढ़ाए गए।

24.03./20151725/यूके/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री विजय अग्निहोत्री जी ने जिला परिषद की बात उठायी थी कि 13वें वित्तयोग में जिला परिषद के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला। ये हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। हमने कोई पैसा जिला परिषद का नहीं काटा है क्योंकि 14वें वित्तायोग की जो टीम यहां पर आयी थी, उन्होंने कहा कि जिला परिषद इस पैसे को मिसयूटिलाईज़ कर रही है और उसकी गाईड लाईन को चेंज करने के लिए हमने विधायक निधि की तरह जिला परिषद के सदस्य एनाऊसमैंट करते थे जब कि हाऊस के अन्दर उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि 13वें वित्तायोग ने कहा था 70% पैसा पंचायत को जाना चाहिए था। जो कि आपने पंचायतों को न दे

कर 50% पैसा जिला परिषद को दिया है । आपके समय में जो राजनीति हुई थी, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि उस वक्त जिला परिषद में 50% पैसा गया था। लेकिन इस 14वें वित्तायोग के अन्दर जीरो, एक पैसा भी जिला परिषद को नहीं आया है । अब 14वें वित्तायोग का पैसा यदि केन्द्र सरकार से आया है तो जीरो पैसा आया है वहां से । इसमें जिला परिषद के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है ,न ही ब्लॉक समिति के लिए । इसलिए आप मिसलीड कर रहे हैं । (व्यवधान) नहीं सर, बात यह है कि जो इन्होंने बात उठायी है, उसमें 13वें वित्तायोग के अन्दर 70 से 75% पैसा वह सीधा जिला परिषद से नहीं वह पंचायत को जाना चाहिए था । यह गाईड लाईन

24.03.2015/1725/यूके/3

के अन्दर है । यदि आप चाहें तो मैं गाईड लाईन की कॉपी हाऊस के अन्दर रखने के लिए तैयार हूं ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, हम श्री किशोरी लाल जी को भी कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहते थे । 50% आरक्षण महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किया था, यह राजीव गांधी जी के टाईम में नहीं हुआ था, पहली बात तो यह है। दूसरे ग्राम सभा 4 होंगी यह हमने डेट्स तय करके किया था । जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिला परिषद के लिए पैसा नहीं दिया । 14वें वित्तायोग ने या इन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 की केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया । माननीय मंत्री जी बहुत समझदार हैं, इनको सब पता है । PRI और ULB का मतलब क्या है? PRI पंचायती राज इन्स्टीट्यूश्न्ज़ है और ULB अरबन लोकल बॉडीज़ है, उसमें नगर परिषद, नगर पंचायतें और नगर निगम आयेगा और PRI में पंचायतें विकास समिति और जिला परिषद है। इसलिए पैसा एक हैड में आया है, वह सबके लिए है । आप इस तरह नहीं कह सकते ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः जो पैसा आया है

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.03.2015/1730/sls-jt-1

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ..जारी
मैं 14वें वित्तायोग की बात कर रहा हूं। 14वें वित्तायोग में जो पैसा आया है वह न तो जिला परिषदों के लिए हैं और न ब्लॉक समितियों के लिए है। वह 100% पैसा केवल पंचायतों के लिए आया है ,मैं यह कहना चाहता हूं। उसमें सर, स्पैसिफिकली कहा गया है कि वह पैसा 100 प्रतिशत् पंचायतों के लिए आएगा। उसमें जिला परिषद का नाम नहीं है और न ही ब्लॉक समिति का नाम है। ...(व्यवधान)... पी.आर.आई. में तीनों आते हैं। 13वें वित्तायोग की गाईडलाईंज में उन्होंने स्पैसिफिकली डिटेल्ज दी थी कि 75 प्रतिशत् पैसा पंचायतों को जाएगा परंतु उसमें जिला परिषद् को 50 प्रतिशत् गया था। यह मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल :पी.आर.आई. में तीनों कवर होते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : तीनों कवर होते हैं लेकिन 14वें वित्तायोग में स्पैसिफिकली जिला परिषद् को इसमें बाहर किया है और 100 प्रतिशत् पैसा पंचायतों को आएगा और पंचायतें ही उसका आबंटन करेंगी। ...(व्यवधान)...यह नीति आयोग का कमाल है।

अध्यक्ष : किशोरी लाल जी, आप बोलिए।

श्री किशोरी लालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक सुरक्षा पैंशन का प्रश्न है, जो विधवा पैंशन है उसे 550 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपया किया गया। जो अपंग हैं उन्हें 750 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया पैशन की गई। 80 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को 1000 रुपया दिया गया। जो 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध हैं, उनके चाहे कितने बच्चे सरकारी नौकरी में हों ,कितनी भी आय हो, उन सभी को 1000 रुपया पैंशन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ऐसी भी सरकारें रही कि पैंशन पाने वाले को, जब कोई पैंशनधारक व्यक्ति मरता था, तब उसे पैंशन लगती थी। ऐसी भी व्यवस्था रही है और आपकी सरकार के समय

24.03.2015/1730/sls-jt-2

में रही है।...(व्यवधान)... माफ करना, मुझे याद है और मैं इस बात को बेहतर जानता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों ,जैसे सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा बिनने वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं या टैक्सी चालक हैं ,ऐसे4 . 48लाख जो लाभार्थी हैं उनको स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवा कर स्वास्थ्य बीमा लाभ देकर बड़ी राहत प्रदान की है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 37 लाख लोगों को राजीव गान्धी अन्न योजना के दायरे में लाकर 3 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा 2 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रदान किया जा रहा है। आवास निर्माण के लिए जो 48,500 रुपये की सहायता मिलती थी ,आज सरकार उन्हें 75000 रुपया दे रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को मकान मुरम्मत के लिए 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। विभिन्न कल्याण योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आय सीमा को 20000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये किया गया। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए स्कूल खुले और कई अपग्रेड हुए। प्रदेश में 14 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। यह कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में खुले जहां गरीब बच्चे दूसरी जगह शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे। खासकर जो हमारी ग्रामीण बच्चियां थीं उनके परिवारजन अपनी बच्चियों को दूर नहीं भेज सकते थे जिन्हें अब यह सुविधा घर-द्वार प्राप्त हुई है। इससे प्रदेश में जो शिक्षा से वंचित गरीब लोग थे, उन्हें वहां शिक्षा प्राप्त होगी। इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। मुझे वह समय याद आता है जब इस प्रदेश में शिक्षा का अभाव था और हमारे बच्चों को क्या नौकरी मिलती थी? पंजाब में कहीं होटल में नौकरी मिल गई और वह लोग कहते थे कि हिमाचल से 'मुण्डु' लाना। लेकिन आज वह व्यवस्था इस सरकार ने खत्म की है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अब वह मुण्डुओं वाला समय नहीं है। आज लोग शिक्षित होकर फ़ौज में

24.03.2015/1730/sls-jt-3

और प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, प्रदेश के सरकारी दायरे में नौकरी कर रहे हैं।

जारी ..गर्ग जी

24/03/2015/1735/RG/AG/1

श्री किशोरी लाल-------क्रमागत
आज किसान जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए इस सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। एक 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' शुरू की है जिससे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और किसान खेती की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। जहां तक किसानों को नए औजार या आधुनिक औजार उपलब्ध कराने का प्रश्न है जैसे पॉवर ट्रेलर या अन्य कई औजार हैं ,तो ये कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में विकसित हुए हैं। इन औजारों की प्रदर्शनियां वहां लगाई जा रही हैं जिससे प्रदेश के किसान अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह किसानों में एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है। सबसिडायज्ड बीज एवं दवाइयां किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पहले से ही फ्री ट्रैवल की सुविधा सरकारी बसों में उपलब्ध थी, परन्तु अब केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों को भी आदरणीय मुख्य मंत्री द्वारा यह फ्री सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, विधायक क्षेत्र विकास निधि जो पहले पचास लाख रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर अब 70,00,000/-रुपये किया गया है जिसमें बीस लाख रुपये प्रदेश के किसानों के लिए रखा गया है जिसे लघु सिंचाई कार्य, कुहलों, तालाबों तथा कमांद क्षेत्र विकास के लिए खर्च किया जाएगा। यह जो बीस लाख रुपये बढ़े हैं इन्हें विकास के साधनों के लिए डायवर्ट करना जरूरी है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से अपील करुंगा कि ये जो बीस लाख रुपये हैं जो हमें पचास लाख रुपये मिलते थे ,इन्हें भी उसी तरह खर्च करने का अधिकार हमें दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनता को खाद्य वस्तुओं में उपदान के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को तीन दालें, दो खाद्य तेल ,आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध

करवाकर वर्ष 2015-16 में भी 210करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही प्रदेश में लागू की थी जो वर्ष 2007 से शुरू है। खाद्यान भण्डारण के निर्माण के लिए भी चार करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल उठाने की आवश्यकता रहती है। इसलिए किसान समूहों को उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवैल स्थापित

24/03/2015/1735/RG/AG/2

करने के लिए 50प्रतिशत उपदान दिया जाना इस बजट में प्रस्तावित है। जिससे किसानों की आर्थिक हालत सुदृढ़ होगी। किसानों के स्वायल में सुधार के लिए स्वायल हैल्थ काड्‌र्ज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसमें किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच होगी और उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा। बेमौसमी सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए गौ-सदन खोलने के प्रयास एक सराहनीय कदम है। सरकार प्रदेश में अधिक-से-अधिक गौ-सदन खोलने के लिए प्रयासरत है। जब ये गौ-सदन खुल जाएंगे, तो आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिलेगी। इसके लिए 'गोवंश सम्वर्द्धन बोर्ड' का गठन करना तथा वर्ष 2015-16 के बजट में 10 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। जोकि एक सराहनीय कदम है। इससे किसानों को और मजबूती मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में बी.ए.एम.एस. की 50 सीटों को बढ़ाकर 60 किया जाना भी बहुत अच्छा कदम है। इसमें 10 सीटें बढ़ी हैं जिसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि बैजनाथ में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसकी 10 सीटें बढ़ी हैं। आयुर्वेदा विभाग को बजट में 218 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारे यहां केवल बस से ही यात्रा करनी पड़ती है। यहां रेल तो बहुत ही कम स्थानों पर उपलब्ध है। अब हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 500 नई बसें खरीद ली हैं------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1740/MS/Ag/1

श्री किशोरी लाल जारी----------

इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 500 नई बसें खरीद ली हैं और 800 और नई बसें JNNURM के अन्तर्गत खरीदी जा रही हैं, इसके लिए भी मैं आदरणीय परिवहन मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। इससे यहां यातायात सुविधाओं को इजाफा मिलेगा। जो हमारे बस अड्डे हैं, वहां पर शौचालय का निर्माण होगा, इसके लिए भी 10 करोड़ रूपये का बजट बुक में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 5 लाख से कम कारोबार करने वाले ढाबा, हलवाई, चाय तथा चाट इत्यादि की दुकान करने वाले जो लोग हैं उनको मूल्यवर्द्धन कर में छूट को बढ़ाकर 8 लाख रूपये कर दिया है। इससे हमारे जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। इसी तरह से प्रदेश में 25 लाख रूपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को जोकि प्रदेश में 47 हजार छोटे व्यापारी हैं पहली बार 2 लाख का समूह दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत आएंगे और इस बीमे का प्रिमियम भी सरकार अदा करेगी। इससे हमारे जो व्यापारी हैं वे लाभान्वित होंगे।

यहां पर सरकारों का जिक्र आया। मैं बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में प्रदेश में आदरणीय श्री शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और उसमें 60 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 8 कांग्रेस के जीतकर आए थे। लेकिन वह सरकार ढाई साल से ज्यादा नहीं चली। जो 60 विधायक थे उन्होंने ही मुख्य मंत्री को छोड़ दिया। तो ऐसी सरकारें प्रदेश में रही हैं। मैं शांता कुमार जी को बड़े नजदीक से जानता हूं। वह मेरे पड़ोसी हैं। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जो सरकार थी, उसने वायदे तो बहुत किए थे लेकिन पूरे कम हुए। प्रदेश के लोगों को कोई जन-कल्याण की योजनाएं उस वक्त मुहैया नहीं हुई, केवल कागजी भाषण उस वक्त हुआ करते थे। दुबारा वर्ष 1990में पुनः आदरणीय शांता कुमार जी सत्ता में आए लेकिन उस वक्त क्या हुआ? देश में जनता दल की सरकार थी और विश्वनाथ

प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे। प्रदेश में शांता जी मुख्य मंत्री थे। 27 प्रतिशत आरक्षण ओ0बी0सी0 को मिलना था और उसका इन्होंने विरोध किया। प्रदेश के जो हमारे नेता थे, मंत्री थे और विधायक थे, वे जगह-जगह पर गाड़ियां रोकते रहे। प्रदेश में बहुत बुरा हाल उन्होंने किया। अब किसानों की बात करता हूं। किसानों ने भी

24/03/2015/1740/MS/Ag/2

आंदोलन किए। उनको भी डण्डे बरसाए गए। पंजाब से कमाण्डो मंगवाए गए और गोलियां चलवाई गई। यह हालत उस वक्त की थी। आज कहते हैं कि प्रदेश में कानून- व्यवस्था की स्थिति खराब है। कौन से कानून-व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? अपनी ओर तो जरा ध्यान दो। वे निहत्थे किसान क्या कर रहे थे? वे अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनके ऊपर जो गोलियां चलवाई, वह कौन सा न्याय था? आज आप कह रहे हैं कि यहां पर बड़ा-भारी काण्ड हो गया। क्या काण्ड हो गया? ठीक है, सबका अधिकार है कि प्रदर्शन करे लेकिन झगड़ा दो तरफ से होता है। हम अगर आपस में न झगड़े तो झगड़ा कैसे होगा? इसलिए झगड़ा दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से नहीं होता है। इसमें कोई कानून-व्यवस्था की बात नहीं है। मेरे यहां पर मित्र जिन्होंने एक ही रटा लगा रखा है कि "पढ़-पढ़ बोबो गंगा राम"। बस एक ही रटा लगा रखा है कि सरकार का विरोध करना है। अच्छी चीजों की तो बात करो। मैंने कई बजट देखे और पढ़े हैं। लेकिन यह जो बजट है ,यह सब वर्गों को राहत देने वाला है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

यहां पर माननीय धूमल जी ने पिछले दिनों मेरा पक्ष भी रखा, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उतराला-होली सुरंग जो उतराला से बननी प्रस्तावित थी तो मैं चाहूंगा कि वह सुरंग वहां से बनें। इसके अलावा बैजनाथ-पपरोला नगर पंचायत का गठन होने जा रहा है। माननीय शहरी विकास मंत्री यहां बैठे हैं तो कृपा करके जो गांव गडथोली, पंतेड़,उस्तेड़, सीतला और पपरोला खास, गणखेतर और कोठी है, इनको नगर पंचायत से बाहर किया जाए। यह मेरी गुजारिश रहेगी। मैं बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बढ़िया बजट है। अब मैं अधिक न कहता हुआ अपना सम्बोधन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा-----

4.03.2015/1645/जेके/एजी/1

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष जी, 18 मार्च, 2015 को जो बजट प्रदेश के मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसी भी प्रदेश का बजट उस सरकार की दशा और दिशा की ओर इंगित करता है। जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया उससे यह पता चलता है कि यह सरकार इस प्रदेश को किस ओर ले जा रही है, उस ओर इशारा करती है? इस बजट में किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। आज हर वर्ग चाहे मज़दूर वर्ग है, किसान-बागवान, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, युवा वर्ग, कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग है इस बजट से सभी वर्ग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 30 दिसम्बर, 2007 को उस समय के मुख्य मंत्री, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने सत्ता सम्भाली थी। पहले ही दिन हमारा जो सबसे गरीब वर्ग यानि मजदूर वर्ग है उसकी दिहाड़ी 75 रूपये से 100 रूपये की गई थी। उस दिहाड़ी को डेढ़ सौ रूपए तक बढ़ाया गया। इस बजट में आपने देखा होगा कि इस मंहगाई के ज़माने में पिछले दो वर्षों में मात्र इसमें 20 रूपये की वृद्धि हुई है जो कि बहुत ही नाकाफी है। इसी प्रकार से किसानों की बात यहां पर की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आदरणीय धूमल जी ने किसानों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से किसान-बागवान समृद्धि योजना लागू की थी। जिसमें पोली हाऊसिज निर्माण के लिए 85 प्रतिशत अनुदान और जो बी.पी.एल. परिवार थे उनके लिए 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया था। लेकिन इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल कर डॉ0 वाई.एस. परमार के नाम से स्वरोजगार योजना चालाई। उसमें 85 प्रतिशत अनुदान रखा गया और बी.पी.एल. परिवारों के लिए उसमें कोई विशेष छूट नहीं दी गई थी। इसी प्रकार से यहां पर महिला वर्ग की भी बात करना चाहूंगा। भाई किशोरी लाल जी भी यहां पर कह रहे थे। आदरणीय धूमल जी ने प्रदेश में महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए दूध

4.03.2015/1645/जेके/एजी/2

गंगा योजना शुरू की थी। महिला सशक्तिकरण के लिए माता शबरी योजना शुरू की थी। इस बजट में इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। युवा वर्ग जिनको बेरोजगारी भत्ता दे कर यह सरकार सत्ता में आई। इस बजट में उसके बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। अनुसूचित जाति वर्ग जिसके समय में पूर्व सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र में 10-10 लाख रूपये की लागत से अम्बेदकर भवन का निर्माण किया। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 25 प्रतिशत है। एस.सी. और एस.टी. के तहत 25 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया। इस बजट में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जिसमें कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई विशेष ध्यान रखा गया हो। मेरे हिसाब से कुल मिला करके यह बजट दिशाहीन है। आंकड़ों का मात्र मायाजाल है । इसमें किसी भी वर्ग को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। मैं इन आंकड़ों में न जा कर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजकल विकास केवल नाम की पट्टिकाएं, उदघाटन और शिलान्यास को ही माना जा रहा है। सरकार के जो ऊंचे ओहदेदार हैं, वे केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो काम हुए थे जिनके लिए बजट का प्रावधान किया गया था उनका ये लोग शिलान्यास कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है जब शिलान्यास होता है उसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला यानि एक चपड़ासी से लेकर सभी अधिकारीगण और कर्मचारी साथ में होते हैं तथा ऑफिस खाली हो जाते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

24.03.2015/1750/SS-jt/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागतः

और ऑफिस खाली होते हैं और वहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़कों की अगर आज स्थिति देखें तो भाई रोहित जी भी यहां ज़िक्र कर रहे थे कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क छैला-नेरीपुल-ओचघाट है ,जिसमें कि शिमला, सोलन और राजगढ़ डिवीजन आते हैं। जिसका कि 42 किलोमीटर हिस्सा राजगढ़ डिवीजन मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। सेब के सीज़न में शिमला

डिस्ट्रिक्ट का पूरा सेब इस सड़क से देश की मंडियों में भेजा जाता है। यह सड़क जोकि स्टेट हाईवे नम्बर-6 है आज इस स्टेट हाईवे की स्थिति किसी लिंक रोड से भी बदतर है। आज सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। प्रतिवर्ष सेब के सीजन में इस वजह से अनेकों एक्सीडेंट होते हैं और हमारे सैंकड़ों किसान भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज इस सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस सड़क को वर्ल्ड बैंक की किसी बड़ी योजना में डाला जाए। जब श्री प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे और पराला में सब्जी मंडी का शिलान्यास हुआ था तो उस समय इस सड़क की घोषणा की गई थी। इसको होर्टिकल्चर सड़क का नाम दिया गया था और 121 करोड़ की लागत से इसकी डी0पी0आर0 बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी गई थी। लेकिन उस समय केन्द्र में यू0पी0ए0 सरकार थी। वह डी0पी0आर0 मंजूर नहीं हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी बड़े प्रोजैक्ट के तहत इस महत्वपूर्ण सड़क को डाला जाए ताकि इस सड़क की दशा सुधारी जा सके। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क सोलन-मीनस मार्ग है जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर जो हमारे सी0पी0एस0 रेणुका जी से है उनके विधान सभा क्षेत्र को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसकी भी हालत बहुत खराब है। दूसरी सड़क वाथल-मेठी-राजगढ़-चंदोल सड़क है जोकि नाहन, रेणुका और पच्छाद विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है। लगभग 142 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इसकी हालत भी बहुत दयनीय है। इस सड़क की स्थिति को भी सुधारा जाए। जो छोटी-छोटी लिंक रोड चाहे सराहां से नारंग सड़क की बात हो या राजगढ़-मानवा सड़क हो, इनकी हालत और भी दयनीय है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इन सड़कों की दशा को सुधारा जाए।

24.03.2015/1750/SS-jt/2

शिक्षा की बात मैं यहां पर करना चाहूंगा। मुझ से पूर्ववक्ताओं ने इसके ऊपर बहुत-सी बातें यहां पर कीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत से स्कूल खोले गए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु बड़े दुख की बात है कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 57 जे0बी0टी0 टीचर की पोस्टस खाली हैं और 12 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी जे0बी0टी0 टीचर नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा एक बहुत ही खेद का विषय है। ट्रांसफर पर बैन था परन्तु बैन के बावजूद भी चहेते टीचरों की

ट्रांसफर की गई। लगातार पूरे वर्ष ट्रांसफर होती रहीं। चहेते टीचरों को डैपुटेशन पर भेजा गया और भेजा जा रहा है। इससे भी बड़ा विषय यह है कि डैपुटेशन के ऊपर डैपुटेशन किया गया। पहले एक टीचर को खाली जगह डिप्यूट किया गया, उसके बाद उसकी जगह दूसरा टीचर डिप्यूट कर दिया गया। इस प्रकार से चहेते टीचरों को मनचाहे स्टेशनों पर डिप्यूट किया जा रहा है। रोज़ वहां पर अध्यापक डिप्यूट करके भेजे जा रहे हैं। वे वहां पर बच्चों को पढ़ाने का कार्य न करके कांग्रेस पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। आज यह स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। बहुत ही हैरानी की बात है कि प्लानिंग बोर्ड के वाइस चैयरमैन के प्राइवेट सैक्रेटरी टेलीफोनिक मैसेज देते हैं और टेलीफोनिक मैसेज के ऊपर अध्यापकों के डैपुटेशन कर दिए जाते हैं। इससे हैरत की बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय में कॉलेज खोला गया, जिसको कि वर्तमान सरकार ने आते ही बंद कर दिया। उस समय यह कहा गया कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं और 6 महीने के बाद दोबारा वहीं पर उसी बिल्डिंग में बिना आधारभूत ढांचे और सुविधाओं के पुनः कॉलेज शुरू कर दिया गया।

जारी श्रीमती के0एस0

24.03.2015/1755/केएस/जेटी/1

श्री सुरेश कुमार जारी---
और दुख की बात यह है कि उस समय चार कमरे थे और जब दूसरी बार खुला तो वहां मात्र तीन कमरों में कॉलेज खोल दिया गया। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने इस कॉलेज के भवन के लिए रूसा के तहत 12 करोड़ रुपये दिए हैं परन्तु अभी तक इस कॉलेज की बिल्डिंग का काम भी शुरू नहीं हो सका। यही स्थिति आई.टी.आई. भवनों की है वह चाहे राजगढ़ की आई.टी.आई. का भवन है या सराहां की आई.टी.आई. भवन है।

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता यहां पर कह रहे थे आज जो स्कूल खुले हैं उनमें अध्यापकों की बहुत कमी है और जो यहां पर बात हो रही थी कि दो अध्यापक और एक बच्चा, तो यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक स्कूल को अपग्रेड करके प्राईमरी से मिडल बनाया गया। वहां पर छठी क्लास में मात्र एक ही बच्चा है और वहां पर एक रैगुलर टीचर और एक टीचर को

डिप्यूट किया गया है। अब आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि एक टीचर को महीने में 50 हजार रुपये मिलते हैं और दो टीचर्ज़ एक लाख रुपये सैलरी लेते हैं तो उनका अगर साल का जोड़ा जाए तो 12 लाख रुपये उनको मिलते हैं और एक बच्चे के ऊपर अगर एक साल में 12 लाख रुपये खर्च किए जाएं तो हिन्दुस्तान की जगह उसको अमेरीका में पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह स्थिति है। मेरे यहां ऐसे बहुत से स्कूल है जहां पर कि छठी क्लास में दो-तीन बच्चे हैं और जो प्लस टू क्लास तक स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, दो-तीन स्कूल ऐसे हैं, मढ़ीघाट, मांढियाघाट, मेहंदोबाग के स्कूलों में मात्र तीन-तीन बच्चों ने एडमिशन ली थी ओर कुछ दिनों के बाद

24.03.2015/1755/केएस/जेटी/2

वे बच्चे भी दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। इन स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के बाद आज प्लस वन में वहां एक भी बच्चा नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जहां पर टीचर्ज़ नहीं है, वहां टीचर्ज़ भेजे जाएं।

अध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों में सबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड से टीचर भर्ती न करके बैकडोर एंट्री की जा रही है। इससे पूर्व भी चाहे पी.टी.ए. की बात थी, पैट की बात थी और अब एस.एम.सी. के तहत बैकडोर एंट्री से टीचर्ज़ लगाए जा रहे हैं। इसमें रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज पी.टी.ए. को काँट्रेक्ट दिया जा रहा है परन्तु इसमें भी उस समय रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओ.बी.सी. वर्ग आरक्षण से वंचित है । अभी जो एस.एम.सी. टीचर्ज़ रखे गए हैं, क्योंकि उसमें पीरियड आधार पर भर्ती हो रही है तो उसमें भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आशा वर्करों की नियुक्ति हुई उसमें भी रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं था। जब भर्तियां बैकडोर से हो रही है तो इस प्रकार का प्रावधान नहीं हो सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भले ही आपने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए चाहे पी.टी.ए., एस.एम.सी. या दूसरे प्रबन्ध किए हों परन्तु सबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड के तहत भी भर्तियां

की जाए और उसमें जो भी आरक्षित वर्ग है उसको भी इसमें आरक्षण का लाभ मिल सके।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। अब आप कितनी देर बोलना चाहेंगें?

24.03.2015/1755/केएस/जेटी/3

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, पांच-सात मिनट और बालूंगा।

अध्यक्षः इसके बाद एक माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं और उनको भी 15-20 मिनट बोलना है तो इस माननीय सदन की बैठक आधा घण्टा, साढ़े छः बजे तक और बढ़ाई जाती है। Please continue.

(माननीय सदन की बैठक का समय सांय साढ़ छः बजे तक बढ़ाया जाता है)

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं पटवारियों की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 42 पटवार सर्कल है जिसमें से 22 पटवार सर्कल खाली है और आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पटवारी नहीं होगा तो किस प्रकार से, चाहे कोई सड़क बननी है, कोई भवन बनना है, कोई विकास का काम होना है, पटवारी ही नहीं होगा तो यह सम्भव ही नहीं हो सकता। बड़े खेद का विषय है कि एक-एक पटवारी के पास सात-सात पटवार सर्कल भी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नौरी में एक पटवारी के पास सात पटवार सर्कल है तो आप खुद ही अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि एक पटवारी अगर सात दिन भी सातों पटवार सर्कलों में जाएगा तो किस प्रकार से वहां का कार्य प्रभावित होगा।

अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जी यहां पर नहीं है। मैं टी.डी. के बारे में बात करना चाहूंगा। पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जिनके टी.डी. राइट्स हैं, उनको टी.डी. का अधिकार दिया गया था परन्तु बड़ा दुख का विषय है कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो टी.डी. दी जा रही है वह पिक एण्ड चूज़ के आधार पर दी जा रही है।

श्रीमती अ0व0 जारी---

24.3.2015/1800/जेटी/av/1

श्री सुरैश कुमार ----जारी
आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो टी.डी. दी जा रही है वह पिक एण्ड चूज के आधार पर दी जा रही है। अगर किसी नेता का फोन करवाओ तो आपको टी.डी. मिलेगी नहीं तो आपको टी.डी.नहीं मिलेगी। गरीब लोग जिनको इसका फायदा मिलना चाहिए था और जिनके टी.डी. राइट्स हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। केवल रसूखदार लोगों को इसका फायदा मिल रहा है।

यहां पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा का प्रावधान किया गया है। मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बसें ही नहीं है तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को इसका लाभ कहां से मिलेगा? मैं आदरणीय बाली जी से प्रार्थना करना चाहूंगा। मैंने पहले भी निवेदन किया है और लिखकर भी दिया है कि जहां पर बसिज नहीं हैं वहां पर बसिज चलाई जाएं।

बाकी टूरिज्म के बारे में यहां पर बात की गई है। मुझे जब भी बजट पर बोलने का मौका मिला मैंने इस बारे में बात की है। वैसे तो पूरे सिरमौर जिला में टूरिज्म का स्कोप है। मगर जहां तक रीलिजियस टूरिज्म की बात है तो हमारे पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में इसको काफी बढ़ावा दिया जा सकता है। शिरगुल महादेव की जन्मस्थली शाया मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है। विशेषकर उत्तर भारत के लोग शिरगुल महादेव को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसलिए उनकी जन्मस्थली को रीलिजियस टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हब्बन का क्षेत्र है। वहां पर ट्रैकिंग की सुविधा विकसित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई दूसरे ट्रैक रूट्स भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में बनाये जा सकते हैं। परंतु पिछले दो वर्षों के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 12 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। उसमें केवल मंदिरों का प्रांगण या स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि लगाने के लिए धन का प्रावधान किया गया। केवलमात्र स्ट्रीट लाइट्स लगाने से टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिल सकता। हम चाहे रीलिजियस टूरिज्म की बात करें या आयुर्वेदा से टूरिज्म को जोड़कर देखा जाए। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात भी करना चाहूंगा। मेरे

24.3.2015/1800/जेटी/av/2

विधान सभा क्षेत्र में सेरगास जगह पड़ती है और आजकल वहां पैराग्लाईडिंग का प्रशिक्षण भी चल रहा है। उस जगह को पैराग्लाईडिंग के लिए विकसित किया जाए। मगर इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। वर्ष 2012 में सराहं में इन्होंने वे-साइट अमैनिटीज के लिए 80 लाख रुपये की राशि दी थी। उस राशि से वहां टूरिज्म रिसैप्शन सैंटर व वे साइट अमैनिटीज के भवन का शिलान्यास किया था। आज उसका कार्य चल रहा है। इसके अलावा आप देखें, सराहं-कुमारहट्टी-नाहन के बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जहां टूरिज्म की बहुत सम्भावना है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। वहां पर टूरिज्म को विकसित किया जाए। मैं इस सदन के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। यहां पर पंचायती राज मंत्री विराजमान है। कल ही विधान सभा के अंदर प्रश्न लगा था जिसके उत्तर में यह बताया गया था कि गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 52 प्रधानों को सस्पैंड किया गया। जिनमें से 11 प्रधान जिला सिरमौर से हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उनमें से चार प्रधान मेरे विधान सभा क्षेत्र से हैं जिसमें से दो को टर्मिनेट कर दिया गया और दो को सस्पैंड किया गया। उनमें से एक प्रधान को मात्र इसलिए किया गया क्योंकि उसने चैक की जगह कैश पेमैंट की थी और वह भी मात्र 1696 रुपये की पेमैंट थी। उसको उसके लिए सस्पैंड कर दिया गया जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक आधार पर प्रधानों को सस्पैंड नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से कांग्रेस पार्टी के प्रधानों के खिलाफ भी इस प्रकार की शिकायतें मिली है। मगर केवल भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधानों को ही सस्पैंड किया गया जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसकी जांच करवाई जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन प्रधानों को गैर कानूनी ढंग से सस्पैंड या टर्मिनेट किया गया उन्हें पुनः बहाल किया जाए।

अध्यक्ष : प्लीज, बाइंड-अप कीजिए।

श्री सुरैश कुमार श्री बी.जे.द्वारा दोबारा जारी

24.03.2015/1805/negi/ag/1

श्री सुरेश कुमार .. जारी..
मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन के लिए पिछली बजट में आय सीमा 15 हजार रूपये से बढ़ा कर 20 हजार रूपये किया गया था। परन्तु चाहे पैंशन की बात है या गृह निर्माण की बात है उसमें आय सीमा 35 हजार रूपये है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस आय सीमा को भी 35 हजार रूपये किया जाए। क्योंकि अन्य कामों के लिए आय 3 5हजार रूपये कर दी गई है इसलिए आज के समय में कोई भी पटवारी 20 हजार रूपये आय सीमा देने में एग्री नही होते है इसलिए इस आय सीमा को भी बढ़ा दिया जाए। यहां पर जो विधायक निधि बढा दी गई है उसको एक करोड़ रूपये किया जाए और इसमें जो राइडर लगा दिया गया है उस राइडर को हटा दिया जाए। जो हमारी छोटी-छोटी लिंक रोडज हैं या अन्य मेन्टेनैंस और रिपेयर के काम हैं उनको भी विधायक निधि से जोड़ा जाए। ऐच्छिक निधि जो 2 लाख रूपये है इसको बढ़ा कर कम से कम 5 लाख रूपये किया जाए। अंत में एक अन्य बात मैं कहना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो 4- 4सी.एफ.एल. बल्ब सभी परिवारों को मुफ्त मिलते थे परन्तु इस सरकार ने इस बजट में 3 एल.ई.डी. बल्ब वो भी 150 रूपये प्रति बल्ब के हिसाब से देने का प्रावधान किया है। ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि 3 की जगह 4 बल्ब और चारों बल्ब मुफ्त में दिए जाएं जैसा कि पूर्व सरकार ने भी दिए थे। ऐसा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। बाकी इस बजट में ऐसा कुछ नही है कि मैं इसका समर्थन कर सकूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जयहिन्द, जय हिमाचल।

समाप्त

24.03.2015/1805/negi/ag/2

अध्यक्षः अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट 18 मार्च, 2015 को 18वां बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस मान्य सदन में रखा, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ..

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष का यह दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि इस मान्य सदन में कोरम हो। अगर अभी की स्थिति देखें तो कोरम इस हाऊस में नहीं है। और मुझे लगता है कि इतनी गम्भीर चर्चा इस बजट पर हो रही है और सरकार ही इस बजट को गम्भीरता से नही ले रही है । ऐसी परिस्थिति बहुत कम देखने को इस मान्य सदन में मिली है। लेकिन इस बात पर निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को विचार करना चाहिए।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो 18वां बजट इस सदन में पेश किया गया उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। इस बजट में सभी जाति, वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है । वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी डिटेल में इस चर्चा में भाग लिया। फिर भी मैं इस मान्य सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ जो इस बजट में कुछ हाईलाइट्स हैं उनको मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काफी चर्चा की गई है। विपक्ष की ओर से काफी आलोचनाएं हुई है, कहा गया कि कहीं किसी स्कूल में दो टीचर हैं। कहीं किसी स्कूल में एक भी टीचर नही है । ऐसी चर्चाएं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने अपने समय में स्कूल खोले नहीं बल्कि बन्द किए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

24.03.2015/1810/यूके/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा---जारी----

पिछले सरकार ने तो अपने समय में स्कूल खोले नहीं बल्कि बन्द किए ,काफी स्कूल बन्द किए और जैसे ही माननीय राजा साहिब ने इस प्रदेश की छठी बार सत्ता संभाली, उन्होंने उन स्कूलों को खोलने के साथ-साथ कई और नए स्कूल भी खोले हैं । यह माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक सराहनीय कदम है । इसके अलावा मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसके मुख्य मंत्री

माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी हैं ,उन्हानें अपने दो वर्ष के कार्यकाल में लगभग 719 नए स्कूल खोले और अपग्रेड किए हैं । यह भी एक सराहनीय कदम है । इसके अलावा 14 डिग्री कॉलेजिज़ खोले गए हैं, जिसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । आज घर-घर हर बच्चे को शिक्षा मिली है । जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि पहले खासकर हमारे कॉलेजिज़, टैन प्लस स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल काफी दूर-दूर तक हुआ करते थे जिससे हमारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रहती थीं । लेकिन आज मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हमारे कई स्कूल और कॉलेजिज़ ऐसे हैं, जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी सरकार का एक सराहनीय कदम है । मेरा अपना मत है कि इसमें विपक्ष को खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, आलोचना नहीं करनी चाहिए । पर यह बात स्वाभाविक है कि विपक्ष हमेशा आलोचना करता आया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचना हर चीज़ की नहीं होनी चाहिए । ऐसा नहीं है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है कि सारा आलोचना का ही है । मैने तो अभी तक विपक्ष

24.03.2015/1810/यूके/2

के एक भी जिसने यहां अपनी बात रखी है, किसी ने भी अगर किसी एक चीज़ के लिए ऐसा कहा हो कि यह बजट अच्छा है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। यहां तक कि कल एक वक्ता यहां से विधायक निधि के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर भी धन्यवाद नहीं किया उन्होंने आलोचना ही की है ।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाली साहब भी बैठे हैं, वे भी बधाई के पात्र हैं । मुझे याद है कि जब 25 दिसम्बर, 2012 को हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात भी करूंगा। हमारे यहां बसें नहीं थी, बसों की बड़ी शॉर्टेज थी । काफी समय तक बसों की कमी रही । परन्तु इन्होंने (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री) अब बसों की कमी पूरी कर दी है । जैसा कि इस बजट में है ,800 नयी बसें JNURM के तहत खरीदने का प्रावधान रखा गया है जो सरकार का एक सराहनीय कदम है । इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का नए बस स्टैंड बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है । 800 पोस्टें का प्रावधान रखा गया है, इन कांस्टेबल की भरती होनी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस चर्चा के

दौरान माननीय सदन को एक बात और कहना चाहूंगा कि आज तक जो पुलिस चौकी हुआ करती थी, उसमें FIR लॉज नहीं की जाती थी। लोगों को काफी परेशानी होती थी। दूर-दूर जाना पड़ता था।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.03.2015/1815/sls-jt-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा ...जारी

क्योंकि एफ.आई.आर. केवल पुलिस स्टेशन में ही लॉज होती थी। इसके लिए जो एग्रीव्ड पार्टी थीं ,उनको दिक्कत होती थी। इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी पुलिस चौकियों को सुबोर्डिनेट पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है जो एक सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हर जगह, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, सब जग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इससे लोगों के चालान भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में लोगों को छोटा-सा चालान भुगतने के लिए भी दूर कोर्ट में जाना पड़ता था। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 Posts/Courts of Mobile Traffic Magistrates create करने की भी घोषणा की है जिससे लोगों को दूर न जाना पड़े और घर-द्वार में न्याय मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सराहनीय कदम जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट को पेश करते हुए उठाया है वह सोशल सिक्योरिटी पैंशन है जो पहले 450 रुपये थी, उसके बाद 500 रुपये हुई और अब 550 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा 1000 रुपये पैंशन भत्ता irrespective of the income 80 साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगा। यह भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है जो एक सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में और भी कई प्रावधान है जिन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उनकी डिटेल्ज दे दी हैं। जैसे हाऊस फाईनैंशियल असिस्टैंस है जो पहले 48500 रुपये मिलता था ,उसको बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात आई कि लगभग 11.50 लाख लोग बेरोजगार हैं। ठीक बात है कि इतने बेरोज़गार होंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना मत है कि सभी बेरोज़गारों की बेरोज़गारी तो एक साथ खत्म नहीं की जा

24.03.2015/1815/sls-jt-2

सकती ,सभी को तो नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन जहां तक अपोजीशन ने इस बजट के बारे में बात की है ,उनका कहना है कि इसमें बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सदन में बताना चाहूंगा कि लगभग 5000 फंक्शनल पोस्टे फिल अप की जाएंगी। इसके अलावा, जैसे मैंने पहले कहा ,800 के करीब कांस्टेबलों की भर्ती, डॉक्टरों की भर्ती तथा और भी विभागों में कई पोस्टों पर भर्ती की जाएंगी जिनके लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। यह भी एक सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक और सराहनीय बात कही गई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु सर्विस के समय ही हो जाती है ,उनके किथ एंड किन को अपनी रोजी-रोटी की बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जो परिवार में कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो जाती है। उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह कंपैशनेट ग्राऊंड पर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं। पहले उसको वह नौकरी पाने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती थी; उसमें इनकम उनके आड़े आती थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें इनकम क्राइटेरिया को 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया है। इससे, जो भी ऐसे केसिज हैं ,क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से ऐसे कंपैशनेट ग्राऊंड वाले केसिज लंबित हैं ,उनको भी बहुत राहत मिलेगी।

यहां पर दिहाड़ी की बात भी कही गई है कि ..

जारी ..गर्ग जी

24/03/2015/1820/RG/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-------क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, यहां दिहाड़ी की बात कही गई है कि 10/-रुपये बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि पहले यह दिहाड़ी 150/-रुपये थी अब उसे बढ़ाकर 170/-रुपया किया गया है और अब इस बजट में डेली वेजिज का 180/-रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पहले ही तीन महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं जिनमें एक शिमला, दूसरा धर्मशाला और तीसरा मण्डी में है। इसके अलावा इस बजट में दो और महिला पुलिस स्टेशन खोलने का प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जिन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को पचास लाख रुपये से बढ़ाकर एकदम सत्तर लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही मेरी भी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना रहेगी कि जो उसमें जो बीस लाख रुपये के लिए गाइडलाइन्ज रखी गई हैं उसको भी पचास लाख की तरह खर्च करने की गाइडलाइन्ज की जाएं ताकि इसको खर्च करना सरल हो। यह मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा। साथ-ही-साथ हमारे श्री संजय रतन जी एवं विपक्ष के विधायकों ने यह बात रखी है कि हमारी ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाया जाए। पांच करोड़ इस बजट में प्रावधान रखा है जिससे मेरे चुनाव क्षेत्र में एच.पी.एम.सी. का जो कोल्ड स्टोर है वह सी.ए. कोल्ड स्टोर में बदला जाएगा जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बजट में इसके अलावा चैनेलाइजेशन ऑफ पॉवर ,जो मेरे चुनाव क्षेत्र में नदी है उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है जो टीकरी से धमवाड़ी तक चैनलाइज होगी जिससे आस-पास के काफी गांव एवं लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि नदी के कटाव से काफी लैण्ड इरोजन हो रहा है। लोगों की खेती को बहुत नुकसान हो रहा है विशेषकर जो लोग धान की खेती लगाते थे बाढ़ के कारण तकरीबन वह सारी जमीन तो खराब हो चुकी है।

Speaker: Please, wind up now.

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां ठियोग-खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड की बात इस सदन में काफी चर्चा में आई है। यह रोड काफी दिनों से

24/03/2015/1820/RG/AG/2

चर्चा में है। वैसे तो मैं रोड के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका कार्य जब हमारी सरकार थी और माननीय राजा साहब मुख्य मंत्री थे उनके समय में इसका कार्य शुरू हुआ था और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसका कार्य बन्द हुआ। क्या कारण रहा? The reasons are best known to them. लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह काम काफी अर्सा तक बंद रहा ,तो ये भी इसके लिए इनिशियेटिव ले सकते थे ,इसको दुबारा से शुरू कर सकते थे। अगर चाइनीज कम्पनी के साथ इनका कोई तालमेल नहीं बन सका ,तो कुछ और कर सकते थे। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25 दिसम्बर, 2012 को इस प्रदेश की बागडोर छठी बार संभाली , वैसे ही पांच दिनों के अंदर इस बारे में मीटिंग ------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

24/03/2015/1825/MS/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी----------

जैसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 25 दिसम्बर, 2012 को इस प्रदेश की बागडोर छठवीं बार सम्भाली वैसे ही पांच दिन के अन्दर इसकी मीटिंग रखी, जिसमें लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी, upto Secretary level, मेरे साथ लगते चुनाव क्षेत्र के माननीय रोहित ठाकुर जी और मुझे भी बुलाया और उसी वक्त समूथली इसकी इनक्वायरी की, उनसे पूछताछ की कि इस रोड का काम क्यों बन्द हुआ , क्या दिक्कत है। उसके बाद शीघ्र ही चाइनीज कम्पनी के साथ जो टैण्डर था उसको रिसींड (rescind) करने के आदेश दिए गए और जो भी टैण्डर की प्रोसेसिंग थी उसके बाद इसका काम इनीशिएट हुआ। आजकल इसका काम चल रहा है। यह ठीक है कि इसका काम अभी धीमी गति से चला हुआ है। उसके लिए मैं सरकार से

अनुरोध करूंगा कि इसको एक्सपीडाइट करने के आदेश दिए जाएं। इसका काम दुबारा भी माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के अनुसार ही शुरू हुआ। जैसे मेरे सहयोगी मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर जी ने कहा कि हमारे 2013-14 में सेब की फसल काफी हुई लेकिन हमें दिक्कत का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि वर्ष 2009-10 में हुआ था। वह खौफनाम याद है। लोगों को कई रातें अपनी गाड़ियों में ही सड़कों पर गुजारनी पड़ी थी। अब ऐसे हालत नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker: Now, the sitting of this House is adjourned till Wednesday, the 25th March, 2015 at 11.a.m.

Dated: 24th March, 2015. **Sunder Singh Verma**
Place: Shimla **Secretary.**